चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 30 मई– 05 जून 2016 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

किसान मंच की लखनऊ सभा में नीतीश कुमार की मुनादी

अब यूपी

फोटो-सुरेश वर्मा

प्रभात रंजन दीन

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अखिलेश सरकार को उत्तर प्रदेश में शराब पर रोक लगाने की चुनौती दी है. किसान मंच के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा नीतीश को बुला कर यूपी में भी शराबबंदी आंदोलन का बिगुल फूंके जाने का संदेश यही है कि शराबबंदी का मसला अब सामाजिक आंदोलन के रूप में देशव्यापी हो रहा है. लखनऊ स्थित रवींद्रालय प्रेक्षागृह और रवींद्रालय परिसर में खचाखच भरी भीड़ के बीच जब नीतीश कुमार ने कहा कि अखिलेश जी डरिए नहीं, यूपी में भी शराबबंदी लागू कीजिए, तो लोगों की हर्षध्वनि ने व्यापक सामाजिक आंदोलन की मुनादी दी. हॉल में पुरुषों के सीट घेर कर बैठने के कारण भारी संख्या में महिलाओं को कॉरिडोर, बरामदे और रवींद्रालय परिसर में इधर-उधर छाया तलाश कर बैठने को विवश होना पड़ा. इस पर तकरीबन सभी वक्ताओं ने खेद व्यक्त किया और कहा कि शराबबंदी का आंदोलन महिलाओं के कारण ही सफल हो रहा है, उनके लिए कुर्सी से लेकर हृदय तक में जगह देनी होगी. किसान मंच से जुड़ी महिला सदस्य देशभर से लखनऊ आई थीं, यहां तक कि रेल आरक्षण नहीं मिलने पर महाराष्ट्र किसान मंच की नेता कविता दमभरे कुछ अन्य महिला सदस्यों के साथ कार ड्राइव कर महाराष्ट्र से लखनऊ चली आईं. उनके इस साहस की नीतीश कुमार समेत सभी वक्ताओं ने सराहना की.

बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी लागू करने की किसान मंच की मांग पर उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों की महिलाओं के इस कदर भारी संख्या में लखनऊ पहुंचने का सामाजिक असर तो हुआ ही, इस आमद ने राजनीतिक दलों की बेचैनी भी खूब बढ़ा दी. खास तौर पर समाजवादी पार्टी में सुगबुगाहट और बौखलाहट कुछ अधिक ही रही. कार्यक्रम स्थल पर भी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (एलआईयू) के अधिकारी और कर्मचारी खासी संख्या में टोह लेते दिखते रहे . बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम में आने को लेकर सपा में सरगर्मी इतनी थी कि पार्टी ने पहले से ही कुर्मी मतदाताओं को प्रभावित करने की कवायद शुरू कर दी और इस बेचैनी का फायदा हाशिए पर जा चुके कांग्रेसी नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने उठा लिया. मुलायम ने बेनी को न केवल पार्टी में शामिल कराया बल्कि राज्यसभा तक पहुंचा दिया. राजनीतिक प्रेक्षक बेनी के इस फायदे को नीतीश की लखनऊ में धमक का प्रतिउत्पाद मानते हैं. उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने नीतीश कुमार को कुर्मी प्रभाव से जोड़ कर देखने की संकुचन-दृष्टि से काम लिया, जबकि अब नीतीश कुमार का व्यक्तित्व जाति, दल और सियासी केंचुए से बाहर निकल चुका है. किसान मंच के आयोजन में कई प्रमुख वक्ताओं ने भी यह बात कही. सपा के प्रवक्ता व अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी तो बौखलाहट में यहां तक बोल गए कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक शक्तियों को मजबूत कर रहे हैं. ऐसे कई हास्यास्पद कथन सपा प्रवक्ता के मुंह से निकले, मसलन, नीतीश अब ओवैसी और मोहन भागवत की श्रेणी में आ गए हैं, जो राज्य की जनता को गुमराह करने के लिए दौरा कर रहे हैं. राजेंद्र चौधरी ने फिर कहा कि नीतीश ने शराब पर प्रतिबंध की बात की, लेकिन विकास के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले. सपा प्रवक्ता ने बयान देने से पहले इतना भी होमवर्क नहीं किया था कि किसान मंच का कार्यक्रम शराबबंदी को लेकर ही केंद्रित था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस गैर राजनीतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होकर आए थे. कार्यक्रम के पहले राज्य और देशभर के अखबारों में किसान मंच के इस गैर राजनीतिक कार्यक्रम में खबरें विस्तार से प्रकाशित हुई थीं. चौधरी ने बयानोत्साह में यह भी कहा कि बिहार में आग लगी हुई है और वहां के नेता यूपी पर्यटन में व्यस्त हैं. बिहार में जंगलराज है और नीतीश शराब की चर्चा में लगे हुए हैं. इसी प्रसंग में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव के उस बयान को भी जोड़ कर देखा जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि शराबबंदी के बाद नीतीश कुमार को हाथ में कटोरा थाम कर घूमना पड़ेगा. रामगोपाल के उस बयान पर नीतीश कुमार ने चुटकी भी ली और कहा, रामगोपाल जी! हम कटोरा लेकर नहीं निकलने वाले हैं. शराबबंदी लागू करने का फैसला काफी सोच-समझकर लिया है. जनहित के काम कठिन तो होते हैं लेकिन शुरू कर दें तो कामयाबी मिलती है. देखा नहीं किस तरह केरल के चुनाव में शराबबंदी अहम मुद्दा बना. तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि के साथ-साथ अन्य दलों को भी शराबबंदी का आश्वासन देकर ही चुनाव में उतरना पड़ा. क्या ये सब कटोरा पकड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं? यह समय की मांग है, इसे समझिए नहीं तो देर हो जाएगी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में शराबबंदी सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन जैसा असर कर रही है. बिहार में सभी विधायकों ने शराब न पीने का संकल्प लिया है. बिहार के मुख्य सचिव से लेकर तमाम अधिकारी और कर्मचारी तक व डीजीपी से लेकर सभी अधिकारी और सिपाहियों तक ने यही संकल्प लिया है. थानों से भी अंडरटेकिंग ली गई है कि उनके क्षेत्रों में शराब का व्यापार कतई नहीं होगा. शराबबंदी का बिहार के समाज पर यह असर पड़ा कि बिहार के एक करोड़ 19 लाख स्कूली बच्चों ने अपने-अपने अभिभावकों से शराब न पीने का शपथ पत्र भरवाया.

> “लोहिया का नाम लेकर सरकार चलाते हैं तो लोहिया के कुछ काम भी कीजिए. उनके नाम पर यूपी में शराबबंदी ही लागू कर दीजिए. हम यहां किसी को परेशान करने नहीं आए हैं, हम तो यह कहने आए हैं कि जो हमने किया उसे आप भी करिए, यह समाज के भले के लिए जरूरी है”

नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश सरकार को यूपी में शराब पर पाबंदी लगाने के लिए कहा और यह भी आग्रह किया कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले इलाकों में पांच किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें न खुलने दी जाएं. नीतीश कुमार ने इसके लिए उत्तर प्रदेश आबकारी कानून के प्रावधानों का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि जहां दो प्रदेश या दो जिलों की सीमा मिलती है उसके पांच किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खुलेगी. नीतीश ने कहा कि इस प्रावधान को बिहार से सटे यूपी के जिलों में लागू कराने का अनुरोध करते हुए बिहार के मुख्य सचिव ने यूपी के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ. नीतीश बोले कि वे बिहार में शराबबंदी लागू कर रहे हैं और यूपी अपनी सीमा पर ज्यादा शराब बेच रहा है. हमनें उधर दुकानें बंद कीं तो यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब की और ज्यादा दुकानें खुल गईं. इस बारे में नीतीश ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब की बिक्री सीमित करने व निगरानी रखने का आग्रह किया था. लेकिन अखिलेश ने पत्र का जवाब देने का सामान्य शिष्टाचार भी नहीं निभाया. नीतीश ने कहा कि जवाब तो दूर पत्र की पावती (एकनोलेजमेंट) तक नहीं मिली.

बिहार में शराबबंदी कारगर तरीके से लागू करने में नीतीश सरकार को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, इसे सुनने के बाद राजनीति की दुनिया के कई वरिष्ठ व्यक्तित्वों ने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य से देखें तो नीतीश द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आकर दी गई शराबबंदी की चुनौती के न केवल सामाजिक अर्थ हैं बल्कि इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ भी हैं. नीतीश कुमार जब अखिलेश और रामगोपाल जैसे नेताओं को शराबबंदी का अर्थशास्त्र समझाते हैं तो उसके पीछे के राजनीतिक अर्थ-संकेत समझ में आते हैं. नीतीश ने जब अखिलेश को साहस देते हुए कहा कि यूपी में भी शराबबंदी लागू करिए तो उन्हें उसका अर्थशास्त्र भी बताया. नीतीश ने कहा कि 16 हज़ार करोड़ के राजस्व के लिए जनता की गाढ़ी कमाई के 60 हज़ार करोड़ रुपये बर्बाद मत कीजिए. शराबबंदी नुकसान का नहीं, दूरगामी फायदे का सौदा है. यूपी में 16 से 18 हज़ार करोड़ रुपये का राजस्व कमाने के लिए लोगों को 60 हज़ार करोड़ से अधिक की शराब पिलाई जा रही है. लोग शराब पीना बंद कर दें तो जनता की गाढ़ी कमाई का 60 हज़ार करोड़ रुपया बाजार में लगेगा और अच्छे कामों पर खर्च होगा. उससे कर राजस्व तो बढ़ेगा ही, सामाजिक फायदे भी सामने दिखेंगे, घरेलू हिंसा में कमी आएगी, गांवों में शांति रहेगी, महिलाओं का जीवन और परिवार के अन्य सदस्यों का जीवन सुखमय होगा, सड़क हादसे कम होंगे और अपराध की घटनाओं में कमी आएगी. शराबबंदी से 60 हज़ार करोड़ रुपया बाजार में ही आएगा और उसके टैक्स से राजस्व की कमी पूरी हो जाएगी. नीतीश ने कहा कि शराब का धंधा सामाजिक बुराई है, यह नैतिक व्यापार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट भी यह कह चुकी है कि शराब पीना और इसका व्यापार करना मौलिक अधिकार के तहत नहीं आता.

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार के समक्ष नैतिकता की कसौटी रखते हुए नीतीश ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया जैसे महापुरुषों का केवल नाम ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनके विचारों के अनुरूप काम भी करना चाहिए. नीतीश बोले, हमारा मजाक उड़ाकर कितने दिन काम चलाइयेगा. लोहिया का नाम लेकर सरकार चलाते हैं, लोहिया का नाम लेते हैं तो लोहिया के कुछ काम भी कीजिए. उनके नाम पर शराबबंदी ही लागू कर दीजिए. हम यहां किसी को परेशान करने या तंग करने नहीं आए हैं, हम तो यह कहने आए हैं कि जो हमने किया उसे आप भी करिए, क्योंकि यह समाज के भले के लिए जरूरी है. आमदनी की चिंता मत करिए, यूपी में भी शराबबंदी लागू कीजिए. इससे सरकारी खजाने को जितना घाटा होगा उससे ज्यादा लाभ आपको मिलेगा. नीतीश ने संकेतों से यह जाहिर किया कि शराबबंदी के सामाजिक के साथ-साथ राजनीतिक फायदे क्या हैं. उन्होंने इसके लिए

(शेष पृष्ठ 2 पर)

किसान मंच के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान (बाएं से) वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व सांसद संतोष भारतीय, जदयू नेता व सांसद केसी त्यागी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह

किसान मंच की लखनऊ सभा में नीतीश कुमार की मुनादी

अब यूपी

महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक काम किया है. महिलाओं को उन्होंने घर की चारदीवारी से निकाल कर राजनीति की अगली कतार में खड़ा कर दिया है. नीतीश जी शराबबंदी आंदोलन के जरिए महिलाओं को समाज परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई की अगली कतार में खड़ा करना चाहते हैं इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं : *संतोष भारतीय*

पृष्ठ 1 का शेष

अखिलेश का साहस बढ़ाने के भाव से कहा कि साहस तो करिए, बिहार में भी जब शराबबंदी लागू की गई थी, तो पीने वालों से लेकर धंधा करने वालों और उन्हें संरक्षण देने वालों को कुछ दिन परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद सब शांत हो गए. नीतीश ने शराबबंदी के बाद के बिहार और आज के यूपी के समाज की तुलना करने की भी चुनौती दी और कहा कि तुलना करा लीजिए, जांच दल भेज दीजिए. शराबबंदी के बाद से बिहार के लोगों को जो खुशी मिल रही है, वह सामने है. सड़क दुर्घटनाओं से लेकर अपराध तक में कमी आई है. नीतीश ने कहा कि शराब पीकर घरों में विवाद, झगड़ा और घरेलू हिंसा करने वाले पति अब बदली हुई स्थिति में समय पर घर पहुंचते हैं, परिवार के साथ रहते हैं और खाना बनाने में पत्नी का हाथ भी बंटाते हैं. नीतीश बोले कि बिहार में शराबबंदी कारगर करने में महिलाओं की बड़ी भूमिका है. नीतीश ने कहा कि 1915 के बिहार एक्साइज एक्ट (आबकारी कानून) में संशोधन कर अवैध शराब बनाने और बेचने वालों को फांसी और शराब पीकर उत्पात मचाने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. सरकार की तरफ से बिहार की महिलाओं से कहा गया है कि कहीं भी चोरी-छिपे अवैध शराब की भट्ठी चलती देखें तो उसे तोड़ दें, सरकारी तंत्र उनका साथ देगा, क्योंकि भावी पीढ़ी की खुशहाली के लिए शराबबंदी जरूरी है. अब कोई भी राज्य इससे बच नहीं सकता. इसलिए सबको समय रहते चेत जाना चाहिए. नीतीश ने कहा कि शराबबंदी को लेकर जैसा समर्थन उन्हें उनके राज्य में मिला, वैसा ही जन समर्थन उन्हें उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी मिल रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि देश के अन्य राज्यों में भी इस सामाजिक आंदोलन को व्यापक परिणामकारी जन समर्थन प्राप्त होगा.

देश के वरिष्ठ पत्रकार और चौथी दुनिया के प्रधान संपादक व पूर्व सांसद संतोष भारतीय की अपील पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भरोसा दिया कि शराबबंदी आंदोलन से लेकर किसानों के मसले और खनन व भू-माफियाओं के खिलाफ चलने वाले संघर्ष में वे हर कदम साथ देंगे. संतोष भारतीय ने कहा भी कि मैं यहां पत्रकार के नाते या चौथी दुनिया का संपादक होने के नाते नहीं, बल्कि किसान परिवार का सदस्य होने के नाते निवेदन करने आया हूं. क्योंकि नीतीश जी से किसानों की क्या आशाएं हैं उसे नीतीश जी को जानना जरूरी है. महिलाओं के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है. महिलाओं को उन्होंने घर की चारदीवारी से निकाल कर राजनीति की अगली कतार में खड़ा कर दिया है. इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं. संतोष भारतीय ने कहा कि नीतीश कुमार का शराबबंदी का आंदोलन सिर्फ शराबबंदी का आंदोलन नहीं है, गांधी जी का शराबबंदी का आंदोलन केवल शराबबंदी के आंदोलन तक सीमित नहीं था. गांधी ने उस आंदोलन के जरिए महिलाओं को आजादी की लड़ाई के साथ जोड़ दिया. उसी तरह नीतीश जी शराबबंदी आंदोलन के जरिए महिलाओं को समाज परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई की अगली कतार में खड़ा करना चाहते हैं. महिलाएं अगर विकास के काम पर नजर रखेंगी तो सटीक और बेहतर परिणाम सामने आएंगे. नीतीश जी से बात करते हुए मुझे यह झलक भी मिली है कि बिहार में विकास के काम पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी महिलाओं को सौंपी जा सकती है. यह कमाल का काम बिहार करने जा रहा है. यह काम सम्पूर्ण भारतवर्ष में होना चाहिए.

संतोष भारतीय ने कहा कि देश के तमाम राजनीतिक नेताओं पर नजर डालें, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है समाज परिवर्तन की, उनमें ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो हर आदमी से संवाद कर सके, हर आदमी से लोगों की समस्याओं पर चर्चा कर सके. नीतीश कुमार अकेले ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जो देश समाज के विकास और एकजुटता के लिए मुलायम से भी बात कर सकते हैं, लालू यादव से भी बात कर सकते हैं, मायावती से भी बात कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी से भी बात कर सकते हैं. किन सवाल पर... जो देश के सवाल हैं, देश के सवाल क्या हैं... देश का पहला सवाल शराबबंदी है और दूसरे सवाल किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा दिलाना है. किसान के बेटों को नौकरी दिलाना है, गांवों में रोजगार के अवसर सृजित करना है. ये सवाल नीतीश के समक्ष राष्ट्रीय योजना के सदृश हैं. इस योजना पर कोई बात कर सकता है तो अकेले नीतीश कुमार कर सकते हैं, यह हमें दिखाई दे रहा है. नीतीश कुमार में लोगों को वीपी सिंह की छवि दिखाई देती है. जैसा शेखर दीक्षित ने कहा, सही कहा कि वीपी सिंह की कोमलता, उनकी लगनशीलता, उनकी कल्पनाशीलता नीतीश कुमार में नजर आती है और लोगों के लिए मरना दिखाई देता है. उसे हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं. वीपी सिंह अपने आखिरी दिनों में भी अपना खून डायलिसिस कराते थे और समाज के बीच निकल पड़ते थे. नीतीश कुमार के सारे कार्यक्रम लोगों के लिए होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, लोगों के लिए वे घूम रहे हैं. कोई दूसरा नेता ऐसा नजर नहीं आता जो इस तरह का हो. देश के आम लोगों को बहुत धोखे मिले हैं. उनका भरोसा नीतीश कुमार के प्रति फिर से जागा है. ऐसे में नीतीश कुमार को यह वादा करना ही चाहिए कि सामाजिक न्याय, गैर बराबरी, किसानों की लड़ाई और शराबबंदी के जरिए महिलाओं को राजनीति में लाने का अभियान पूर्णाहुति तक जारी रहेगा. नीतीश कुमार अब पार्टी की सीमाओं से काफी विस्तार ले चुके हैं, अब वे देशभर के लोगों, महिलाओं, किसानों और युवकों के बीच जा चुके हैं. नीतीश कुमार अब जहां जा रहे हैं, वहां आशा की लौ जाग रही है. उनकी आंखों में अब आंसू न आए, यह वादा उन्हें मिलना ही चाहिए.

यूपी में शराबबंदी लागू करने और उस लड़ाई के साथ भूमाफियाओं के खिलाफ संघर्ष को जोड़ने की मांग पर किसान मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जदयू के वरिष्ठ नेता व सांसद केसी त्यागी ने बिहार में शराबबंदी लागू करने के लिए नीतीश को युग पुरुष बताया और कहा कि महात्मा गांधी से लेकर देश में जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वे विनोबा भावे हों या जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई हों या चौधरी चरण सिंह या कर्पूरी ठाकुर सब लोगों का यही सपना था कि देश शराब से पूर्ण रूप से मुक्त हो, समाज में वैमनष्यता न हो और सबको सबका अधिकार मिले. आज के समय में उन नेताओं का असली वंशज या उत्तराधिकारी होने लायक अकेले नीतीश कुमार हैं. यही वजह है कि उन्हें देशभर का प्रेम और समर्थन प्राप्त हो रहा है. उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों के विभिन्न महिला संगठन और महिला मोर्चा की सदस्याएं नीतीश कुमार को सम्मानित कर रही हैं. इसकी शुरुआत झारखंड के धनबाद से हुई. उसके बाद किसान मंच द्वारा लखनऊ के रवींद्रालय में यह अभूतपूर्व स्वागत किया जा रहा है. इसी तरह के कई कार्यक्रम राजस्थान, उत्तराखंड और ओड़ीशा व कुछ अन्य राज्यों में भी होने जा रहे हैं. जदयू नेता ने कहा कि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी शराबबंदी को लेकर व्यापक मुहिम चलाए जाने की तैयारी है. 16 कलाकारों का एक दल उत्तर प्रदेश में जगह-जगह जाकर नुक्कड़ नाटक और अन्य माध्यमों के जरिए लोगों को शराब के प्रति जागरूक करेगा. त्यागी ने कहा कि शराबबंदी के लिए आंदोलन के साथ-साथ यूपी में किसानों को उनकी फसलों की कीमत, किसानों की आत्महत्याएं, भुखमरी, खनन और भू-माफियाओं के खिलाफ किसान मंच के अभियान को भी तेज किया जाएगा.

महिलाओं की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में कुर्सियों पर काबिज पुरुषों पर कटाक्ष करते हुए केसी त्यागी ने भी कहा कि मूलतः यह कार्यक्रम महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए आयोजित है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज का अगर असली रूप देखना हो तो इस कार्यक्रम में देखने को मिलता है. महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया वे अधिकांशतः बाहर बैठी हैं और जिनके विरुद्ध आयोजित किया गया, वह सब अंदर बैठे हैं. शराब पुरुष ही अधिक पीते हैं तो शराबबंदी का आंदोलन महिलाओं का ही है. किसान मंच की सराहना करते हुए त्यागी ने कहा कि वीपी सिंह की अगुवाई वाले किसान मंच ने दादरी में कौड़ियों के मोल रिलाएंस को दी गई किसानों की जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ कानूनी से लेकर सामाजिक लड़ाई तक लड़ी और रिलाएंस को उस मामले में अपने पैर पीछे खींच लेने को विवश होना पड़ा. वीपी सिंह जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे उस समय नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के सदस्य थे. उस समय वे और संतोष भारतीय दोनों सांसद थे. जयप्रकाश आंदोलन में भी सब साथ रहे और सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय के संघर्षों में साक्षी और साझीदार दोनों रहे. त्यागी ने बिहार में शराबबंदी को भी वैसा ही जन आंदोलन बताया, जिसकी पराकाष्ठा यह है कि कोई पति शराब पीता हुआ पाया जाता है तो उसकी पत्नी थाने में सूचना देकर अपने पति को गिरफ्तार करा देती है. त्यागी ने गुजरात के कुछ व्यापारियों के पटना के होटल में शराब पीते पकड़े जाने का वाकया सुनाया और कहा कि गिरफ्तारी की खबर गुजरात में इस तरह प्रकाशित की गई कि जैसे नीतीश ने राजनीतिक वैमनष्यता में गुजरात के व्यापारियों को गिरफ्तार कराया हो. असलियत ऐसे उजागर हुई कि व्यापारी की पत्नी ने ही कहा कि नीतीश कुमार को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मेरे शराबी पति को पकड़ा. देशभर में बन रहे ऐसे प्रभाव के कारण ही पार्टियों को और राज्य सरकारों को परेशानी हो रही है, लेकिन वे निश्चिंत रहें, हम उनकी रोजी-रोटी पर लात मारने नहीं आए हैं. हम तो केवल यह समझाने आए हैं कि शराब एक सामाजिक बुराई है. शराब का धंधा करने वालों द्वारा नीतीश को काला झंडा दिखाने की चर्चा का हवाला देते हुए त्यागी ने कहा, मैंने सुना कि शराब का धंधा करने वाले नीतीश को काला झंडा दिखाने की तैयारी कर रहे थे. काले झंडे तो गांधी जी को भी दिखे, नेहरू को भी दिखे, जयप्रकाश को भी दिखे, वीपी सिंह को भी दिखे. ऐसे महापुरुषों के लिए तो काले झंडे नजर का टीका हैं, यह तो नीतीश कुमार जी के लिए अत्यंत शुभ संकेत हैं. त्यागी ने कहा कि सत्ता किसी की भी हो, नीतीश ने जो आग लगाई है वह पूरे देश में फैलेगी और वह दिन आने वाला है (शेष पृष्ठ 3 पर)

किसान मंच के लखनऊ आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (बोलते हुए), मंच पर बैठे वरिष्ठ पत्रकार व पूर्व सांसद संतोष भारतीय, जदयू नेता व सांसद केसी त्यागी और किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह.

भाजपा शासित राज्यों में शराबबंदी लागू कराएं मोदी

नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे भाजपा शासित राज्यों में शराबबंदी लागू कराएं. नीतीश ने तर्क दिया कि गुजरात राज्य में उसके स्थापना काल से ही शराबबंदी लागू है. नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वहां शराबबंदी समाप्त नहीं की, इसका मतलब है कि मोदी भी शराबबंदी के पक्षधर हैं. तब तो उन्हें भाजपा शासित राज्यों में भी शराबबंदी फौरन लागू कराना चाहिए.

किसान मंच के नेताओं को दी गई जान से मारने की धमकी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिल कर उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तर्ज पर शराबबंदी का अभियान चलाने की घोषणा से परेशान तत्वों ने किसान मंच के नेताओं को फोन पर धमकियां दीं और आयोजन से अलग रहने को कहा. फोन पर धमकी देने वालों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी गालियां दी और किसान मंच के नेता को गोली मारने की धमकी दी. किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा कि इस तरह की धमकियों के एक दर्जन से अधिक मामले लखनऊ, सरोजनी नगर, बाराबंकी समेत कई जिलों और शहरों में दर्ज कराए गए हैं. लखनऊ पुलिस ने ऐसे कई फोनों की सर्विलांस में पाया कि उनमें से कुछ भाजपा नेताओं के नम्बर थे. मामले की तफ्तीश चल रही है. कई धमकीबाजों ने इस अभियान को न चलाने की चेतावनी देते हुए अंजाम भुगत लेने की बात कही थी. पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों को जल्दी ही गिरफ्तार भी किया जा सकता है.

हॉल में जगह नहीं मिली तो रवींद्रालय प्रेक्षागृह के कॉरिडोर में बैठ गईं महिलाएं.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 13
30 मई- 05 जून 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोनः 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

किसान मंच की लखनऊ सभा में नीतीश कुमार की मुनादी

अब यूपी

पृष्ठ 2 का शेष

जब वोट उसे ही मिलेगा जो शराब पर रोक लगाने का ठोस वादा करके चुनाव मैदान में उतरेगा.

किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह ने हॉल की कुर्सियों पर काबिज पुरुषों पर प्रहार से ही अपनी बात शुरू की. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बिहार में शराबबंदी लागू करने वाले नीतीश कुमार जी के सम्मान के लिए महिलाओं द्वारा आयोजित है. लेकिन देखिए महिलाओं की क्या स्थिति है, कुर्सी पर पुरुषों ने कब्जा कर रखा है. महिलाएं गैलरी में, तो बाहर पेड़ के नीचे बैठी हैं. लड़ाई वो लड़ती हैं, शराब के खिलाफ मुहिम वो चलाएंगी, आपको उनके साथ चलना था, लेकिन कहीं न कहीं आप लोग जो घर में करते हैं, वही इस कार्यक्रम में भी कर दिखाया. विनोद सिंह ने आगाह किया कि आगे से ऐसा मत करें. अगर महिलाओं को सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से आपकी यह मुहिम आगे बढ़ेगी. जब महिलाएं आगे निकलेंगी, महिला मुहिम चलाएंगी, तो आपकी मुहिम शराब के साथ किसानों के सवालों को लेकर आगे बढ़ेगी. तब चलेगा खनन माफिया के खिलाफ संघर्ष, तब चलेगा कारपोरेट घरानों के खिलाफ संघर्ष. लड़ाई को धार लाने के लिए महिलाओं को आगे करना होगा. जिस तरह राजनीतिक दल दिखाते हैं, उस तरह काम नहीं करना है. 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को बैठने के लिए भागीदारी क्यों नहीं दिखाते. किसान मंच के कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों के जुटने से उत्साहित किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लखनऊ में ऐसा कार्यक्रम करना पैसे का खेल होता है. लेकिन ऐसी अंधी रेस के दौर में किसान मंच का कार्यक्रम मिसाल है. लोग अपने साधनों से आए. महिलाएं अपने साधनों से आईं. विनोद सिंह ने ऐलान किया कि किसान मंच शराबबंदी के पक्ष में और खनन व भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान को पूरे उत्तर प्रदेश में और देशभर में चलाएगा. सितंबर में देवरिया से दादरी तक की यात्रा निकाली जाएगी. छह महीने के अंदर पूरी ताकत के साथ किसान मंच उभरेगा और आंदोलन शक्तिशाली बनेगा. विनोद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार में वीपी सिंह का चेहरा दिखाई देता है. सामाजिक न्याय और ईमानदारी की छवि दिखाई देती है. देश में एक ही चेहरा है नीतीश कुमार का जिसे किसानों का चेहरा बनना है, दबे कुचलों का चेहरा बनना है, वीपी सिंह के सिद्धांतों पर चलने वाले नीतीश कुमार ने शराब बंद करने का जोखिम उठाया. अब यूपी में भी शराब पर पूर्ण पाबंदी लगनी चाहिए. यूपी में शराब का धंधा एक पौंटी परिवार के हाथों में केंद्रित है. विनोद सिंह ने कहा कि अब यह ज्वार बिहार से उठा है तो यूपी होते हुए दिल्ली तक जाएगा.

महाराष्ट्र से 12 सौ किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर लखनऊ पहुंचीं किसान मंच की नेता कविता दमभरे ने महिलाओं का आह्वान किया कि वे जोश के साथ तब तक आंदोलन चलाएं जब तक कि पूरे देश में शराबबंदी लागू न हो जाए. कविता ने कहा कि महाराष्ट्र के कई जिलों में शराबबंदी का आंदोलन चल रहा है. वर्धा जिले से ही शराबबंदी का आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी के आदर्श को केवल वर्धा तक ही सीमित रख दिया गया. लेकिन बाद में महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली में भी शराबबंदी का आंदोलन सफल हुआ. चंद्रपुर जिले में शराबबंदी के आंदोलन में कविता भी शरीक रहीं, उस आंदोलन के समक्ष महाराष्ट्र सरकार को झुकना पड़ा. चंद्रपुर में अब शराब पूर्ण रूप से बंद है. कविता बोलीं कि दिन भर खेती करने वाली, रोजगार करने वाली महिलाएं भी आंदोलन में शरीक हैं, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है. पूरे देश की महिलाएं नीतीश कुमार के साथ हैं. क्योंकि शराब की त्रासदी का शिकार महिलाएं ही होती हैं. महिलाओं को नीतीश कुमार का संरक्षण चाहिए, देशभर की महिलाएं नीतीश कुमार की तरफ उम्मीद से देख रही हैं. बनारस से आईं डॉ. रितु गर्ग ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आह्वान करते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने बिहार की महिलाओं को शराब की त्रासदी से मुक्त कराया है, उसी तरह वे उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं का साथ दें और यही आंदोलन देशभर में फैले. कार्यक्रम का संचालन किसान मंच उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने किया. पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के काफी करीबी रहे शेखर ने भी कई बार वीपी सिंह को स्मरण किया और कहा कि नीतीश कुमार जी के साथ वे जब गाड़ी से आ रहे थे तो उनकी बातें सुन कर उन्हें वीपी की याद आ रही थी. शेखर गाड़ी ड्राइवर करते थे और वीपी बगल में बैठे हुए देश समाज के बारे में बताते रहते थे.

किसान मंच की यूपी प्रभारी रिचा चतुर्वेदी और महाराष्ट्र प्रभारी कविता दमभरे के नेतृत्व में महिलाओं ने स्मृति चिन्ह देकर नीतीश कुमार को सम्मानित किया. इसके पहले किसान मंच के कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में अमौसी एयरपोर्ट पहुंच कर वहां नीतीश कुमार का स्वागत किया. वीवीआईपी गेस्ट हाउस में भी कई महिला प्रतिनिधिमंडल से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई. बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के सिलसिले में आईएफडब्लूजे के प्रतिनिधिमंडल ने भी नीतीश से मिलकर ज्ञापन सौंपा. नीतीश लखनऊ के अम्बेडकर महासभा भी गए और वहां डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अस्थिकलश पर पुष्पांजलि अर्पित की. नीतीश को वहां भी स्मृतिचिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया.

(सपा की बेचैनी, बेनी को फायदा पृष्ठ 4 पर)

सभी फोटो : सुरेश वर्मा
किसान मंच, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शेखर दीक्षित और उनके दल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया.

काले झंडे दिखाए नहीं, पर अखबारों में छप जरूर गए

यूपी में भी शराबबंदी लागू करने की मांग पर लखनऊ में आयोजित किसान मंच के कार्यक्रम में शरीक होने वाले नीतीश कुमार को शराब व्यापारियों द्वारा काला झंडा दिखाने की तैयारी की चर्चा थी. नीतीश के आने से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक काला झंडा तो कहीं नहीं दिखा, पर चर्चा जरूर होती रही. यह चर्चा नीतीश के कानों तक भी पहुंची. उन्होंने भी कहा कि सुना तो, लेकिन कहीं देखा नहीं. लेकिन अगले दिन विडंबना कई प्रमुख अखबारों में दिखी. शराब का धंधा करने वाले लोगों द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाने की खबरें प्रमुखता से छपीं. एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार समेत कई अन्य स्वनामधन्य अखबारों में ये खबरें विडंबना की तरह चिपकी हुई मिलीं और शराब माफियाओं की असली औकात का एक और आयाम उजागर कर गईं.

एलआईयू के एक अधिकारी ने कहा कि शराब एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने नीतीश को काला झंडा दिखाने की तैयारियों का हौव्वा बनाया था. कानपुर रोड के पास उन लोगों ने ऐसी जगह पर नारे लगाने और काला झंडा दिखाने की औपचारिकता की जो नीतीश कुमार के रूट में नहीं था. अखबारों में उसी प्रहसन को खबर का रंग देकर छपवा लिया गया.

शराब लॉबी की ताकत जानते हैं नीतीश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराब लॉबी की ताकत वे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वे लॉबी के आगे झुकना नहीं जानते. नीतीश ने कहा कि लखनऊ आने पर उन्हें कुछ लोगों ने जानकारी दी कि शराब व्यवसाय से जुड़े कुछ लोग काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे हैं. नीतीश ने कहा कि पता नहीं काला झंडा दिखाया या नहीं. बिहार में तो शराब का धंधा करने वालों ने धरना तक दे दिया था. पहले तो दबाव बनाने का काम किया, लेकिन झुकने का सवाल ही कहां था, तब खुद झुके और कहा कि शराब की दुकान बंद हो जाएगी तो हम बेरोजगार हो जाएंगे. हमने उनसे कहा कि शराब का काम बंद करके दूध का व्यवसाय शुरू कर दें. धंधा का धंधा और स्वास्थ्य का स्वास्थ्य. हमें अच्छी तरह मालूम है कि शराब लॉबी कितनी मजबूत है और वह क्या-क्या करा सकती है. हम तो अब ताल ठोक कर मैदान में उतर ही चुके हैं.

शराबखोरी के खिलाफ गांधीगीरी

शराबबंदी को लेकर लखनऊ में नीतीश कुमार की आमद का कुछ ऐसा असर हुआ कि कुछ अन्य सामाजिक संस्थाएं भी शराब के खिलाफ सड़क पर उतर पड़ीं. शराबखोरी के खिलाफ समाजसेवियों ने गांधीगीरी शुरू की. लखनऊ के मुंशीपुलिया के पास ठेके पर शराब पीने वालों को माला पहनाकर समाजसेवियों ने उन्हें शराब नहीं पीने की नसीहत दी. अभियान की शुरुआत उसी दिन देर शाम मुंशीपुलिया चौराहा स्थित आरोही ऑर्केड से हुई, जिस दिन नीतीश किसान मंच के कार्यक्रम में शरीक होने लखनऊ आए थे. वहां एक शराब की दुकान के बाहर शराबियों का झुंड शराब पीता दिखा. अभियान में शामिल लोगों के हाथ में फूलों की माला देखते ही शराबी वहां से भाग निकले. पुलिस ने कुछ को पकड़ लिया और संस्था के लोगों ने माला पहनाकर सार्वजनिक स्थल पर शराब न पीने की उन्हें कसम दिलाई.

समाजसेवियों ने खुलेआम शराब पी रहे पॉलिटेक्निक छात्र को भी माला पहनाई. माला पहनाने से वह नाराज हो गया. उसने समाजसेवियों के साथ-साथ वहां मौजूद पुलिस वालों को भी हड़काने की कोशिश की. लेकिन पुलिस ने जब उसका चालान काटा तो फिर उसके होश फाख्ता हो गए. पार्वती पैलेस में एक दुकान के अंदर कई लोग शराब पीते दिखे, जिसका स्थानीय व्यापारियों ने विरोध किया. इसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप पर वहां शराबखोरी रुकी.

आजम ने नीतीश को नसीहत दी

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नसीहत देने से बाज नहीं आए और समाजवादी पार्टी का समर्थन करने की उनसे मांग भी कर डाली. उन्होंने मुस्लिम वोटों के बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार को नसीहत दी. आजम खान ने कहा कि नीतीश कुमार मुस्लिम वोटों को बांटने का काम न करें. ऐसा करने से विरोधियों को लाभ मिलेगा. अगर उन्हें अल्पसंख्यकों का भला करना है, तो साथ मिलकर काम करें. आजम ने कहा कि अगर नीतीश कुमार मुसलमानों के शुभचिंतक हैं, तो सपा के समर्थन की घोषणा करें, जिससे विधानसभा चुनाव के बाद सपा की सरकार बनने में आसानी हो.

नीतीश का सामाजिक बनाम राजनीतिक अभियान

सरोज सिंह

जनता दल (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संघ-मुक्त भारत और शराब-मुक्त समाज के आह्वान के साथ अपना मिशन 2019 आरंभ कर दिया है. मिशन 2019 के पहले अग्निपरीक्षा उत्तर प्रदेश में होनी है, लिहाजा उन्होंने अपना पहला पड़ाव देश के सबसे बड़े राज्य को बनाया है. नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के पिंडरा में अपने मिशन की शुरुआत की. इसके बाद नीतीश लखनऊ पहुंचे. 12 मई को पिंडरा में और 15 मई को लखनऊ में नीतीश ने बिगुल फूंका. इस अभियान को लेकर कुछ खास बातें उभर कर सामने आई हैं जिसे जदयू सुप्रीमो की भावी राजनीति के संकेत के रूप में देखा जा सकता है. साफ है कि नीतीश कुमार के शराब मुक्त समाज के नारे को व्यापक समर्थन मिलता दिख रहा है. महिलाओं की सक्रियता बढ़ने से यह अभियान गति पकड़ रहा है. समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को खुलकर ललकारने से नीतीश कुमार अब तक बचते रहे, लेकिन लखनऊ में शराबबंदी को लेकर उन्होंने सपा सरकार के समक्ष चुनौतियां उछालीं. इन सब गतिविधियों के बीच कांग्रेस को लेकर नीतीश का रुख हिन्दीपट्टी में नए राजनीतिक समीकरण की उम्मीदों को जन्म दे रहा है. उधर, बिहार में महागठबंधन के सबसे बड़े घटक राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान भी कम महत्व के नहीं माने जा रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के दो कार्यक्रमों में से एक राजनीतिक था तो दूसरा बिल्कुल गैर राजनीतिक. वाराणसी के राजनीतिक आयोजन में उन्होंने मुख्यतः नरेंद्र मोदी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को निशाने पर लिया और गत संसदीय चुनावों के दौरान देश से किए गए उनके वायदों को लेकर उनकी नीयत पर कई सवाल खड़े किए. भाजपा पर हमले के बाद उन्होंने शराबबंदी का मसला उठाया. बिहार में शराबबंदी के मिल रहे सकारात्मक नतीजों का उन्होंने जिक्र किया. उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के अभियान को लेकर कुछ सवाल नए सिरे से उठ रहे हैं. चौधरी अजित सिंह के राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) से पहले तो तालमेल की बात चली, फिर जदयू में उसके विलय की चर्चा चली. लेकिन यह धरातल पर नहीं उतरा. चौधरी अजित सिंह की कुछ स्वाभाविक शर्तें होती हैं, जो सब जानते हैं, लिहाजा तालमेल क्यों नहीं हुआ यह समझ में आता है. हालांकि नीतीश कुमार कहते हैं कि चौधरी का दरवाजा अब भी खुला है. इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सक्रिय एक क्षेत्रीय पार्टी से भी चुनावी तालमेल की चर्चा है. लेकिन जमीन पर अभी कहीं नहीं दिख रहा. नीतीश कुमार ने पिंडरा की सभा में पूर्वी उत्तर प्रदेश की 127 विधानसभा सीटों की खासतौर पर चर्चा की और पूर्वांचल को लेकर तैयारियों का संकेत दिया. उधर, झारखंड की हालत से दल में संतोष है. धनबाद में शराबबंदी अभियान को लेकर आयोजित एक सभा में नीतीश कुमार के साथ मंच पर झारखंड विकास मोर्चा (झविमो) के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे. मरांडी की मौजूदगी जदयू के साथ उनकी नजदीकियां जाहिर करती हैं और भविष्य में राजनीतिक साझीदार बनने के संकेत देती हैं. नीतीश कुमार के मिशन-2019 व मिशन उत्तर प्रदेश का राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया है. उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी अपने मुख्यमंत्री में पीएम मैटीरियल पाया है.

बनारस की सभा में नीतीश कुमार...

लेकिन पुराने समाजवादी और राजद के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार के इस अभियान को लेकर दो टूक बातें की हैं. उन्होंने नीतीश कुमार को नसीहत दी है कि वे बिहार पर ध्यान दें, यहां की स्थिति बिगड़ रही है. चूंकि स्टीयरिंग सीट पर नीतीश कुमार ही हैं तो सवाल भी उन्हीं से होना है और जवाब भी उन्हीं को देना है. इसके कुछ दिन बाद रघुवंश बाबू का दूसरा बयान आया कि नीतीश कुमार के ऐसे राजनीतिक अभियान से देश की सेकुलर राजनीति को नुकसान होगा. कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि महागठबंधन तो है ही नहीं, कुछ नेता आपस में मिल गए हैं. रघुवंश बाबू के इन बयानों पर नीतीश कुमार और उनके खास नेताओं ने कोई टिप्पणी नहीं की है. उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसे रघुवंश बाबू की निजी राय कहा. राजद सुप्रीमो इस पर खामोश हैं. महागठबंधन में शरीक कांग्रेस नीतीश में पीएम मैटीरियल नहीं देखती. कांग्रेस गांधी परिवार को छोड़ कर किसी को बतौर नेता पेश नहीं कर सकती. गांधी परिवार की सारी उम्मीदें राहुल गांधी पर टिकी हैं और राहुल अधर में टंगे हैं. ■

सपा की बेचैनी, बेनी को फायदा

रामगोपाल-आजम की नाराजगी दरकिनार कर मुलायम ने अमर सिंह को दिया राज्यसभा का पास

राज्यपाल के विरोध को ठेंगा दिखाकर सपा ने विवादास्पद बिल्डर संजय सेठ को भेजा राज्यसभा

प्रभात रंजन दीन

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश में दो कार्यक्रमों की सुगबुगाहट से ही समाजवादी पार्टी इतनी सक्रिय हो गई कि आनन-फानन कुर्मी वोट मैनेज करने की कवायद होने लगी और मुलायम को बेनी प्रसाद वर्मा याद आने लगे. पार्टी ने ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मीडिया के सामने बेनी को पेश कर दिया. बेनी को सपा में शरीक कराया और अगले ही दिन राज्यसभा भेजे जाने वाले नेताओं की सूची जारी हो गई जिसमें बेनी का नाम चस्पा हो गया. बेनी के साथ-साथ अमर सिंह भी राज्यसभा के लिए सपा की पसंद बने, जिसकी संभावना पहले से थी. संभावना में एक चैनल के मालिक का नाम पहले से चल रहा था, लेकिन लिस्ट जारी होते ही वह चर्चा थम गई. इसी धुप्पल में समाजवादी पार्टी ने उस विवादास्पद बिल्डर संजय सेठ को भी राज्यसभा भेजने का फैसला संलग्न कर लिया, जिसके विधान परिषद भेजने पर राज्यपाल राम नाईक ने कानूनी आपत्ति जताई थी और राज्य सरकार राज्यपाल के विरोध का कोई जवाब नहीं दे पाई थी. इसके बाद संजय सेठ के ठिकानों पर आयकर और प्रवर्तन निदेशालय के छापे भी सुर्खियों में रहे. इन छापों के बाद इटावा में संजय सेठ द्वारा मुलायम को भेंट की गई आलीशान कोठी भी सुर्खियों में रही. एवजिया पुरस्कार में संजय सेठ को राज्यसभा की सीट मिल गई. कानून अपनी जगह झेंपता रहा. सपा की तरफ से राज्यसभा के लिए चुने गए नामों में बेनी प्रसाद वर्मा, अमर सिंह, सुखराम यादव, रेवती रमण सिंह, विशम्भर प्रसाद निषाद, अरविंद सिंह और संजय सेठ शामिल हैं. सपा ने विधान परिषद के प्रत्याशियों के नाम भी साथ-साथ घोषित किए, जिनमें मुलायम के प्रिय सेवक रहे जगजीवन प्रसाद भी शामिल हैं. जगजीवन के अलावा बलराम यादव, शतरुद्र प्रकाश, यशवंत सिंह, बुक्कल नवाब, राम सुन्दर दास निषाद और गोंडा के रणविजय सिंह के नाम भी शामिल हैं.

राज्यसभा की लिस्ट फाइनल करने में सपा नेतृत्व ने राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव और अखिलेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खान की नाराजगी का कतई ध्यान नहीं रखा. इससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि आने वाले समय में खास तौर पर विधानसभा चुनाव के समय रामगोपाल और आजम खान की क्या वकत रहने वाली है. रामगोपाल और आजम दोनों ने ही अपने-अपने अंदाज में पार्टी नेतृत्व का विरोध किया, लेकिन मुलायम पर इस विरोध का कोई असर नहीं पड़ा. बेनी और अमर को राज्यसभा भेजने पर मुलायम अड़िग थे और वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव उनका साथ दे रहे थे. रामगोपाल और आजम के कारण ही अमर सिंह पार्टी से बेदखल हुए थे और पार्टी में उनकी वापसी नहीं हो पाई थी. मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह को राज्यसभा का टिकट देकर आजम और रामगोपाल की कोई परवाह नहीं की. मुलायम सिंह का 75वां सालगिरह आलीशान तरीके से रामपुर में मनाने वाले आजम खान ने उनके 76वें सालगिरह पर अमर सिंह को देख कर कहा था कि जब तूफ़ान आता है तो कूड़ा करकट आ ही जाता है. ऐसा कह कर वे सैफई से चले गए थे. लेकिन उनके विरोध को नजरअंदाज कर मुलायम ने अमर सिंह को राज्यसभा का टिकट दे ही दिया. संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रो. रामगोपाल ने विरोध दर्ज कराया लेकिन मुलायम ने उनके नाम पर मुहर लगा दी. शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जब नेताजी चाहेंगे अमर सिंह की पार्टी में वापसी भी हो जाएगी. अमर सिंह को राज्यसभा का टिकट दिए जाने से नाराज़ आजम खान ने कहा, नेताजी समाजवादी पार्टी के मालिक हैं, जिसे चाहें पार्टी में रखें. उनके फैसले को चुनौती देना मेरा अधिकार नहीं है. हालांकि यह बहुत दुखद कदम है.

बेनी प्रसाद वर्मा भी अमर सिंह के तीखे आलोचक रहे हैं. बेटे को टिकट न मिलने से नाराज होकर बेनी 2007 में पार्टी छोड़ गए थे. बेनी के बेटे राकेश वर्मा को अमर सिंह की वजह से ही टिकट नहीं मिला था. राज्यसभा का टिकट मिलते ही बेनी बोले कि पिछले दो साल से कांग्रेस पार्टी में उनका दम घुट रहा था. मुलायम सिंह यादव ने बेनी प्रसाद वर्मा का स्वागत करते हुए कहा कि बेनी हमारे पुराने साथी हैं. बेनी ने ही पार्टी को समाजवादी नाम दिया था. पार्टी बनाने में उनका बड़ा सहयोग मिला है. मेरे सारे राजनीतिक निर्णय में बेनी प्रसाद वर्मा हमारे साथ रहे. उनके पार्टी में शामिल होने से पूरे देश में एक संदेश जाएगा और सपा लखनऊ के साथ-साथ दिल्ली की लड़ाई भी लड़ेगी.

feedback@chauthiduniya.com

बेमानी हुईं दौर-ए-बेवफाई की बातें

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

यह दिलचस्प है कि मुलायम सिंह यादव से नाराज होने वाले उनके सभी पूर्व सहयोगी एक जैसे आरोप लगाते हैं लेकिन दोस्ती होते ही उनके स्वर बदल जाते हैं. फिर कोई मुलायम के दल में आ जाता है, तो कोई दिल में रहकर राज्यसभा का सदस्य होने की कतार में लग जाता है. कोई भी दौर-ए-बेवफाई में दिए गए बयानों को याद नहीं करना चाहता. ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था. ठीक भी है, दुश्मनी को दोस्ती में बदलते समय पुरानी कड़वाहट को भुलाना पड़ता है लेकिन निजी और सार्वजनिक जीवन में फर्क भी होता है. सार्वजनिक जीवन में समाज के प्रति जवाबदेही की अपेक्षा होती है क्योंकि यश, वैभव, पद प्रतिष्ठा आदि सभी कुछ समाज के द्वारा ही मिलता है. ऐसे में समाज को कुछ बातों का जवाब भी मांगना चाहिए.

दुश्मनी के बाद दोस्ती पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए. राजनीति में तो इसे प्रायः अस्थायी तत्व माना जाता है. मौके के अनुसार पैसले, फासले, रंग और पाले बदलते रहते हैं. न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर तालमेल या गठबंधन भी होते हैं. यह बेहतर तरीका होता है. आमजन को पता होता है कि परस्पर विरोधी पार्टियां किन मुद्दों पर साथ चलने को सहमत हुई है. इस दशा में न्यूनतम साझा कार्यक्रम ही अहम होता है. तब पहले एक दूसरे के लिए संबंधित पार्टियों के द्वारा क्या कहा गया, उसका महत्व नहीं रह जाता. यदि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर अमल मुनासिब न हो तो बिना किसी कठिनाई के संबंधित पार्टियां अलग राह पर लौट सकती हैं. पुनः एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल सकती हैं लेकिन निजी निर्णय अथवा बयान इस दायरे में नहीं आते. यह सही है कुछ बातें भूलनी पड़ती हैं लेकिन कतिपय बयानों पर स्पष्टीकरण भी मिलना चाहिए. यह दो नेताओं के बीच का मसला नहीं रह जाता. वरन इसमें समाज और शासन के विषय भी समाहित होते हैं. संबंधित राजनेता आमजन के प्रति अपनी इस जवाबदेही से बच नहीं सकते.

इस बात को नजरंदाज नहीं किया जा सकता कि आजम खान, बेनी प्रसाद वर्मा और अमर सिंह ने नाराजगी के दौर में मुलायम सिंह यादव पर लगभग एक जैसे आरोप लगाए थे. फर्क इतना है कि तीखे आरोप लगाने के बाद भी आजम खान ने न कोई नई पार्टी बनाई थी, न किसी अन्य दल में वह शामिल हुए थे. नई पार्टी बनाने का वह जोखिम नहीं उठा सकते थे. कांग्रेस में न जाने का कारण रामपुर और वहां के नवाब परिवार से जुड़ा मसला था. बसपा के बारे में आजम पहले ही इतना बोल चुके थे कि वहां गुंजाइश कम थी. इसके अलावा बसपा में जाते तो उनके बोलने पर लगाम लग जाती. आजम के लिए यह बहुत परेशान करने वाली सजा होती. इसे बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल था. फिर भी उन्होंने मुलायम पर हमले में कोई रियायत नहीं की थी. उन्होंने मुलायम पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भाजपा से साठगांठ करने तक का आरोप लगाया था. अपने इस आरोप को आजम ने प्रतीकात्मक ढंग से पेश किया था. कहा था कि मुलायम धोती के नीचे हाफपैंट पहनते हैं. अर्थात संघ से उनका लगाव है, लेकिन वह इसे छिपा कर रखते हैं. आरोप गंभीर था. इसमें बाबरी ढांचे का मसला भी समाहित था. आरोप लगाने वाला मुलायम सिंह यादव का लंबे समय तक सहयोगी रह चुका था. ऐसे में आरोप को हल्के में नहीं लिया जा सकता था. एक साथ कार्य करने वालों को अपने सहयोगी की पर्याप्त जानकारी होती है. मुलायम और आजम की दोस्ती के बाद भी आमजन को आरोप की वास्तविकता जानने का अधिकार था. दो ही विकल्प थे. एक यह कि आजम स्वीकार करते कि आरोप बेबुनियाद थे. दूसरा यह कि वह आरोपों के पक्ष में प्रमाण देते. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. आरोप आज भी रिकार्ड में है और दोस्ती चल रही है.

बेनी प्रसाद वर्मा ने भी मुलायम पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से साठगांठ का आरोप लगाया था. वह कई कदम आगे निकल गए थे और मुलायम पर आतंकवादी होने तक का आरोप लगाया था. कहा था कि मुलायम सिंह यादव देश के सबसे खतरनाक राजनीतिक जीव हैं, पता नहीं कब किसका भोजन कर जाएं. वह मुसोलिनी अर्थात तानाशाह हैं. लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले बेनी ने कहा था कि इंडियन मुजाहिदीन को पैदा करने वाले मुलायम सिंह यादव हैं. मुलायम ने ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को बढ़ावा दिया. इस बयान के कुछ समय बाद बेनी ने कहा कि मुलायम और आडवाणी ने मिलीभगत करके बाहरी मस्जिद गिरवाई. मुलायम हमेशा साम्प्रदायिक ताकतों का साथ देते रहे हैं. वह आतंकवादियों की मदद करते हैं.

जाहिर है कि बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे. इसमें आतंकवाद, साम्प्रदायिक, बाबरी ढांचा विध्वंस आदि बड़े मसले शामिल थे. दोस्ती से पहले बेनी यदि इतना कह देते कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद थे तो गनीमत होती. लगता कि साफ मन से दोस्ती हो रही है लेकिन आजम की ही भांति बेनी ने मुलायम पर जड़े गए आरोपों पर कोई अफसोस व्यक्त नहीं किया, न कोई सफाई दी. क्या इसी को दोस्ती कहते हैं. गंभीर आरोप तो अपनी जगह पर हैं. सभी बातें रिकार्ड पर हैं. बेनी और आजम की कठिनाई यह है कि वह मुलायम पर लगाए गए आरोप को झूठा बताएं तो उनकी विश्वसनीयता हमेशा के लिए समाप्त होगी. भविष्य में ये कोई बयान देंगे तो उस पर लोग आसानी से विश्वास नहीं करेंगे. यह माना जाएगा कि ये नेता अपने ही बयान से पलट जाएंगे. मतलब साफ है कि इन नेताओं ने दोस्ती नहीं केवल स्वार्थ को महत्व दिया. जब कांग्रेस में रहने पर स्वार्थ लगा तो वहां रहे. सोनिया और राहुल का गुणगान किया. केंद्र में मंत्री भी बने, लेकिन अब उन्हें केंद्र या प्रदेश में कांग्रेस का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है तो सपा में आ गए. अपनी और अपने पुत्र की चिंता ने उन्हें पाला बदलने को विवश कर दिया. वहीं मुलायम सिंह यादव आज कह रहे हैं कि अब बेनी के साथ दिल्ली की लड़ाई लड़ेंगे, जबकि लोकसभा चुनाव के समय मुलायम ने कहा था कि बेनी प्रसाद वर्मा अपने बेटे की जमानत तक नहीं बचा सके, राहुल को प्रधानमंत्री क्या बनाएंगे. अब मुलायम को यह बताना चाहिए कि बेटे की जमानत बचाने में विफल नेता के साथ यह दिल्ली की लड़ाई कैसे लड़ेंगे. लेकिन बेनी की भांति मुलायम भी कोई सफाई नहीं दे सकते. सपा सरकार पर एक जाति विशेष को वरीयता देने के आरोप लगते रहे हैं. वह बेनी को प्रतीक रूप में पेश करना चाहते हैं लेकिन सत्ता में रहने वालों को चेहरा नहीं अपने कार्यों पर ही विश्वास करना चाहिए. चुनाव में इसी का आकलन होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

विधानसभा चुनाव परिणाम

नया गणित, नए प्रतिमान नई उम्मीदें, नई चुनौतियां

ममता बनर्जी

जयललिता

सर्वानंद सोनोवाल

पी विजयन

पश्चिम बंगाल

किसे कितनी मिली सीटें

दल का नाम	विजयी
इंडियन नेशनल कांग्रेस	44
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	1
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	26
भारतीय जनता पार्टी	3
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस	211
ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक	2
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	3
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा	3
निर्दलीय	1
कुल	294

वोट प्रतिशत

तमिलनाडु

किसे कितनी मिली सीटें

दल का नाम	विजयी
इंडियन नेशनल कांग्रेस	8
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	134
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	89
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	1
कुल	232

वोट प्रतिशत

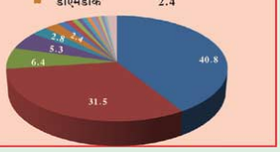

असम

किसे कितनी मिली सीटें

दल का नाम	विजयी
इंडियन नेशनल कांग्रेस	26
भारतीय जनता पार्टी	60
असम गण परिषद	14
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	13
बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट	12
निर्दलीय	1
कुल	126

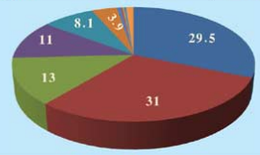

वोट प्रतिशत

आईएनसी	31.0	आईएनडी	11.0
बीजेपी	29.5	एजीपी	8.1
एआईयूडीएफ	13.0	बीपीएफ	3.9

केरल

किसे कितनी मिली सीटें

दल का नाम	विजयी
इंडियन नेशनल कांग्रेस	22
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	19
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (M)	58
नेशनल कांग्रेस पार्टी	2
भारतीय जनता पार्टी	1
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	18
केरल कांग्रेस (एम)	6
जनता दल (सेक्युलर)	3
कम्युनिस्ट मार्कसिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमेटी	1
केरल कांग्रेस (जैकब)	1
केरल कांग्रेस (बी)	1
कांग्रेस (सेक्युलर)	1
नेशनल सेक्युलर कांफ्रेंस	1
निर्दलीय	6
कुल	140

वोट प्रतिशत

सीपीएम	26.5	आईयूएमएल	7.4
आईएनसी	23.7	आईएनडी	5.3
बीजेपी	10.5	केईसी (एम)	4.0
सीपीआई	8.1	बीडीजेएस	3.9

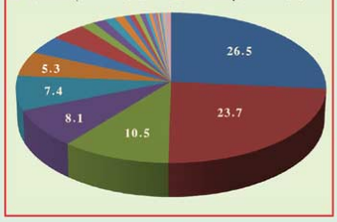

पुडुचेरी

किसे कितनी मिली सीटें

दल का नाम	विजयी
इंडियन नेशनल कांग्रेस	15
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	4
ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस	8
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	2
निर्दलीय	1
कुल	30

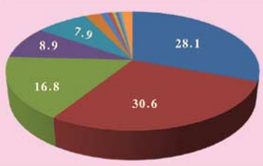

वोट प्रतिशत

आईएनसी	30.6	डीएमके	8.9
एआईएनआरसी	28.1	आईएनडी	7.9
एडीएमके	16.8	बीजेपी	2.4

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है. पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा की करारी हार हुई है. कांग्रेस को लेफ्ट से ज्यादा सीटें मिलीं हैं. ममता बनर्जी ने जबर्दस्त वापसी की है. लेकिन, केरल में वाममोर्चा ने सत्ता में वापसी तो की है लेकिन वहां हर पांच साल में जनता सरकार बदल देती है. उसी परंपरा का वाममोर्चा को फायदा मिला है. हालांकि, तमिलनाडु में प्रत्येक पांच साल में सरकार बदलने की चली आ रही परंपरा इस बार टूट गई और जयललिता यानी अम्मा ने दोबारा सत्ता में वापसी की. असम में निश्चित तौर पर भाजपा को जबरदस्त जीत हासिल हुई. कांग्रेस के हाथ से दो राज्य निकल गए, लेकिन पुडुचेरी की सत्ता उसके खाते में आ गई, जिसका कोई खास राजनीतिक महत्व नहीं है. इन परिणामों से कुछ सवाल निकलते हैं. मसलन, क्या भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के रास्ते पर तेज़ी से अग्रसर है? क्या लेफ्ट की राजनीति खत्म होने के कगार पर है? क्या भाजपा अब अजेय पार्टी बन गई है? कांग्रेस-लेफ्ट गठबंधन पश्चिम बंगाल में क्यों फेल हो गया? और अंत में यह कि इसका आने वाले राज्यों के चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा?

सबसे पहले बात असम की. यहां कांग्रेस अपनी करनी और एंटी-इंकबेंसी की वजह से हारी है. बीजेपी को जो भी मिला है, वह कांग्रेस की गलतियों की वजह से मिला है. बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा वहां एक अहम मुद्दा था. ऐसे में कांग्रेस ने अकेले ही चुनाव में उतरने का फैसला किया जबकि उसके पास बदरूद्दीन अजमल के साथ हाथ मिलाने का मौका था. गौरतलब है कि, चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक ग्रैंड अलायंस बनाने की सलाह दी थी लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. अब, यह कांग्रेस का अति आत्मविश्वास था या कुछ और कहना मुश्किल है, कि उसने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया. निश्चित तौर पर वोट बंटे, जिसका खामियाजा कांग्रेस समेत अजमल साहब की पार्टी को भी भुगतना पड़ा. असम में 30 फीसदी से अधिक मुस्लिम वोटर हैं. पिछली बार मौलाना बदरूद्दीन अजमल के असम युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 18 सीटें हासिल की थीं. लेकिन, इस बार उनकी सीटें घट गईं. फिर, 15 साल के लगातार शासन से एंटी इंकंबेंसी फैक्टर भी बन ही जाता है. भाजपा ने एक युवा चेहरे, सर्वानंद सोनोबाल को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया था. भाजपा ने खुल कर बांग्लादेशी मुसलमानों के अतिक्रमण को अपना मुद्दा बनाया, जिसका फायदा उसे मिला. एक बात और साफ हुई कि जहां भी भाजपा की सीधी टक्कर कांग्रेस से है या कहें कि दोतरफा मुक़ाबला हो, वहां भाजपा को जीत हासिल होती है. बहरहाल, इस जीत के बाद अब भाजपा के ऊपर असम के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने का दायित्व है. बांग्लादेशी घुसपैठ और अतिक्रमण जैसे मुद्दों का वह कैसे समाधान निकालती है, देखना दिलचस्प होगा.

जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है तो यहां लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन, दोनों पार्टियों के लिए ही नुकसानदायक साबित हुआ. यह कहा गया कि इस गठबंधन के तहत लेफ्ट का वोट कांग्रेस को तो मिला लेकिन कांग्रेस का वोट लेफ्ट को नहीं मिला. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने स्वीकार भी किया है कि एक तरफ कांग्रेस उम्मीदवारों को लेफ्ट मतदाताओं की ओर से मिले समर्थन से फायदा हुआ है, वहीं कांग्रेस के मतदाताओं का वोट अपने-अपने क्षेत्र में लेफ्ट के उम्मीदवारों को नहीं मिल पाया. उत्तरी बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन ने अच्छी खासी सीटें गंवाईं, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि वे यहां से बड़ी संख्या में सीटें जीतेंगे. दक्षिणी बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को उम्मीद थी कि उन्हें फायदा मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. यहां कांग्रेस को 44 सीटें मिली हैं और वह राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है. जाहिर है, लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करते हुए ममता बनर्जी ने अपना कद ऊंचा तो किया ही है साथ ही पश्चिम बंगाल में लगातार कमजोर हो रहे वाममोर्चा को और भी कमजोर बना दिया है. ऐसे में ममता बनर्जी आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में एक सशक्त चेहरा बनकर उभर सकती हैं.

तमिलनाडु में जयललिता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह तमिलनाडु की राजनीति की एक सशक्त धुरी हैं. उन्होंने लंबे समय से चली आ रही बारी-बारी से सत्ता परिवर्तन की परिपाटी को तोड़कर अपनी पार्टी को लगातार दूसरी बार जीत दिलाई. यहां 1989 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में बरकरार रहने में सफल रही. उन्होंने अम्मा कैंटीन जैसी कल्याणकारी योजनाओं से राज्य के आम लोगों के बीच अपनी पैठ मजबूत की. उनकी सरकार में राशनकार्ड धारकों को 20 किलोग्राम चावल, मुफ्त मिक्सर ग्राइंडर, दुधारु गाय, बकरियां बांटी गईं और मंगलसूत्र के लिए 4 ग्राम सोना दिया गया. उन्होंने इन सभी राशनकार्ड धारकों को मुफ्त मोबाइल फोन बांटने का वादा भी किया है. उनकी जीत से फिलहाल डीएमके की राजनीति को धक्का पहुंचा है. करुणानिधि परिवार में आंतरिक कलह की भी गुंजाइश बनेगी.

केरल में परंपरा के मुताबिक ही सत्ता का हस्तांतरण हुआ है. इस बार एलडीएफ की बारी थी, सो उसे सत्ता मिली है. भाजपा ने यहां से एक सीट जीतकर अपना खाता खोला है. भाजपा के वरिष्ठ नेता ओ राजगोपाल यहां से चुनाव जीते हैं. पिछले चालीस साल से वे राज्य में पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं. कई बार चुनाव हारने के बाद आखिरकार, उन्होंने पार्टी को अपनी एकमात्र जीत के साथ सफलता दिलवाई. केरल में लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सक्रिय है. पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 139 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे पर जीता कोई नहीं. इस बार उसने चार पार्टियों के साथ गठबंधन किया और एक सीट हासिल हुई.

लेकिन, मूल सवाल यही है कि क्या इस परिणाम से कांग्रेस मुक्त भारत की बात आगे बढ़ती दिखती है? फिलहाल, ऐसा होता नहीं दिखता. कांग्रेस को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर और सीटें बताती है कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अभी दूर है. पांच राज्यों में कांग्रेस के खाते में 125 सीटें आई हैं और वोट प्रतिशत भी ठीक-ठाक है. दूसरी तरफ, असम में भाजपा ने जिन मुद्दों पर चुनाव जीता है, जिन वादों पर लोगों ने भरोसा किया है, उन्हें पूरा करना, भाजपा के लिए एक कठिन चुनौती होगी. असमिया पहचान, बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मसले भाजपा के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं. असम के ये मुद्दे बहुत पुराने हैं. लोगों के आम जनजीवन से संबंधित हैं. नई सरकार कैसे घुसपैठियों की पहचान करेगी, कैसे उन्हें बांग्लादेश वापस भेजेगी, यहएक अहम सवाल है, जिसका जवाब आसानी से शायद ही मिल पाए.■

भारत में कितना सुरक्षित है पत्रकार

भारत में प्रेस की आज़ादी का अंदाज़ा हालिया दिनों में हुए पत्रकारों की गिरफ्तारी से भी लगाया जा सकता है. जुलाई 2015 के बाद से छत्तीसगढ़ में चार पत्रकारों संतोष यादव, समारू नाग, प्रभात सिंह और दीपक जायसवाल को गिरफ्तार किया गया. ख़बरों के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस यातनाएं भी दे रही है. हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद को प्रभात सिंह की गिरफ्तारी पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगनी पड़ी.

शफ़ीक आलम

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक स्थानीय पत्रकार करुण मिश्रा की हत्या का ज़ख्म अभी ताज़ा ही था कि बिहार और झारखण्ड में महज़ कुछ घंटों के अन्तराल पर एक के बाद एक दो पत्रकारों की हत्या कर दी गई. बिहार के सीवान में दैनिक हिन्दुस्तान अख़बार के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन और झारखंड के चतरा में स्थानीय न्यूज चैनल के पत्रकार अखिलेश प्रताप सिंह अपराधियों की गोलियों का शिकार बन गए. दोनों मामलों में गोली नज़दीक से चलाई गई थी और पुलिस की प्रारंभिक जांच यह बता रही है कि इन दोनों हत्याओं के पीछे स्थानीय माफियाओं और राजनेताओं के गठजोड़ काम कर रहा था. बहरहाल, विस्तृति जांच रिपोर्ट आने के बाद भी यह सवाल बना रहेगा कि क्या इन हत्याओं के असल दोषीयों को सजा मिलेगी?

बहरहाल, उक्त तीनों घटनाओं ने एक बार फिर यह ज़ाहिर कर दिया है कि देश में पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं. इन वारदातों ने प्रेस की आज़ादी और पत्रकारों की सुरक्षा के मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की ख़राब छवि को एक बार भी उजागर कर दिया है. पिछले कुछ वर्षों से भारत में हो रहे पत्रकारों पर जानलेवा हमले का सिलसिला वर्ष 2016 में भी थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस वर्ष बीते पांच महीनों में ही हुई कम से कम पांच पत्रकारों की हत्याएं हुईं. इससे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में पिछले कुछ वर्षों की भांति इस वर्ष भी भारत पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों के साथ खड़ा होगा.

पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारों की सुरक्षा के मामलों से संबंधित प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में भारत दुनिया के सबसे खतरनाक देशों सीरिया और इराक के साथ खड़ा नज़र आता है. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की सूची में तीसरे स्थान पर था. इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में दुनिया में कुल 110 पत्रकार अपना काम करते मारे गए थे, जिनमें से भारत में कुल 9 पत्रकारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक भारत की रैंकिंग पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान से भी नीचे थी और केवल गृहयुद्ध की मार झेल रहे इराक और सीरिया ही इस मामले में भारत से ऊपर थे. इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ-साथ पत्रकारों की अधिकतम हत्या वाले देशों में इराक (11), सीरिया (10), फ्रांस (8), यमन (8) मैक्सिको (8), साउथ सूडान (7), फिलीपीन्स (7) और होंडुरस (7) के नाम शामिल थे. गौरतलब है कि फ्रांस का नाम इस सूची में शार्ली अब्दो के कार्टून प्रकरण के बाद उसके दफ्तर पर हुए हमले की वजह से शामिल हो गया था. इस सूची में शामिल फ्रांस के सभी पत्रकार आतंकी हमले का शिकार हुए थे, वरना फ्रांस का नाम इस सूची में इतना ऊपर शायद नहीं होता. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक पूरे विश्व में मारे गए 110 पत्रकारों में से कम से कम 67 पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने काम के दौरान अपनी जान गंवाई और शेष हत्याओं की वजह अस्पष्ट हैं. पिछले कुछ वर्षों के दौरान पूरी दुनिया पत्रकारों के लिए खतरनाक जगह बन गई है. इसका बात की पुष्टि इस रिपोर्ट से भी होती है कि वर्ष 2005 से 2015 तक पूरे विश्व में कुल 787 पत्रकार मारे गए और साल दर साल यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है.

वर्ष 2014 में प्रकाशित एक रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इसमें भारत कहां खड़ा है. वियाना स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रेस संस्थान (आईपीआई) के मुताबिक वर्ष 2014 में पूरी दुनिया में 100 पत्रकार मारे गए थे, जिनमें भारत के केवल 2 पत्रकार शामिल थे. उस वर्ष भारत पत्रकारों के लिए खतरनाक देशों की सूची में सातवें स्थान पर था. लेकिन इसके एक वर्ष पूर्व यानि 2013 में यह आंकड़ा 11 का था. नतीजतन 2013 की आईपीआई की मारे गए पत्रकारों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया था, जो 2015 में एक बार फिर बरक़रार रहा. बहरहाल, बात यह कि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे और इन दंगों में दो पत्रकार राजेश वर्मा और इसरार मारे गए थे. इस वर्ष उत्तर प्रदेश में चार पत्रकार मारे गए थे. मुजफ्फरनगर दंगों में मारे गए राजेश वर्मा और इसरार के अलावा बुलंदशहर में ज़ाकाउल्लाह और इटावा में राकेश शर्मा की हत्याएं हुई थी. वर्ष 2013 में भी भारत पत्रकारों की सुरक्षा के मामले में सीरिया और इराक के बाद दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक देश माना गया था. वर्ष 2004 से 2013 तक की आईपीआई की डेथ वॉच सूची में भारत लगातार सातवें स्थान पर बना रहा था.

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2016

देश	रैंकिंग
फ़िनलैंड	01
नीदरलैंड्स	02
नॉर्वे	03
स्वीडन	08
जर्मनी	16
कनाडा	18
चेक रिपब्लिक	21
ऑस्ट्रेलिया	25
स्पेन	34
टोंगा	37
यूनाइटेड किंगडम	38
संयुक्त राज्य अमेरिका	41
फ्रांस	45
नाइजर	52
मंगोलिया	60
हांगकांग	69
साउथ अफ्रीका	70
इटली	77
ग्रीस	89
पनामा	91
इजरायल	101
कुवैत	103
ब्राज़ील	104
क़तर	117
यूनाइटेड अरब अमीरात	119
अफ़ग़ानिस्तान	120
इंडोनेशिया	130
फिलिस्तीन	132
भारत	133
श्रीलंका	141
म्यांमार	143
बांग्लादेश	144
पाकिस्तान	147
रूस	148
टर्की	151
इराक	158
सऊदी अरब	165
क्यूबा	171
चीन	176
सीरिया	177
उत्तर कोरिया	179
एरिट्रेरिया	180

जहां तक एशिया क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल है तो यहां वर्ष 2014 की आईपीआई की सूची के अनुसार कुल 23 पत्रकार मारे गए थे, जिनमें से सबसे अधिक पांच-पांच पत्रकार पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मारे गए. वर्ष 2014 में दक्षिण एशिया क्षेत्र पत्रकारों के लिए खतरों के मामलों में केवल मध्य पूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से पीछे था. इस वर्ष मध्य पूर्व एशिया में कुल 38 पत्रकार मारे गए, जिनमें 18 केवल सीरिया में मारे गए. उल्लेखनीय है कि कनफ्लिक्ट और वॉर ज़ोन्स में मरने वाले पत्रकारों की संख्या सबसे अधिक है. भारत जैसे शांति पूर्ण देश भी पत्रकारों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं.

यदि 2016 में अब तक हुई पत्रकारों की हत्याओं पर नज़र डालें तो यह आसानी से कहा जा सकता है कि इस वर्ष भी भारत को पत्रकारों के लिए असुरक्षित देश होने का दाग अपने माथे पर लेकर चलना होगा. इस वर्ष भी भारत में पत्रकारों की सुरक्षा की स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी खराब रहने वाली है. इस साल अब तक पाकिस्तान में एक पत्रकार की हत्या हुई है. जबकि बांग्लादेश में भी एक संपादक मारा गया है. वहीं अफगानिस्तान में आतंकियों ने एक पत्रकार को मौत की घाट उतार दिया. वर्ष 2016 के बीते चार महीनों की बात करें तो अब तक पूरी दुनिया में 19 पत्रकार मारे गए हैं, जिनमें से दस पत्रकारों की हत्या के पीछे रहे मकसद का जांच एजेंसियों ने पता लगा लिया.

अब सवाल यह उठता है कि भारत में पत्रकार, खास तौर पर छोटे शहरों का पत्रकार, अपराधियों के निशाने पर क्यों रहता है? छोटे शहरों में काम कर रहे पत्रकारों की रिपोर्टिंग अधिकतर स्थानीय स्तर के भ्रष्टाचार, ग्राम पंचायत के फैसलों, जन सुनवाई में अधिकारी की अनुपस्थिति, ग्राम सभा की गतिविधियों, सड़कों की बदहाली, बिजली की समस्या, स्थानीय अधिकारियों, विधायकों के कारनामों और स्थानीय आपराधिक मामलों आदि पर केंद्रित रहती है. अक्सर यह देखा गया है कि इनकी ख़बरों से बड़े खुलासे होने की संभावनाएं होती हैं. लिहाज़ा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान न होने के कारण कई बार ऐसे पत्रकार अपनी ख़बरों की वजह से स्थानीय स्तर पर काम कर रहे माफियाओं और अपराधियों का निशाना बन जाते हैं. यहां तक कि पुलिस प्रशासन भी उन्हें झूठे मुक़दमों में फंसा देती है.

प्रेस की आज़ादी

भारत का संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है. सत्ता और विपक्ष में बैठे सभी राजनीतिक दल संविधान द्वारा दिए गए इस अधिकार की दुहाई देते हुए अक्सर नज़र आते हैं. लेकिन जब एक अंतरराष्ट्रीय मानक पर भारत संयुक्त अरब अमीरात और क़तर जैसे राजतंत्रों, आतंकवाद और गृहयुद्ध की मार से जूझ रहे अफ़ग़ानिस्तान से भी पीछे चला जाए तो यह ज़रूर एक चिंता की बात है. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स (सूचकांक) पर दुनिया के 180 देशों में भारत का स्थान 133वां है. हालांकि इस वर्ष भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में तीन अंकों का सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी स्थिति उत्साहजनक नहीं है. (देखें बॉक्स). इस रिपोर्ट में भारत के पडोसी देशों में पाकिस्तान 147वें स्थान पर, श्रीलंका 141वें स्थान पर बांग्लादेश 144वें स्थान के साथ भारत से पीछे है, जबकि अफ़ग़ानिस्तान 120वें स्थान, नेपाल 105वें स्थान और भूटान 94 वें स्थान के साथ भारत से ऊपर हैं. इस रैंकिंग में दिलचस्प बात यह है कि क़तर और यूएइ जैसे राजतंत्र प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत से आगे हैं.

भारत में प्रेस की आज़ादी का अंदाज़ा हालिया दिनों में हुए पत्रकारों की गिरफ्तारी से भी लगाया जा सकता है. जुलाई 2015 के बाद से छत्तीसगढ़ में चार पत्रकारों संतोष यादव, समारू नाग, प्रभात सिंह और दीपक जायसवाल को गिरफ्तार किया गया. ख़बरों के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस यातनाएं भी दे रही है. हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद को प्रभात सिंह की गिरफ्तारी पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगनी पड़ी. इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर एमेनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने रमन सिंह सरकार से यह मांग की कि राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार पत्रकारों को तुरंत रिहा करे. दरअसल छत्तीसगढ़ में पत्रकार दोहरी मार का शिकार हैं, जहां सरकार और पुलिस के खिलाफ रिपोर्टिंग करने पर उन्हें पुलिस और प्रशासन द्वारा फर्जी मामलों में फंसा कर गिरफ्तार कर लिया जाता है. वहीं पत्रकारों को स्थानीय गुंडों और नेताओं का भी शिकार होना पड़ता है. मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चल रही सुरक्षा फोर्सेज की कार्रवाई में मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों को उजागर करने वाली पत्रकार मालिनी सुब्रमनियम को उनके घर पर हमले के बाद और पुलिस के दबाव में उनके माकन मालिक ने उन्हें घर खाली करने के लिए कह दिया. इसके अलावा पत्रकारों की गिरफ्तारी के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. मसलन नक़ली आरटीआई मामले में पुलिस ने पुष्प शर्मा को दिल्ली में गिरफ्तार किया है.

देश में पत्रकारों की हो रही लगातार हत्याओं और उनकी असुरक्षा को देखते हुए यह ज़रूरी हो गया है कि उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए और उन पर हुए हमलों के मामलों को स्पीड ट्रायल के जरिए निपटाया जाए. प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया अपनी रिपोर्ट में कह चुका है कि पत्रकारों से सम्बंधित 97 प्रतिशत आपराधिक मामले अभी तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं. इन्हीं कारणों से नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स कई बार जर्नलिस्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग कर चुका है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं हो पाई है.

भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है. पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और पत्रकारों को लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है. जहां एक तरफ पत्रकारिता लोगों में जागरूकता पैदा करके लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है, तो वहीं लोकतंत्र के दूसरे स्तंभों यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका पर भी नज़र रखता है. यदि इराक, सीरिया, अफ़ग़ानिस्तान इत्यादि जैसे गृहयुद्ध से जूझ रहे देशों (कनफ्लिक्ट जोन) में पत्रकारों की जान जाती है तो बात समझ में आती है, लेकिन भारत के उन क्षेत्रों भी में जहां कोई सशस्त्र संघर्ष नहीं चल रहा है, अगर वहां भी पत्रकारों को अपना काम ईमानदारी से करने का इनाम मौत या गिरफ्तारी की शक्ल में मिले, तो इससे न सिर्फ देश की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ जाती है बल्कि यह लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सफेद हाथी साबित होती सूखा राहत योजनाएं

प्रदेश के जो अधिकारी भी ग्रामीण भ्रमण पर गए थे उनमें से अधिकांश ने अपनी रिपोर्ट में भ्रमण किए गए गावों में गर्मी के मौसम में पानी की कमी होने की आशंका जताई थी और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही थी. अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि पिछले दो वर्षों से वर्षा नहीं होने के कारण गांवों का भू-जल स्तर गिर गया है, अधिकांश गांवों में नल-जल योजना के पाइप डले हैं लेकिन पानी की सप्लाई बंद है. अधिकांश गावों में नल-जल योजना फेल है. इसके अलावा गांवों में जो हैंडपंप लगे हैं उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है. प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सरकार को भ्रमण की रिपोर्ट दिए छह महीने से ज्यादा समय गुजर गया, लेकिन सरकार ने उनके सुझावों पर कतई अमल नहीं किया.

चौथी दुनिया ब्यूरो

करने को तो मध्य प्रदेश सरकार सूखा राहत के लिए बहुत से कदम उठा रही है या उसने इसके लिए अब तक बहुत से कदम उठाएं हैं लेकिन इन योजनाओं का फायदा लोगों को होता नहीं दिखाई पड़ रहा है. पिछले साल अवर्षा की वजह से उत्पन्न हुई संभावित सूखे की स्थिति के आंकलन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए तीन दिन (25, 26 और 27 अक्टूबर) के ग्रामीण भ्रमण पर भेजा था. इसके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों अलग-अलग विकास खंड आवंटित किए गए थे. आदेशानुसार उन्हें नौ से दस गांवों का दौरा करके, ग्रामीणों के साथ बातचीत करके ज़मीनी अनुभव के आधार पर अवर्षा की स्थिति, कृषि और इससे जुड़े विषयों के संबंध में रिपोर्ट देनी थी. अधिकारियों को भ्रमण किए गए गांवों में पीने के पानी की स्थिति एवं स्रोत, अगली फसल के लिए (गत वर्ष की तुलना में) कुएं, तालाब, नहर, ट्यूबवेल व अन्य संसाधनों से सिंचाई की व्यवस्था की जानकारी मांगी गई थी. और सबसे प्रमुख अधिकारियों को यह जानकारी भी देनी थी कि गर्मी तक उन गांवों में पीने का पानी उपलब्ध रहेगा या नहीं, या गर्मियों में इन गांवों में पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी. वैकल्पिक व्यवस्था कैसी होगी इस संबंध में अधिकारियों को ग्रामीणों से बातचीत कर सुझाव देने थे.

जो अधिकारी भी ग्रामीण भ्रमण पर गए थे उनमें से अधिकांश ने अपनी रिपोर्ट में भ्रमण किए गए गावों में गर्मी के मौसम में पानी की कमी होने की आशंका जताई थी और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही थी. अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि पिछले दो वर्षों से वर्षा नहीं होने के कारण गांवों का भू-जल स्तर गिर गया है, अधिकांश गांवों में नल-जल योजना के पाइप डले हैं लेकिन पानी की सप्लाई बंद है. अधिकांश गावों में नल-जल योजना फेल है. इसके अलावा गांवों में जो हैंडपंप लगे हैं उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है. प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सरकार को भ्रमण की रिपोर्ट दिए छह महीने से ज्यादा समय गुजर गया, लेकिन सरकार ने उनके सुझावों पर कतई अमल नहीं किया.

इसका सीधा सा उदाहरण नल-जल योजना है. इस योजना की शुरूआत साल 2011 में केंद्र सरकार द्वारा स्पेशल बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत जल प्रदाय योजना की शुरूआत की गई थी. प्रदेश के सभी गांवों में घर-घर तक पीने का पानी सप्लाई करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने इस योजना के विस्तार का खाका तैयार किया था. गत वर्ष अक्टूबर माह में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) की समीक्षा बैठक में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश के हर घर में इस योजना के बल पर पानी पहुंचाने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि पानी पहुंचाने के प्रबंध अभी से किए जाएं ताकि गर्मियों में प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में दिक्कत न आए. जिन जगहों पर बिजली की दिक्कत है उन बसाहटों में सौर ऊर्जा आधारित नल-जल योजना चलाने की बात कही गई थी. लेकिन आज स्थिति यह है कि प्रदेश के तकरीबन 70 प्रतिशत गांवों में यह योजना बंद पड़ी है. एक तरह से सूखे से निपटने के लिए शुरू की गई अधिकांश योजनाएं सफेद हाथी साबित हो रही हैं. सरकार इन योजनाओं के नाम पर अथाह पैसे खर्च कर रही है लेकिन इसका प्रभाव ज़मीनी स्तर पर नहीं हो रहा है.

मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के 150 गावों में सन 2011 में इस योजना की शुरूआत की गई थी. जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव में दो पानी की टंकी और एक पंप लगाया जाना था. इसके लिए 9 करोड़ रुपये भी खर्च किए गए, लेकिन आज पांच साल बाद इन 150 गावों में से 87 गांवों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह योजना ठप्प पड़ी है. इसके अलावा सरकार जिन 63 गांवों में इस योजना के चलने का दावा किया जा रहा है उनमें से 33 गांवों में योजना बदहाल है. क्या ऐसे में सरकारों से सूखे से जूझ रहे लोगों की प्यास बुझाने की अपेक्षा की जाए. यदि प्रदेश के सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इस योजना की यह हालत है तो राज्य के अन्य हिस्सों में इसका क्या हाल होगा इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है. प्रदेश सरकार पर इस योजना के असफल होने का आरोप इसलिए भी लग रहा है क्योंकि विधान सभा में तकरीबन हर क्षेत्र के विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से बंद पड़ी नल-जल योजना के पुनः प्रारंभ होने के संबंध में सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन मंत्री महोदया के पास इस योजना के पुनः प्रारंभ होने के संबंध में कोई साफ जवाब नहीं है. यह स्थिति तब है जब सरकार सूखा राहत को अपनी कार्यसूची में सबसे ऊपर रखा है. पिछले साल 16 दिसंबर को विधान सभा में 163 सवाल पूछे गए थे जिनमें लगभग 28 सवाल केवल नल जल योजना से संबंधित थे. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नल-जल योजना की प्रदेश में क्या स्थिति है. कहीं मोटर चलाने के लिए बिजली नहीं है, तो कहीं वोल्टेज कम है, कहीं मोटर महीने से जली पड़ी है तो कहीं बोर में पानी नहीं है. कहीं टंकी लगी है तो पाइप लाइन नहीं बिछी है.कई जगहों पर तो खराब गुणवत्ता की पाइपलाइन बिछाने की खबरें भी आईं यह बात मंत्री कुसुम सिंह मेहदले ने भी सदन में स्वीकार की थी. सरकार ने योजना में पैसा तो खर्च किया लेकिन इनका संचालन नहीं हो पा रहा है न ही रख-रखाव. ऐसे में इसे मजद दिखावा ही कहा जाएगा कि सरकार प्रदेश के घर-घर तक लोगों के पास पानी तो पहुंचाने का श्रेय लेना चाहती है लेकिन लेकिन इसके लिए न तो वह गंभीर है और न ही उसका महकमा.

यूपी के आठ जिले सूखाग्रस्त घोषित केंद्र से मांगी मदद

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे के आठ जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है. इनमें बुंदेलखंड के सात जिले और कानपुर नगर जिला शामिल हैं. प्रदेश में रबी फसल के दौरान बारिश न होने से किसानों के नुकसान की सूचना पर केंद्र सरकार ने पिछले महीने प्रदेश सरकार से सूखे की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी. इस पर शासन ने जिलों से रिपोर्ट मांगी, तो बुंदेलखंड के ललितपुर को छोड़कर छह जिलों और कानपुर नगर में 33 फीसदी से अधिक फसलों के नुकसान की बात सामने आई. इन सात जिलों में 1,261 करोड़ के नुकसान का हवाला देते हुए केंद्र से सहायता मांगी गई है. उक्त जिलों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया जा रहा था जिससे केंद्र सरकार मेमोरंडम की जांच केलिए अपनी टीमें नहीं भेज पा रही थी. केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर इसकी सूचना भेजने का निर्देश दिया था. इस पर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के बांदा, महोबा, झांसी, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन व ललितपुर तथा कानपुर नगर जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने का फैसला कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से किया. केंद्र को भेजे गए रबी मेमोरेंडम में ललितपुर जिला शामिल नहीं था, फिर भी केंद्र ने ललितपुर को भी सूखाग्रस्त जिलों में शामिल कर लिया है. इससे प्रदेश सरकार केंद्र को नए सिरे से मांगपत्र भेज सकती है. सूखाग्रस्त घोषित करने की रिपोर्ट केंद्र को भेजी जा रही है. रिपोर्ट पाते ही केंद्र सरकार सूखाग्रस्त जिलों का जायजा लेने के लिए अपनी टीम भेजेगी. इसी टीम की रिपोर्ट पर राहत पर फैसला होगा.

पिछले साल भी 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए थे. तब किसानों को क्या मदद मिली थी, सरकार के कारनामे जगजाहिर हो चुके हैं. सरकार ने पिछले साल मध्य यूपी के सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, कानपुर नगर, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, कानपुर देहात, फतेहपुर, पूर्वांचल के बलिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, जौनपुर, गोंडा, फैज़ाबाद, बाराबंकी, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, महाराजगंज, कुशीनगर, इलाहाबाद, कौशांबी, अंबेडकरनगर और बलरामपुर, विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, चंदौली, पश्चिमी यूपी के मैनपुरी, शाहजहांपुर, एटा, इटावा, बागपत, रामपुर, कन्नौज, हाथरस, आगरा, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, औरैया, पीलीभीत, बुंदेलखंड के बांदा, झांसी, जालौन, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर को सूखाग्रस्त जिला घोषित किया था.

यदि सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में इस योजना की यह हालत है तो राज्य के अन्य हिस्सों में इसका क्या हाल होगा इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है.

इसी तरह सरकार की एक अन्य योजना है कपिल धारा योजना. इस योजना में अधिकतम 50 फिट की गहराई तक किसान के खेत में कुआं खोदने का प्रावधान है. जिसका व्यास छह मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए. इसके निर्माण में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लोगों को रोजगार भी मिलता है. कपिल धारा योजना के लिए सरकार एक से तीन लाख के रुपये के बीच आवश्यक्तानुरूप धन उपलब्ध कराती है, इसका मुख्य लक्ष्य बारिश के पानी को संरक्षित कर किसान को रबी की फसल के लिए पानी उपलब्ध कराना है जिससे कि किसान एक से ज्यादा फसल का उत्पादन अपने खेत में कर सके और उसके पास अपने उपयोग के लिए गर्मियों में भी पानी उपलब्ध रहे. लेकिन अधिकांश भ्रष्टाचार की वजह से कुओं को 50 फिट से कम खोदा गया. इस वजह से इनमें ज्यादा पानी संरक्षित नहीं हो पाता है, ऐसे में यह योजना हितग्राही मूलक न होकर भ्रष्टाचार मूलक बनकर रह गई है. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना शत प्रतिशत सफल नहीं हो सकती है क्योंकि जल स्तर के लगातार नीचे जाने की वजह से जमीन का पानी कुएं में एकत्रित नहीं हो पाता है. वहीं दूसरी तरफ लगातार वर्षा न होने की वजह से भी इनमें पानी एकत्र नहीं हो पाता है. ऐसे में सरकार को लोगों को सूखे से निजात दिलाने के लिए दृगामी कदम उठाने चाहिए. पानी के लिए पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद लोगों के गले तर नहीं हो पा रहे हैं. ऐसे में सरकारी योजनाओं और सरकार की मंशा पर निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

2019 में मोदी को पहले से अधिक मेहनत करनी होगी

पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए हैं. ये परिणाम वैसे ही हैं, जैसी कि उम्मीद की गई थी. केरल में हमेशा सरकार बदलती रही है. एक बार एलडीएफ तो दूसरी बार यूडीएफ. इसी प्रथा के तहत यहां का चुनाव परिणाम आया है. इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है. तमिलनाडु में भी आमतौर पर एआईएडीएमके और डीएमके के बीच सत्ता बदलती रही है. लेकिन, इस बार एआईएडीएमके दोबारा सत्ता में चुन कर आई है. इससे पुरानी प्रथा समाप्त हो गई है कि कोई एक दल लगातार दूसरी बार तमिलनाडु में सत्ता में नहीं आता. इसके लिए जयललिता को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने तमाम विवादों के बाद भी अभी तक लोगों के विश्वास को कायम रखा है. पश्चिम बंगाल में लोगों ने सोचा कि ममता बनर्जी साधारण बहुमत पाएंगी, लेकिन उन्हें एक शानदार बहुमत मिला है. उनका मतदाता आधार बरकरार रहा. कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ मिलाने का भी ममता के वोट बैंक पर असर नहीं हुआ. असम में 15 साल के कांग्रेस शासन के बाद एंटी इंकंबेंसी (सत्ता के खिलाफ लहर) होनी ही थी. अच्छी बात यह है कि असम के मतदाताओं में कोई भ्रम नहीं रहा और भाजपा को एक स्पष्ट बहुमत मिला. मैं समझता हूं कि आज कल मतदाताओं में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो वे एक तरफ हो जाते हैं. अब, जनता चुनाव परिणाम आने के बाद त्रिशंकु स्थिति या हॉर्स ट्रेडिंग (विधायकों की खरीद-बिक्री) नहीं होने देना चाहती. लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत है.

पश्चिम बंगाल में लोगों ने सोचा कि ममता बनर्जी साधारण बहुमत पाएंगी, लेकिन उन्हें एक शानदार बहुमत मिला है. उनका मतदाता आधार बरकरार रहा. कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ मिलाने का भी ममता के वोट बैंक पर असर नहीं हुआ. असम में 15 साल के कांग्रेस शासन के बाद एंटी इंकंबेंसी (सत्ता के खिलाफ लहर) होनी ही थी. अच्छी बात यह है कि असम के मतदाताओं में कोई भ्रम नहीं रहा और भाजपा को एक स्पष्ट बहुमत मिला. मैं समझता हूं कि आज कल मतदाताओं में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो वे एक तरफ हो जाते हैं. अब, जनता चुनाव परिणाम आने के बाद त्रिशंकु स्थिति या हॉर्स ट्रेडिंग (विधायकों की खरीद-बिक्री) नहीं होने देना चाहती. लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत है.

कुल मिलाकर, मैं यह नहीं मानता कि तीन साल बाद होने वाले केंद्रीय चुनाव के संबंध में इन राज्यों के चुनाव परिणाम का कोई लेना-देना है. इन परिणामों से अगर कोई संकेत निकलता है तो यह कि पश्चिम बंगाल में ममता और केरल में वाममोर्चा के जीतने के तीन साल बाद लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को पहले से कहीं अधिक मेहनत करनी होगी. तीन साल का समय अभी भी बहुत है और जहां तक राष्ट्रीय परिदृश्य की बात है तो दो समस्याएं हैं. पहली तो यह कि जिन लोगों ने मोदी को वोट दिया था वे अब निराश हो रहे हैं. लोगों ने जितनी उम्मीदें की थीं और जिस तेज़ी से परिणाम मिलनी की उम्मीदें की थीं, वे पूरी नहीं हो रही हैं. दूसरी बात यह कि कांग्रेस अगले चुनाव के लिए उत्साहित नहीं दिख रही है और न ही कोई आक्रामक लीडरशीप पेश करती नज़र आ रही है. इसका फायदा भाजपा को ही मिलेगा. निश्चित तौर पर, तीसरा मोर्चा अपने आंतरिक मतभेद की वजह से अस्तित्व में नहीं आ पा रहा है. यदि, मुलायम सिंह, लालू यादव और नीतीश कुमार और अन्य नेता साथ आते हैं, तो यह एक ताकतवर मोर्चा हो सकता है. लेकिन, 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और तभी पता चलेगा कि ये सभी बातें कहां और किस स्थिति में हैं. अभी तक लोग मान रहे हैं कि मायावती जीतेंगी. मुलायम सिंह की पार्टी के पास सोचने-विचारने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं. राज्यसभा में अभी मुलायम सिंह ने जिन लोगों के नाम का चयन किया है, उसमें बेनी प्रसाद वर्मा हैं. वो कुर्मी जाति से आते हैं, जो करीब 12 से 13 फीसदी हैं. उन्होंने निषाद का चयन किया है, रेवती रमण सिंह, जो कि भूमिहार हैं. राजनीतिक रूप

से महत्वपूर्ण लोगों की जगह मुलायम सिंह ने इस बार अपने पसंदीदा लोगों का चयन किया है. इसलिए, 2017 को लेकर वे कितने गंभीर हैं, इसे समझा जा सकता है. उत्तर प्रदेश का 2017 में क्या परिणाम आता है, इसके बाद ही कोई व्यक्ति 2019 के आम चुनाव की पूर्व समीक्षा कर सकता है.

ये सभी बातें तो चुनाव से संबंधित हैं. आमतौर पर देश आगे चलता रहता है. हालांकि, सुब्रमण्यम स्वामी, जो हाल ही में राज्यसभा के लिए नामांकित हुए हैं, ने कुछ मुद्दे उठाए हैं. जैसे कि वे चाहते है कि दो लॉ ऑफिसर को बदल दिया जाए, आरबीआई के गवर्नर को बदल दिया जाए. लेकिन, जिस तरह से वह यह बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि उन्हें ऊपर से कोई संकेत मिल रहा है या समर्थन हासिल है. बेशक यह बहुत सारे लोगों को मालूम है कि रघुराम राजन शिकागो डॉक्टरीन की नीतियों का अनुपालन करते हैं. एस गुरुमूर्ति ने लिखा है कि वित्तीय घाटा एक बेहतर चीज है जब क्रेडिट एक्सपेंशन और महंगाई दर व्यापक रूप लेती है. अगर यह नहीं हो तो आपको अर्थव्यवस्था में धन मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त वित्त का नुक़सान होता है. बेशक यह एक ऐसा विषय है, जिसे अर्थशास्त्र के माहिर ही बेहतर तरीके से समझा सकते हैं. पीएमओ और वित्त मंत्रालय के अधिकारी इस पर अपनी राय दे सकते हैं. लेकिन, यह सच्चाई है कि जब तक अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं डाला जाएगा, तब तक निवेश के वातावरण में सुधार नहीं होगा. विदेशी निवेश में सामान्य प्रवाह बना हुआ है. इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है, बड़ा निवेश नहीं आ रहा है. अगले छह माह से एक साल के दरम्यान सरकार को कुछ ऐसे कदम जरूर उठाने चाहिए ताकि घरेलू या विदेशी निवेश में वृद्धि हो.

आरबीआई के गवर्नर पर दो तरह की राय हैं. इनसे उद्योग जगत या विदेशी निवेशक खुश नहीं है क्योंकि वे ब्याज दर घटा नहीं रहे हैं. लेकिन, मौजूदा वक्त में उनकी साख बेहतर है. ऐसे में, उद्योग जगत यह कह सकता है कि उनको हटाने से सरकार की साख कमजोर होगी. इन सारी बातों के बावजूद, भारत जैसे विशाल देश में किसी एक व्यक्ति के होने या न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. बहरहाल, सरकार को इस अनिश्चितता को समाप्त करते हुए कहना चाहिए कि सरकार रघुराम राजन को एक और कार्यकाल दे रही है या फिर किसी नए व्यक्ति को आरबीआई गवर्नर नियुक्त कर रही है. इस तरह की अनिश्चितता और सांसदों द्वारा दिए गए बयान सरकार के लिए ठीक नहीं हैं. देखते हैं, आगे क्या होता है.■

feedback@chauthiduniya.com

नई आर्थिक नीतियां हटाने का वक्त

(के सी त्यागी का राज्यसभा में दिए गए विदाई-भाषण का अंश)

के सी त्यागी

आर्थिक सुधारों के 25 साल मनाए जा रहे हैं, सिल्वर जुबली है. अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन आ रहे हैं. हमारे जो दायीं तरफ के नए मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं इन्होंने तो नेहरू जी की नीतियों को छोड़ दिया, उनका स्थान तो मोंटेक सिंह जी ने ले लिया. हमारे बायीं तरफ के जो मित्र हैं, श्री कलराज मिश्र जी से लेकर, उनके इंटेलेक्चुअल्स, जैसे पनगढ़िया जी और सुब्रमण्यम जी और उसमें प्रभात झा जैसे जनसंघ वाले भी शामिल हैं.

दुनिया की कोई शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती, जिसका अब वक्त आ गया है, वे नए इकोनॉमिक रिफॉर्म हैं. वे क्या हैं? बाजार की भूमिका को ऊपर रखना, निजी क्षेत्र, निजी संपत्ति को बढ़ावा देना, उदारीकरण, निजीकरण और भू-मंडलीकरण को बढ़ावा देना. यह प्रयोग थैचर और रीगन ने ब्रिटेन और अमेरिका में किए थे. मैं फिर डॉ. मनमोहन सिंह जी की एक और लाइन पढ़ता हूं कि नए भारत के निर्माण के लिए घिसी-पिटी प्रतिबद्धताएं, नेहरू मॉडल को दूर फेंकना होगा. मैं दूसरी लाइन माननीय जसवंत सिंह जी की सुना रहा हूं कि केंद्रीय नियोजन पर हमारी प्रतिबद्धता बड़ी भूल थी. क्या इन आर्थिक नीतियों में कोई फर्क नहीं है? अमेरिका और यूरोप में इन नीतियों को अपनाने के बाद क्या हुआ? वर्ष 2007-2008 में यूरोप और अमेरिका में मंदी आई और इसने पूरी अर्थव्यवस्था को और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया. लेहमन ब्रदर्स बैंक बैंकरप्ट (दीवालिया) हो गया. जे.पी मॉर्गन को बैंक होल्डिंग कंपनी बनकर सरकार के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा, जिस पर दुनिया को बड़ा नाज था. यूरोप का इससे भी बुरा हाल हुआ. यूनान, आइसलैंड, पुर्तगाल, स्पेन सब मंदी और बेरोज़गारी के शिकार हो गए और ब्रिटेन को रेलवे का डि-नेशनलाइजेशन करना पड़ा. ठीक वैसे ही हमारे रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने पर लगे हुए हैं. हमारा सारा टेलीकम्युनिकेशन घाटे में चला गया और जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके दाम दिन दूने, रात चौगुने बढ़ गए हैं, टेलीकम्युनिकेशन को प्राइवेट सेक्टर में लाना पड़ा. न्यूजीलैंड में सिविल एविएशन को दोबारा नेशलाइज करना पड़ा. रेलवे का भी राष्ट्रीयकरण करना पड़ा और अमेरिका ने सारे मेडिकेयर को प्राइवेट सेक्टर में भेजने से मना कर दिया. ब्रिटेन में रेलवे का नेशनलाइजेशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन का हो गया और उसे पब्लिक सेक्टर में ले आए. अमेरिका में वर्कर्स कोऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं. यह तो यूरोप और अमेरिका की हालत है, जो हमारे आदर्श बने हुए हैं.

आजकल भारत में पांच-छह शब्द प्रचलन में हैं, चमकता भारत, दमकता भारत, इंडिया एक उदीयमान शक्ति, इंडिया राइजिंग आदि. मैं भी 2004 में एनडीए की तरफ से फील गुड इंडिया का कैंडिडेट बनकर मेरठ गया था और पराजित होकर

आया था. इस समय भारत की स्थिति सहारा रेगिस्तान के मुल्कों से भी ज्यादा बुरी है, लेकिन चमकते दाम, चमकता भारत अलग है. 20 करोड़ लोगों की हालत सहारा रेगिस्तान के लोगों से भी बुरी है. भारत में कम उम्र के 45 प्रतिशत बच्चे मानक वजन से कम वजन के हैं, 80 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, लेकिन वे एनपीए वालों के बच्चे नहीं हैं. ऐसे शब्द के इस्तेमाल के लिए माफी चाहता हूं. 80 प्रतिशत बच्चों में खून की कमी है, ये एनपीए वालों के बच्चे नहीं हैं, मैं दोबारा दोहराता हूं, लेकिन चमचमाते मॉल, निजी स्कूल, निजी कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्राइवेट चमकते अस्पताल, एमसीआर के अस्पताल और मुंबई के अस्पताल, नर्सिंग होम, नए पांच सितारा होटल्स, यह वाइब्रेंट भारत नहीं है. 93 प्रतिशत भारतीय अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में और देहातों में बेरोजगारी पहले के मुक़ाबले 20 प्रतिशत अधिक बढ़ गई है.

अर्जुनसेन गुप्ता केमटी रिपोर्ट के मुताबिक देश के 96 करोड़ लोग 20 रुपये से भी कम में गुजारा कर रहे हैं. काफी बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है. मुझे राजनीतिक कार्यक्रमों के तहत कई बार जेल जाने का मौका मिला. जेल मैन्युल के मुताबिक मुझे जो खाना मिलता था, हिंदुस्तान की एक तिहाई आबादी उससे भी खराब खाना खाकर गुजारा करती है. साल 2000 में भारत के 20 प्रतिशत लोगों का राष्ट्रीय कमाई में हिस्सा 45 प्रतिशत था और 20 प्रतिशत का सिर्फ एक प्रतिशत.

मैं कृषि के सवाल पर आना चाहता हूं. चूंकि दुर्भाग्य है कि हम गांव में किसान के घर में पैदा हुए. जो गमलों में खेती करने वाले लोग हैं, वे हमें कृषि उत्पादन के बारे में बता रहे हैं. हमारा इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? पिछले दिनों सरकारी कर्मचारियों का वेतन 150 से लेकर 165 प्रतिशत तक बढ़ा है और कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले लोगों का वेतन 150 से 170 प्रतिशत तक बढ़ा है. सातवें वित्त आयोग के बाद एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 18000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे और किसानों को उनकी पैदावार की मिलने वाली कीमत क्या है?

मैं पैरिटी प्राइस का एक फॉर्मूला बताता हूं. 1970 में गेहूं का मूल्य 76 रुपये प्रति क्विंटल था. मैं चाहता हूं कि इस पर सदन के सभी सदस्य ध्यान दें कि गेहूं का मूल्य 2016 में 1450 रुपये हो गया, यानी 45 वर्षों में 19 गुना ज्यादा हो गया. ऊपर जो मैंने वृद्धि बताई वो 300 गुना है और गेहूं के दाम में वृद्धि 19 गुना. इसलिए, मेरा यह कहना है कि अगर हमारा मूल्य भी 100 गुना बढ़ा दो, तो हमारा गेहूं भी 7600 रुपये क्विंटल के हिसाब हो जाएगा. जब और क्षेत्रों में इतनी बढ़ोत्तरी हो सकती है, तो इस क्षेत्र में इतनी बढ़ोत्तरी क्यों नहीं हो सकती?

डॉ. मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि अब बदलाव का वक्त आ गया है. मेरा यह निवेदन है कि अब वक्त आ गया है कि 25 वर्षों में हमने जो नेहरूवियन मॉडल छोड़ा, जो हमने दीनदयाल का अंत्योदय छोड़ा, क्या उसके बाद चमकता, सुनहरा भारत बना? यदि हां, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आप कहेंगे कि विपक्षी दल राष्ट्र के विकास में बाधक हैं. आपका मन खराब है, हम बाधक नहीं हैं. आप कुछ और भी लाइए, हम उसका भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन यह जो रास्ता है, यह पंडित दीनदयाल जी का रास्ता नहीं है. यह रास्ता जो उन्होंने अपनाया था, यह रास्ता भी पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के नियोजन का रास्ता नहीं था. यह रास्ता रीगन का है, थैचर का है. जिनकी वजह से रूस, अमेरिका बर्बाद हुआ, यूरोप की मंदी आई और यूरोप की मंदी की यह हालत हुई कि इस आधार पर कई मुल्कों में सरकारें बदल गईं.

इस देश के अंदर पूजा-अर्चना के 25 लाख स्थल हैं. मेरा घर एक सनातनी हिंदू का घर है. कुछ लोग आर्यसमाजी हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यहां पर 15 लाख स्कूल भी हैं. पूजा के स्थान 25 लाख, पर स्कूल सिर्फ 15 लाख हैं. मैंने विवेकानंद जी को पढ़ा है. उन्होंने कहा था कि, ये भगवे कपड़े छोड़ो, आदिवासी मोहल्ले में जाओ और जाकर उनके बच्चों को पढ़ाओ, इससे अच्छा धर्म कोई नहीं. लेकिन उसको तो हम अपनाते ही नहीं हैं. पूजा अर्चना के स्थल 25 लाख, अस्पताल 75 हजार और स्कूल 15 लाख हैं.

मैं कहना चाहता हूं कि 2010 में 30 लाख एनजीओज कार्यरत थे, यानी कि हर 400 लोगों की छाती पर एक एनजीओ काम कर रहा था. लेकिन लूटपाट के अलावा कुछ नहीं हुआ. उसमें कई तरह के रैकेट्स पकड़े गए. मैं कांग्रेस पार्टी के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि आप थोड़ी हमारी भी मानिए. पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की नीतियों की वजह से ही आप यहां आए थे, इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण किया था. पिछली सरकार में अगर ये वामपंथी न होते-जो यूपीए टूटी थी, तो हिंदुस्तान का हाल भी अमेरिका जैसा होता. जो बचत हुई, वह इन वामपंथियों ने आपकी सरकार से करवाई. आपके यहां तो कुछ लोग मनरेगा भी लागू नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए ये जो नई आर्थिक नीतियां हैं, ये अब अनप्रोडक्टिव हो गई हैं.

कैपिटलिज्म का एक दौर होता है, उसके विकास के भी मायने होते हैं. जब पूंजीवाद आता है, तो कुछ क्षेत्रों में जरूर कुछ अच्छे-अच्छे काम होते हैं, लेकिन यह पूंजीवाद का विकसित नहीं, विकृत रूप है, इसलिए इतनी असमानता है. डॉ मनमोहन सिंह जी के टाइम में मैक्सिम 9.3 परसेंट जीडीपी थी. मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि उस समय देश में सबसे ज्यादा असमानता थी. 125 जिलों में नक्सलाइट्स आपकी तलाश में घूम रहे हैं. गरीबी और अमीरी के बीच की दूरी आपकी आर्थिक नीतियों से बढ़ेगी. गरीब कुछ दिन तक तो भूखा मरेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि भूख और हथियार के बीच में से जब उसे एक चीज उठानी पड़ेगी, तो वह हथियार उठाएगा. इतिहास में ऐसे मौके यहां आए हैं और कई मुल्कों में भी आए हैं, इसीलिए मैं एक बार चाहता हूं कि इन आर्थिक नीतियों पर नए तरीके से, दोबारा बैठकर विचार हो. पच्चीस साल पहले नई आर्थिक नीतियों को अपनाने का वक्त आया था, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इनको हटाने का वक्त है. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

विपक्ष का कमजोर होना लोकतंत्र के लिए चिंताजनक

पांच राज्यों के चुनाव परिणाम हमारे सामने हैं और इसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत उत्साहित किया है. भारतीय जनता पार्टी और सभी टेलीविजन चैनल यह कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ है और आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर नतीजे दिखाएगी.

भारतीय जनता पार्टी को खुशी है, इसका स्वागत करना चाहिए. लेकिन, यह स्वागत सवाल खड़े करता है. देश में जितने भी समझदार लोग असम गए थे, मैं खुद असम गया था, उनमें से कोई यह नहीं कह रहा था कि कांग्रेस वापसी करेगी. कांग्रेस को सबसे ज्यादा 40 से 45 सीटें मिलने का अनुमान था और उसे बदरुद्दीन अजमल के सहयोग से सरकार बनानी पड़ सकती है, इसका अंदेशा था. जब मैं असम गया था तब मुझे यह साफ नज़र आ रहा था कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूती के साथ जीतेगी और अगर उसने अपने साथ प्रफुल्ल मोहंता और बोडो को मिला लिया तो उसकी जीत निश्चित है. इसके पीछे मेरा आकलन यह था कि जितनी भी हिल काउंसिल हैं, वह सब आदिवासियों से जुड़ी हुई हैं और वे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं.

इससे भी ज्यादा मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मुस्लिम नौजवान खुलेआम मुझसे कह रहे थे कि कांग्रेस चोर है, हमारे विकास के लिए जितना पैसा आता है, उसे कांग्रेस खा जाती है, असम में विकास नहीं हुआ और तरुण गोगोई चोरों के सरदार हैं. यह शब्द मैंने अपने कानों से सुने और मैंने जब इनका विश्लेषण किया और जानकारी हासिल की तो यह पता चला कि वहां पर पचास साल से ऊपर के लोग तो बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस की बात कर रहे थे, लेकिन जो नौजवान तबका था, वह भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा था. उसे लग रहा था कि कांग्रेस का विकल्प भारतीय जनता पार्टी ही है. तीसरी पार्टी वहां प्रफुल्ल मोहंता की थी, लेकिन प्रफुल्ल मोहंता 15 सालों से सत्ता से बाहर हैं. हालांकि वह दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी पार्टी ने ही उन्हें किनारे कर दिया है. संकेत साफ थे कि भारतीय जनता पार्टी असम में चुनाव जीतेगी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस दिवःस्वप्न में रही और उसने सबसे पहले मुख्यमंत्री पद के लिए तरुण गोगोई का नाम घोषित कर दिया. इसके पीछे रहस्य यह था कि तरुण गोगोई ने केंद्रीय नेतृत्व को धमकी दी थी कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया तो वह क्षेत्रीय दल बनाकर चुनाव लड़ेंगे. कांग्रेस इससे डर गई. यह घटना पहले भी एक राज्य में दोहराई जा चुकी है जहां पर कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के लिए वही उम्मीदवार चुनना पड़ा जिसने कहा था कि वह अलग क्षेत्रीय दल बना लेंगे. कांग्रेस असम में प्रफुल्ल मोहंता से भी संपर्क नहीं कर पाई बल्कि वह इस भ्रम में थी कि उसका बहुमत आएगा, इसलिए किसी से गठबंधन की क्या जरूरत है और यहीं पर भाजपा कांग्रेस से बाजी मार गई. भाजपा के ऊपर न भ्रष्टाचार का आरोप था, भाजपा के ऊपर न किसी और तरह का आरोप था. मुख्यमंत्री पद के लिए नौजवान चेहरा था. उसने मुस्लिम वोटरों को अपने साथ लाने के लिए कोई कोशिश भी नहीं की. इसके बावजूद मुस्लिम वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया. जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रफुल्ल मोहंता को अपना सहयोगी बना लिया तो असम की जीत में कोई संदेह रहा ही नहीं.

लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की यह ख़ुशफ़हमी कि उसने असम में, केरल में खाता खोल लिया है, यह शायद ज्यादा बड़ी खुशफ़हमी है क्योंकि इस तरह के खाते तो निर्दलीय कहीं भी खोल लेते हैं. भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव एक सीख है. चुनाव से हफ्ते भर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों की क्लास ली थी और उन्हें डांटा था. सख्ती से समझाया था कि वे लोगों के पास जाएं और लोगों को सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में समझाएं. इसकी जड़ में भारत सरकार द्वारा कराया हुआ एक सर्वे है, जो यह कहता है कि भारत सरकार के प्रमुख छह या सात मंत्रालय कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं या ऐसे काम कर रहे हैं जिससे जनता खुश नहीं है. भारतीय जनता पार्टी को लोगों की आशाओं पर खरा उतरना पड़ेगा और अपनी जीत को एक ऐसी जीत के रूप में लोगों को दिखाना जो न भूतो न भविष्यति की परिभाषा के दायरे में आती हो उसके खुद के लिए नुकसान दायक होगा. ये चुनाव कांग्रेस को एक सीख देते हैं कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस में कोई प्राण फूंक सकते हैं? इन पांच राज्यों के चुनावों ने यह सवाल बहुत विशाल बना दिया है. कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है. चुनाव हारने के बाद विश्लेषण होता है. एक कमेटी बनती है. जो रिपोर्ट देती है, लेकिन उस रिपोर्ट के ऊपर कभी अमल नहीं होता. शायद इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हैं और अब कार्यकर्ताओं की जगह वह नव-धनाढ्य या ठेकेदार आ गए हैं जो किसी भी तरह राजनीति में चुनाव लड़कर अपने को, अपने क्षेत्र में राजनीतिक व्यक्ति घोषित करना चाहते हैं. कांग्रेस जीतती है तो सेहरा राहुल गांधी के सिर जाता है, हारती है तो वह सामूहिक हार होती है. यही बात इस चुनाव में भी कही जा रही है. कांग्रेस का यह अपना मामला है कि वह किसे अपना अध्यक्ष बनाए या किसे न बनाए, लेकिन कांग्रेस अगर राजनीतिक परिदृश्य से हटेगी या कमजोर होगी तो यह देश के लोकतंत्र के लिए थोड़ी चिंताजनक बात होगी, क्योंकि लोकतंत्र में सत्तापक्ष के मुक़ाबले विपक्ष भले ही कमजोर हो लेकिन विपक्ष होना चाहिए, पर ऐसा विपक्ष भी अपनी साख खो देता है जो जनता से जुड़े सवाल नहीं उठाए और उन सवालों को देश का सवाल बनाने की कोशिश करे जिन सवालों को सत्ताधारी दल सवाल बनाने में रुचि दिखाता है. हमारे देश की आज यही हालत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुनः यह आशा करनी चाहिए कि इन चुनावों के संकेत को ध्यान में रखकर उन्हें कुछ ऐसी कारगर योजनाएं बनानी चाहिए ताकि देश के लोगों को यह लगे कि उन्होंने जिसे वोट दिया वह निरर्थक नहीं, सार्थक था.■

> मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मुस्लिम नौजवान खुलेआम मुझसे कह रहे थे कि कांग्रेस चोर है, हमारे विकास के लिए जितना पैसा आता है, उसे कांग्रेस खा जाती है, असम में विकास नहीं हुआ और तरुण गोगोई चोरों के सरदार हैं. यह शब्द मैंने अपने कानों से सुने और मैंने जब इनका विश्लेषण किया और जानकारी हासिल की तो यह पता चला कि वहां पर पचास साल से ऊपर के लोग तो बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस की बात कर रहे थे, लेकिन जो नौजवान तबका था, वह भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा था. उसे लग रहा था कि कांग्रेस का विकल्प भारतीय जनता पार्टी ही है.

editor@chauthiduniya.com

डिग्री में क्या रखा है!

मेघनाद देसाई

आखिरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चली छह हफ़्तों की लड़ाई के बाद उत्तराखंड का झगड़ा समाप्त हो गया. इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित किया कि दोष संविधान में नहीं बल्कि देश में चलने वाली राजनीतिक प्रक्रिया में है. राजनितिक दलों के बीच पिछले दो वर्षों जैसी खटास पैदा हुई उसकी मिसाल भारतीय राजनीति में पहले कभी देखने को नहीं मिली है.

जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे, तब वहां अनगिनत लोगों, खास तौर पर टी पार्टी ग्रुप्स के लोगों को एक अश्वेत व्यक्ति का राष्ट्रपति बन जाना हज़म नहीं हो रहा था. लिहाज़ा अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति के जन्म प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता पर संदेह ज़ाहिर किया गया. ओबामा के बर्थ सर्टिफिकेट पर संदेह करने वाले डोनाल्ड ट्रम्प और दूसरे लोगों ने यह दावा करना शुरू किया कि ओबामा मूल अमेरिकी नहीं हैं उनका जन्म अमेरिका से बाहर हुआ है. दरअसल यह क़ानून की चाशनी में लिपटा हुआ एक रंगभेदी विचार था.

यही बात नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में भी कही जा सकती है. उनसे पहले किसी ने भी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की डिग्री पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पुराने संभ्रांत वर्ग के लिए मोदी नीचे से उठे हुए व्यक्ति हैं. उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है कि कैसे एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है और प्रधानमंत्री बन सकता है? दून स्कूल, सेंट स्टीफेंस और कैंब्रिज के ग्रेजुएट एक ओबीसी के देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच जाने से हैरान हैं, इसलिए उन्होंने उनकी डिग्री की वैधता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है.

यह रवैया भारत के लिए नया नहीं है. महादेव देसाई ने अपनी डायरी में यह लिखा है कि गांधी जी सोचते थे कि अंबेडकर जरूर ब्राह्मण होंगे क्योंकि वह बहुत अधिक शिक्षित थे. महादेव देसाई ने गांधीजी की ग़लतफहमी दूर की लेकिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि ऐसा लगता है कि अंबेडकर को हिंदुत्व से कोई सरोकार नहीं है.

> जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे, तब वहां अनगिनत लोगों, ख़ास तौर पर टी पार्टी ग्रुप्स के लोगों को एक अश्वेत व्यक्ति का राष्ट्रपति बन जाना हज़म नहीं हो रहा था. लिहाज़ा अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति के जन्म प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता पर संदेह ज़ाहिर किया गया. ओबामा के बर्थ सर्टिफिकेट पर संदेह करने वाले डोनाल्ड ट्रम्प और दूसरे लोगों ने यह दावा करना शुरू किया कि ओबामा मूल अमेरिकी नहीं हैं उनका जन्म अमेरिका से बाहर हुआ है. दरअसल यह क़ानून की चाशनी में लिपटा हुआ एक रंगभेदी विचार था.यही बात नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में भी कही जा सकती है. उनसे पहले किसी ने भी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की डिग्री पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था.

वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज की मानसिकता इस तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रसित है. यहां तक कि अरविन्द केजरीवाल, जो निचले तबके की बात करते हैं, को भी राजनीति से अलग मोदी से परेशानी है. ओबामा की तरह मोदी के मामले में भी यहां के भद्र लोगों कोई साक्ष संतुष्ट नहीं कर सकता.

लेकिन इसका एक और पहलू है जिसमें परिवार (संघ परिवार) को सोनिया गांधी के प्रति द्वेष की भावना है. जिसे समझना मुश्किल है. जब सोनिया गांधी दुलहन बनकर दिल्ली के लुटियंस जोन में आईं तो वहां के वासीयों ने अपने अहंकार में उन्हें एक सेकुलर प्रिंस की प्रिंसेस बनने योग्य भी नहीं माना था, लेकिन वह दौर भी बीत गया.

जब उन्होंने ने वंश के वरिष्ठ सदस्य के रूप में कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाली तो पार्टी के दूसरे लोगों में गुस्सा फैल गया. जब उन्होंने एनडीए को पराजित किया और जब क़ानूनी तौर पर वह सत्ता में आ सकती थीं तो भाजपा की एक वरिष्ठ महिला नेता द्वारा सिर मुंडवाने और आमरण अनशन पर बैठने की अलोकतांत्रिक धमकी दी गई. हालांकि बाद में वह धमकी उनके लिए सेल्फ-गोल साबित हुई. सोनिया ने बड़ी चालाकी से इस दांव को उल्टा उन्हीं के ऊपर फेंक दिया. सोनिया को इस कुर्बानी के लिए खूब वाह-वाही मिली और बिना पद लिए वह सत्ता पर क़ाबिज़ रहीं. सोनिया गांधी के प्रति इस लगातार द्वेष की भावना ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया. दरअसल यह भी एक तरह का नस्लवाद था जिसमें लैंगिक भेदभाव का पूर्वाग्रह भी शामिल था.

मोदी के एक पिछड़े वर्ग से ऊपर उठने और सोनिया के इटली से संबंधित होने के प्रति उनके विरोधियों की दुर्भावना एक दूसरे से मेल खाती है. यह दोनों दुर्भावनाएं संसद के विभाजन का कारण बन रही हैं और इससे देश की जनता का नुकसान हो रहा है. संसद के कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल न तो सबसे वरिष्ठ सदस्य रख रहे हैं और न ही सबसे जूनियर सदस्य. ऐसा लगता है कि कोई भी लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की बात नहीं सुन रहा है. भारतीय लोकतंत्र अपने मतदाताओं के कारण एक आला दर्जे का लोकतंत्र है. लेकिन संसदीय राजनीति खंडित हो चुकी है जिसे दुरुस्त करना बहुत ही मुश्किल है और आगे के खतरे साफ़ दिखाई दे रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड में भीषण जल संकट

पानी के लिए मारामारी

भीषण जल संकट की वजह से पलामू जिला अकाल के करीब है. इंसान तो पानी के बगैर मर ही रहे हैं जानवरों को भी राहत नहीं है. इस भीषण जल संकट की वजह से गिरिडीह जिले के पूर्णा नगर पंचायत निवासी 26 वर्षीय दिलीप यादव ने कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली. दिलीप यादव ने अपने कुएं में बोरिंग कराने के लिए 95 हजार रुपये कर्ज लिए थे. लेकिन बोरिंग के बावजूद भी पानी नहीं निकल पाया जिससे हताश होकर उन्होंने अपनी जान दे दी.

शैलेंद्र चौहान

देश के दूसरे हिस्से की तरह झारखंड में भी पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पानी के भीषण संकट को देखते हुए सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि जितनी जल्द हो सके जल संकट को दूर किया जाए, लेकिन स्थिति को देखकर नहीं लगता है कि इतनी जल्द पानी का संकट दूर होने वाला है. हाल यह है कि रामगढ़ के विधायक और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी के क्षेत्र के लोग भी पानी के बगैर तड़प रहे हैं. सरकारी तंत्र के अधिकारियों के बीच तालमेल

की कमी और उनकी न काम करने की प्रवृत्ति इस भीषण जल संकट की प्रमुख वजह है. भीषण जल संकट की वजह से पलामू जिला अकाल के करीब है. इंसान तो पानी के बगैर मर ही रहे हैं जानवरों को भी राहत नहीं है. इस भीषण जल संकट की वजह से गिरिडीह जिले के पूर्णा नगर पंचायत निवासी 26 वर्षीय दिलीप यादव ने कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली. दिलीप यादव ने अपने कुएं में बोरिंग कराने के लिए 95 हजार रुपये कर्ज लिए थे. लेकिन बोरिंग के बावजूद भी पानी नहीं निकल पाया जिससे हताश होकर उन्होंने अपनी जान दे दी. इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया. इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे झारखंड में पानी की स्थिति क्या है? कई जिलों में जल के भीषण संकट को देखते हुए परिवार में होने वाली शादी तक के कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है. अगर किसी के घर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, तो श्राद्धकर्म के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है. ऐसा ही एक मामला बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड के भोक्की गांव के प्रखंड कमेटी के महासचिव संटुलाल महथा के निधन के बाद देखने को मिला, क्योंकि उनके श्राद्धकर्म के लिए कहीं से मात्र एक बाल्टी पानी ही मिल पाया.

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा के गांव सुंदरपुर में पानी की भीषण संकट की वजह से यहां के निवासियों ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. उन्होंने प्रधानमंत्री से पानी की भीषण संकट से जल्द निजात दिलाने की मांग की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जयंत सिन्हा ने खुद संज्ञान लेकर बीडीओ को फोन कर तुरंत पानी की व्यवस्था करने का आदेश दिया. काश अगर ऐसी व्यवस्था मंत्री जी पूरे झारखंड के लिए करवाते, क्योंकि मंत्री जी के गांव ही नहीं पूरे राज्य में पानी का भीषण संकट है. पूर्वी सिंहभूमि में जलश्रोतों के सुख जाने की वजह से चेकाम पहाड़ी पर एक हाथी का बच्चा प्यास से तड़पकर मर गया. पटमदा के दलमा वन में जलशाय सुख जाने के कारण दो हिरण के बच्चों के प्यास की वजह से मौत हो गई. पानी के तलाश में भटक रहे गढ़वा के केतार गांव में तेंदुए की कुएं में कुदने से मौत हो गई. मैथन चेक पोस्ट पर तस्करी के लिए ले जाई जा रहीं 371 गायों को पकड़ा गया था, जिसमें से 30 गायें प्यास की वजह से मर गईं. गोड्डा जिले में एक जंगली लगड़बग्घा पानी की तलाश में घर के अंदर घुस गया. झारखंड में पानी की भयावहता का अंदाजा इसी लगाया जा सकता है कि राज्य की 197 नदियों में से 133 नदियों का पानी पूरी तरह सुख चुका है. उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की सबसे बड़ी नदी दामोदर एवं संताल परगना की गंगा नदी में भी पानी कम हो गया है. अगर जिलेवार नदियों की हालत पर नजर डाली जाए, तो स्थिति काफी गंभीर नजर आती है. रांची में दो नदियां हैं और दोनों सुख चुकी हैं, साहेबगंज में दो नदियां है, लेकिन इसमें एक सुख चुकी है. लोहरदगा में दो नदियों में से एक सुख चुकी है. धनबाद में सात नदियां हैं, देवघर में छः नदियां हैं और सभी चुकी हैं. पूर्वी सिंहभूमि में नौ में से आठ, जमताड़ में दो में से एक नदी सुख चुकी है. गिरडीह में केवल एक नदी है वो भी पूरी तरह सुख चुकी है. दुमका में पांच नदियां हैं और पांचो सुख चुकी हैं. पाकुड़ में चार नदी है और उसमें से तीन सुख चुकी हैं. गोड्डा में 8 नदी हैं, लेकिन इसमें से सात सुख चुकी हैं. चतरा में 17 नदियां हैं और सभी सुख चुकी हैं. कोडरमा में 32 नदियां और सभी सुख चुकी हैं. हजारीबाग में 11 में से दस नदियां सुख चुकी हैं. इसी तरह रामगढ में 15 में से 12, लातेहार में सात में से सातों, गढ़वा में 19 में से 14, पलामु में 4 में से 4 और खुंटी में तीन नदियां हैं और तीनों सुख चुकी हैं. झारखंड हाईकोर्ट के बाद राज्य सरकार भी मानती है कि झारखंड में जलसंकट की समस्या अति गंभीर है. स्थिति यह है कि पानी के लिए पूरे राज्य में युद्ध जैसी स्थिति हो गई है. प्रत्येक जिले, प्रखंड, पंचायत, गांव और नगर निगम क्षेत्रों में पानी के लिए मारपीट की संगीन घटनाएं घट रही हैं और मामला थाने में भी दर्ज हो रहा है. झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयु राय ने तो यहां तक कह दिया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी सिर्फ बरगला-ने का काम करते हैं. जिस भी जिले में पानी के मद में जितनी भी योजनाएं पास हुई हैं, उसमें से एक भी धरातल पर दिखाई नहीं देती हैं. सरयु राय तीन जिलों के प्रभारी मंत्री हैं. उन्होंने हजारीबाग, रामगढ़ एवं लातेहार के दौरे के दौरान पाया कि पिछले वर्ष जितनी भी योजनाएं लागू की गईं थीं किसी पर भी ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है. जबकि रामगढ़ के विधायक चंद्रप्रकाश चौधरी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं, लेकिन बावजूद इसके रामगढ़ क्षेत्र के लोग पानी के बगैर तड़प रहे हैं.

अब अगर मंत्री महोदय के क्षेत्र का ही यह हाल है, तो पूरे झारखंड के हालात का आकलन आसानी से किया जा सकता है. कई जिलों में लोगों का गुस्सा सामने आ चुका है और अगर अब भी हालात नहीं सुधरे, तो स्थिति भयावह हो सकती है.■

feedback@chauthiduniya.com

न गाड़ी हैं और न पानी

कोसी की अग्निशमन व्यवस्था भगवान भरोसे है

राजेश सिन्हा

बिहार के लगभग सबसे अधिक पिछड़े इलाकों में शुमार कोसी अर्थात सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया गर्मी का मौसम आते ही आग में जलने लगता है. प्रत्येक वर्ष न केवल दर्जनों लोगों के आशियाने आग के भेंट चढ़ जाते हैं, बल्कि कई लोगों की आग में झुलसकर मौत भी हो जाती है. घटना घटित हो जाने के बाद प्रशासनिक अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचते हैं और जांच पड़ताल के बाद अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं. राहत के नाम पर प्रभावित परिवारों के हाथों में मुट्ठी भर अनाज और चंद रुपये थमा दिए जाते हैं. इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि सात नदियों से घिरे इस इलाके के लोग कहीं भी आग लग जाती है, तो पानी के लिए तरस जाते हैं.

अग्निशमन विभाग की व्यवस्था से दहशतजदा लोगों का कहना है कि अगर कभी भीषण आग लगने की घटना घटी, तो पूरा खगड़िया जलकर खाक हो सकता है. यहां के भौगोलिक बनावट की वजह से वैसे भी इस इलाके के लोग अपने गंतव्य तक समय पर नहीं पहुंच पाते हैं. अग्निकांड की घटना होने पर आग पर काबू पाने वाला विभाग भी बौना पड़ जाता है. ऐसा इसलिए, क्योंकि खगड़िया का अग्निशमन विभाग भगवान भरोसे चल रहा है. विभाग के पास न ही पर्याप्त मात्रा में दमकल गाड़िया हैं और न ही पर्याप्त कर्मचारी. लेकिन इसके बावजूद इसके पूरे जिले के लोगों को अग्निकांड से बचाने का भरपूर दावा किया जाता है. पिछले वर्ष भी प्रशासनिक पदाधिकारी दुरुस्त अग्निशमन व्यवस्था का ढोल पिटते रहे, लेकिन दर्जनों बस्तियां जलकर राख हो गईं. लाखों रुपये की बर्बादी तो हुई ही और साथ ही व्यापक पैमाने पर जान-माल की भी क्षति हुई. दमकल की गाड़िया या तो पहुंची ही नहीं और अगर पहुंची भी तो तब तक गांव के गांव जलकर राख हो चुके थे.

अग्निकांड की घटना के समय दमकल की गाड़ियों में दरअसल पानी का खत्म हो गया था. विभागीय अधिकारी से जब बात की गई, तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जिले में महज एक ही पानी टंकी की वजह से पानी की कमी रहती है. लेकिन बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है. नतीजतन आज भी अग्निशमन विभाग का हाल खराब है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आग पर काबू पाने के लिए प्रर्याप्त पानी की व्यवस्था भी समय पर नहीं हो पाती है. जब तक विभाग के कर्मचारी पानी की व्यवस्था कर पाने में सफल हो पाते हैं, तब तक बस्तियां जलकर खाक हो जाती हैं. बार-बार मिल रही शिकायत की सत्यता के लिए चौथी दुनिया के द्वारा विभागीय व्यवस्था का मुआयना किया गया. शहर से लगभग दो किलोमीटर दूर बाजार समिति प्रांगण में ''फायर स्टेशन खगड़िया'' का बोर्ड लगा था और कार्यालय के बाहर एक छोटी अग्निशमन गाड़ी सहित तीन दमकल की गाड़ियां लगी थीं. दमकल गाड़ियों की हालत के संदर्भ में पूछे जाने पर बताया गया कि तीन वाहनों में से दो बेहतर स्थिति में है जबकि एक वाहन खराब पड़ा है. अधिक जर्जरता की वजह से वाहन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वर्ष 1991 में स्थापित इस अग्निशमन विभाग के लिए अपना कार्यालय भवन भी नहीं है. टूटे-फूटे कमरे में संचालित कार्यालय भवन की हालत इतनी खराब पड़ी है कि रात्रि में विश्राम करना भी कार्यालय प्रभारी सहित अन्य कर्मियों के लिए मुश्किल हो जाता है. ऐसी स्थिति में विभागीय कर्मचारियों को चौबीस घंटे चौकस रहने की हिदायत देना कर्मियों के गाल पर करारा तमाचा ही है.

कई माह से वेतन के लिए लालायित कर्मचारियों का कहना था कि भूखे पेट ही सही सभी विभागीय कर्मी आग पर काबू पाने के मामले में पीछे नहीं हटते. लेकिन बिना पानी के आग पर काबू पाना कितनी टेढ़ी खीर है, यह बताने की शायद कोई आवश्यकता नहीं है. कार्यालय प्रभारी आरएन रजक ने बताया कि महज दो दमकल गाड़ियों के दम पर दो अनुमंडल और सात प्रखंड के लोगों को आग से होने वाली जान-माल की क्षति से बचाना कितना संभव है! वैसे भी सृजित पद के अनुसार कर्मियों की नियुक्ति नहीं होने की वजह से चार गृह रक्षकों से सहयोग लिया जा रहा है. इन

प्रशिक्षित जवानों को जब तक थोड़ा बहुत प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है तब तक इनका स्थानांतरण हो जाता है. उन्होंने कहा कि सबसे अधिक कठिनाई तब आती है जब आवश्यकता के समय पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है. खगड़िया शहर में एक ही पानी की टंकी है और इसका नल हमेशा खराब ही रहता है. बीते लगभग एक माह से शहर की पानी टंकी का नल खराब पड़ा था. संबंधित विभाग के अधिकारी से जब नल ठीक कराने की गुहार लगाई गई, तो उन्होंने कहा कि विभाग को इसके लिए लिखा गया है, राशि आवंटित होते ही नल ठीक करा दिया जाएगा.

हालांकि जब इस बात की जानकारी नवपदस्थापित जिलाधिकारी को मिली तो उन्होंने त्वरित गति से इसे ठीक कराया. कार्यालय प्रभारी रजक का कहना था कि अगर जिले को अग्निदेव के कोप से सुरक्षित रखना है, तो सर्वप्रथम वाहनों की संख्या में इजाफा करते हुए जगह-जगह पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए. अगर संभव हो तो कार्यालय परिसर में ही पानी की टंकी की व्यवस्था की जाए, ताकि जब भी जरूरत पड़े पानी की व्यवस्था हो जाए. बहरहाल, गर्मी के मौसम में पछुआ हवा को देखते हुए प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा अग्निशमन व्यवस्था में सुधार किया जाएगा या नहीं, यह तो प्रशासनिक पदाधिकारी ही जानें. लेकिन इतना तय है कि इस वर्ष भी अग्निशमन व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो अन्य वर्ष की तरह इस वर्ष भी कई परिवार के लोग न केवल आशियाना गंवाने के लिए मजबूर होंगे, बल्कि कई परिवार के लोग अपनों को खोने के गम में आंसू बहाते रह जाएंगे.■

www.iiher.org,
Mob. : 9386745004, 9204791696
Email : anilsulabh6@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH
Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.
(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)
AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

POST GRADUATE COURSES :

Name of Courses		Eligibility	Duration
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.
DEGREE COURSES			
BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.
1 YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT			
DIPLOMA COURSES :			
DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate in Medical Dersing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN

Form & Prospectus -
Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/- only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डॉ. अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख

कागज पर सर्जरी

करोड़ों का फर्जीवाड़ा

आपराधिक घटनाएं कभी सरकार के माथे का कलंक बन जाती हैं, तो कभी घोटालों को लेकर नीतीश सरकार कटघरे में खड़ी नजर आती है. पत्रकार राजदेव रंजन की निर्मम हत्या के बाद से खराब कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है, तो बिहार ''कोख''(गर्भाशय का ऑपरेशन) के नाम पर हुए फर्जीवाड़े से भी दागदार हो रहा है. हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि किसी एक जिले में ''कोख'' के नाम पर हुई लूट की कहानी ठंडी भी नहीं पड़ती है कि किसी दूसरे जिले का मामला सड़कों पर जुगाली करने लगता है.

राजेश सिन्हा

नीतीश सरकार विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नायाब कार्यों को अमलीजामा पहनाने के साथ-साथ पूर्ण शराबबंदी सख्ती के साथ लागू कर सुर्खियां बटोर रही है. लेकिन घपले-घोटालों और कानून व्यवस्था को लेकर बिहार अक्सर कलंकित होता जा रहा है. बढ़ती आपराधिक घटनाएं कभी सरकार के माथे का कलंक बन जाती हैं, तो कभी घोटालों को लेकर नीतीश सरकार कटघरे में खड़ी नजर आती है. पत्रकार राजदेव रंजन की निर्मम हत्या के बाद से खराब कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है, तो बिहार ''कोख''(गर्भाशय का ऑपरेशन) के नाम पर हुए फर्जीवाड़े से भी दागदार हो रहा है. हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि किसी एक जिले में ''कोख'' के नाम पर हुई लूट की कहानी ठंडी भी नहीं पड़ती है कि किसी दूसरे जिले का मामला सड़कों पर जुगाली करने लगता है. पुर्णियां, बेगूसराय, कटिहार और सहरसा के साथ-साथ कुछ अन्य जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मिलने वाली मुफ्त स्वास्थ्य योजना के नाम पर हुई लूट की जांच अभी गति भी नहीं पकड़ पाई थी कि सुपौल, समस्तीपुर एवं मधेपुरा सहित कुछ अन्य जगहों पर ''कोख'' के नाम पर सरकार को चूना लगाए जाने का मामला गरम होने लगा है. यह बात अलग है कि लगभग सभी जिले के सिविल सर्जन एसीएमओ के मत्थे दोष मढ़कर अपने दागदार दिख रहे दामन को बचाने की कोशिश में लगे हैं, जबकि एसीएमओ लेबर डिपार्टमेंट के माथे ठीकरा फोड़ने की ताक में है.

''कोख'' के नाम पर सरकार को चूना लगाए जाने के मामले में गुनहगार कौन-कौन लोग हैं, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. लेकिन जानकारों का कहना है कि गर्भाशय सहित अन्य तरह की सर्जरी के नाम पर हुए फर्जीवाड़े में निजी नर्सिंग होम के संचालकों के साथ-साथ अन्य नौकरशाहों की भी मिलीभगत है. धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों के हाथ भी गुनाहों से इसलिए सने हैं, क्योंकि प्रसव वेदना से पीड़ित महिलाओं के गर्भाशय का ऑपरेशन होना दिखाकर उनके स्मार्ट कार्ड से हजारों रुपये की राशि निकाली गई है. स्मार्टकार्ड धारियों अथवा उनके परिजनों को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि उन्हें बीमारी क्या थी और उनका ऑपरेशन किस चीज का हुआ अथवा नहीं! कहा तो यहां तक जा रहा है कि छोटी-मोटी बीमारी से भी पीड़ित बीपीएल परिवार के लोगों को गंभीर बीमारियों का हवाला देकर न केवल कागज पर सर्जरी की गई, बल्कि बीपीएल स्मार्ट कार्ड के जरिए करोड़ों का फर्जीवाड़ा भी कर लिया गया. यहां तक कि अपने बूते नहीं होने वाली सर्जरी का ब्यौरा दर्ज कराकर भी कई निजी अस्पताल संचालकों द्वारा स्मार्ट कार्ड के जरिए सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया गया. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि गर्भाशय सहित अन्य तरह की सर्जरी के नाम पर सरकार को चूना लगाने के लिए धंधेबाजों द्वारा ऐसे-ऐसे तिकड़म आजमाए गए, जिसकी कल्पना भी लोगों ने नहीं की होगी. कई जिलों में जांच के दौरान मामला आइने की तरह साफ भी हो गया है. लेकिन सुलगता सवाल यह है कि इस गंभीर सत्य को स्वीकराने से सरकारी हुक्मरान आखिरकार कन्नी क्यों काट रहे हैं? ''कोख'' तथा अन्य सर्जरी के नाम पर कौन-कौन से निजी अस्पतालों के द्वारा सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया है और गुनहगार कौन-कौन हैं? उच्च पदाधिकारियों के द्वारा बार-बार आदेश जारी किए जाने के बाद भी आखिर जांच की गति में तेजी क्यों नहीं आ रही है? गुनाहगारों की कुंडली खंगालने में नौकरशाहों के हाथ आखिर क्यों कांप रहे हैं? सवाल तो अनगिनत हैं, लेकिन यह कहने में शायद कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि खगड़िया सहित कुछ अन्य जिलों में गर्भाशय तथा अन्य सर्जरी के नाम हुई लूट के मामले की जांच अभी तक शायद इसलिए नहीं पूरी हो पाई है, क्योंकि चिंहित निजी अस्पतालों में से पांच निजी अस्पताल दबंगों के हैं और वहां हाथ डालना स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर प्रतीत हो रहा है. कुछ अस्पताल तो इतने रसूखदार लोगों के बताए जा रहे हैं जिनके अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई तो दूर अभी तक शायद किसी ने उनकी तरफ बुरी नजर से देखना तक गंवारा नहीं समझा है. जांच में यह बात सामने आई है कि वित्तीय वर्ष 2012-2013 में खगड़िया जिले के आठ नर्सिंग होम के द्वारा कुल 1836 सर्जरी की गई, लेकिन केवल 124 मामलों की जांच हुई और बाकी को ठंडे बस्ते डाल दिया गया. सुपौल में 995, मधेपुरा में 1603 तथा बेगूसराय में 2503 स्मार्ट कार्डधारियों के गर्भाशय का ऑपरेशन किया गया, लेकिन अभी तक दस फीसद मामलों की भी जांच नहीं हुई. अब सवाल यह उठता है कि खगड़िया जिले में 1836 गर्भाशय ऑपरेशन की जानकारी होने के बावजूद जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने केवल 124 कार्ड की ही जांच क्यों की? जबकि 1836 स्मार्ट कार्ड के जरिए गर्भाशय के ऑपरेशन के नाम पर पैसों की निकासी हुई.

जानकारों का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2012-2013 एवं 2014-2015 में गर्भाशय ऑपरेशन के नाम पर जमकर सरकारी धन को लूटा गया है. खगड़िया के सिविल सर्जन डॉक्टर रास बिहारी सिंह तथा एसीएमओ डॉक्टर मीरा सिंह भी मानती हैं कि ''कोख'' के नाम पर विभिन्न जिलों में सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया है. रासबिहारी सिंह कहते हैं कि स्मार्ट कार्ड संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की वजह से सभी 1836 मामलों की जांच संभव नहीं हो सकी है. 124 मामलों की जांच संतोषजनक पाई गई है. अगर विभाग को दस्तावेज उपलब्ध कराया गया, तो पूरे मामले की जांच संभव हो सकेगी. वैसे खगड़िया, पूर्णियां, सहरसा, सुपौल और बेगूसराय जैसे जगहों पर ही ''कोख'' के नाम पर सरकार को चूना नहीं लगाया गया है. लगभग सभी जिलों में इस तरह के अपराध को अंजाम देकर धंधेबाजों ने न केवल सरकार की चूलें हिला दी हैं, बल्कि सुशासन की हवा भी निकाल दी है. विभिन्न उच्च पदाधिकारियों द्वारा जांच की बात भी कही जा रही है और जांच भी चल रही है. लेकिन इस गोरखधंधे में संलिप्त धंधेबाजों के हाथ इतने लंबे हैं कि किसी भी तरह मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है. देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में आखिर कार्रवाई क्या होती है और गुनहगारों के फेहरिश्त में कौन-कौन लोग शामिल होते हैं? लेकिन यह तो सत्य है कि दबंग और रसूखदार लोगों के द्वारा संचालित निजी अस्पताल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए बीपीएल परिवार के लोगों को गंभीर ऑपरेशन का हवाला देकर फर्जी निकासी कर ली गई. अधिकांश रोगियों के गर्भाशय का ऑपरेशन दिखाकर फर्जी निकासी की गई है. जबकि हकीकत यह है कि पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, दवा दुकान, कैंटीन, एंबुलेंस सहित अन्य सुविधाओं के नाम पर तय किए गए मानक पर शायद ही कोई निजी अस्पताल खरा उतर पा रहा है. चौबीस घंटे चिकित्सक व प्रशिक्षित नर्सों के तैनाती की कल्पना ही बेमानी है. इस योजना के तहत तीस हजार रुपये हड़पने के लिए निजी अस्पताल संचालकों द्वारा मरीजों को तरह-तरह का प्रलोभन देकर जाल में फंसा लिया जाता है और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को मुफ्त भोजन के साथ-साथ अधिकतम एक वर्ष तक यात्रा व्यय के नाम पर मिलने वाले सौ रुपये थमा-थमाकर चलता कर दिया जाता है. गर्भाशय अथवा अन्य तरह की सर्जरी होने की जानकारी तक मरीजों को नहीं होती. बहरहाल, कई वर्षों से चल रहे इस गोरखधंधे का पर्दाफाश होने के बाद आम जनता की नजरें धंधे में संलिप्त गुनहगारों पर हैं.■

> **कई जिलों में जांच के दौरान मामला आइने की तरह साफ भी हो गया है. लेकिन सुलगता सवाल यह है कि इस गंभीर सत्य को स्वीकराने से सरकारी हुक्मरान आखिरकार कन्नी क्यों काट रहे हैं? ''कोख'' तथा अन्य सर्जरी के नाम पर कौन-कौन से निजी अस्पतालों के द्वारा सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया है और गुनहगार कौन-कौन हैं? उच्चपदस्थ पदाधिकारियों के द्वारा बार-बार आदेश जारी किए जाने के बाद भी आखिर जांच की गति में तेजी क्यों नहीं आ रही है?**

feedback@chauthiduniya.com

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आर्युवेदिक दवा बतायें। दीनानाथ सिंह, रांची

उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कौप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते सम लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मै क्या करूं? प्रभात, औरंगाबाद

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा

उत्तर : आप REPL निर्मिता विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।

प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए । मैं क्या करू? शंकर तिवारी, गुरगांव

उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिशन में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान

उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डह ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।

प्रश्न : डॉ. साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद

उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।

प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा।

उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दे एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।

प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली।

उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कम पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंदरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें :
REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)

E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटरः दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुरः आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसरायः प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छत्तीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहारः मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- बोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेडर्स 9903175579, देव मार्कटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंडः सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -विजापुर 9341610592 गुलवर्गा:9343834519

दांतो की सुरक्षा के प्रति जागरूक होना जरूरी

ariskon Pharma Pvt.Ltd.

An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ. धनन्जय कुमार BDS
दन्त रोग विशेषज्ञ, औरंगाबाद

औरंगाबाद के दाँतों के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. धनन्जय कुमार से हुई बातचीत के कुछ अंश निम्न हैं उनका मानना है कि सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है स्वस्थ्य दांत, और दांत न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं,बल्कि हमारे लूक को अच्छा बनाते हैं जिससे

व्यक्तित्व में निखार आता है। हालांकि दांतों की स्वच्छता के मायने और तरीके अलग होते हैं। चिकित्सकों की राय है कि प्रतिदिन ब्रश करने के बाद जीभ अवश्य साफ करें। ब्रश करने का कोई समय निर्धारित नहीं परन्तु दो मिनट जरूरी माना गया है। ब्रश अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए अल्ट्रा वाले। दांतो को स्वस्थ्य रखने के लिए आवश्यक है। आपको चाहिए कि आप गृभावस्था से ही केयर करना शुरू कर दें। उचित मात्रा में कैल्शियम हमेशा दें। डॉ धनन्जय ने आगे बताया कि साढ़े छः साल बाद भी दांतों की वजह से परेशानी हो या दांत खराब हों तो तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें क्योंकि 6-7 साल बाद फंक्शन एप्लाइसेंस तथा 12 साल बाद सिस्ड आर्थो ट्रीटमेन्ट द्वारा दाता का ठीक किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति या बच्चे के लिए दो बार ब्रशींग आवश्यक है, दूध पिलाने के बाद कुल्ला, कराना, आवश्यक है, दांतों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है चिपचिपा फूड, चॉकलेट, बिस्कूट खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह साफ करें जिससे पायरिया से भी बच सकते हैं। डॉ.धनन्जय ने बताया कि दांतों की सुरक्षा में कोताही न करें, दो बार ब्रशिंग तो जरूरी है ही साथ ही समय देकर अच्छे से ब्रश करें जिससे मसूढ़े स्वस्थ्य होंगे। यदि आपके दाँत टूट रहे हैं तो उसे निकालने के बजाय उसे बचाने का प्रयास करें और यदि टूट जाता है तो उसे डॉक्टर के पास जाकर प्रत्यारोपण करा लें या फिर नया लगा लें और हर छहः महीने पर इसका चेकअप कराते रहें। ■ भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.

A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil

Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus

Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg

Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

आईपीएस अफसर का निलंबन प्रकरण : कैट के आदेश पर सरकार ने घुटने तो टेके पर हठ नहीं छोड़ी

बहाल कर दिया, काम नहीं दिया

अफसरों को बैठा कर वेतन दिया जाना गैर कानूनी है : अमिताभ ठाकुर

बहाली आदेश पर भी निलंबित लिखने की आदत नहीं छोड़ रही सरकार

दीनबंधु कबीर

उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर का निलंबन रद्द कर उन्हें तत्काल तैनात करने के केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव राइब्यूनल) के फैसले पर सरकार ने घुटने तो टेक दिए लेकिन उन्हें काम नहीं दे रही है. ठाकुर का निलंबन समाप्त कर उन्हें डीजीपी मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है, उन्हें कोई काम नहीं दिया जा रहा है और बैठा कर वेतन दिया जा रहा है. इसे लेकर आईजी अमिताभ ठाकुर ने सरकार के समक्ष नया तकनीकी पचड़ा फंसा दिया है. ठाकुर का कहना है कि अधिकारियों को सम्बद्ध कर उन्हें काम न देना और बैठा कर वेतन देना सरकार का गैरकानूनी कृत्य है, इस पर फौरन रोक लगनी चाहिए. उन्होंने यह भी मांग की है कि सम्बद्ध किए गए पुलिस अधिकारियों को बेमानी दिए गए वेतन की राशि गृह विभाग के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक के वेतन से काटा जाना चाहिए. इसे लेकर अमिताभ ठाकुर की समाजसेवी पत्नी नूतन ठाकुर ने कानूनी लड़ाई भी छेड़ दी है. सरकारी मंशा का हाल यह है कि पंचाट के फैसले पर नौकरी पर बहाल किए जाने के बावजूद प्रदेश सरकार अपने पत्रों में उन्हें निलंबित ही बता रही है. केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट के फैसले पर घुटने टेकते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को आखिरकार आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को सेवा में बहाल करना पड़ा. गृह विभाग के प्रमुख सचिव देवाशीष पांडा के 11 मई 2016 के आदेश में कहा गया कि अमिताभ ठाकुर को 11 अक्टूबर 2015 से ही पूरे वेतन के साथ बहाल किया जाता है. केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2016 को अमिताभ ठाकुर का निलंबन निरस्त कर दिया था और उस पर केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (कैट) की लखनऊ बेंच ने भी 25 अप्रैल 2016 को अपनी मुहर लगा दी थी. उत्तर प्रदेश सरकार के टालमटोल पर केंद्र सरकार ने 26 अप्रैल 2016 को अमिताभ की बहाली का दोबारा आदेश दिया, जिसके अनुपालन में राज्य सरकार को उनकी बहाली का आदेश जारी करना पड़ा.

जिस लिफाफे में अमिताभ ठाकुर की बहाली का परिपत्र भेजा गया, उस पर ठाकुर को निलंबित आईपीएस अफसर ही लिखा गया. आईजी कार्मिक पीसी मीना की तरफ से ठाकुर को आदेश पत्र प्राप्त कराया गया, उसमें अमिताभ ठाकुर, आईपीएस (निलंबित) बताया गया. इस मंशागत भूल की तरफ ध्यान दिलाए जाने के बाद उसे दोबारा सुधार कर भेजा गया. अमिताभ ठाकुर को डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं दिया जा रहा. काम देने के लिए भी अमिताभ को कैट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है. उन्होंने कैट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा है कि उन्हें सात महीने तक अवैध रूप से निलंबित रखा गया और अंत में केंद्र सरकार और कैट के आदेश पर 11 मई 2016 को उनकी बहाली हुई. उन्हें डीजीपी कार्यालय में ज्वाइन भी करा लिया, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं दिया गया. 16 मई को आईपीएस अफसरों की तैनाती के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक हुई जिसमें 62 आईपीएस अफसरों की तैनाती तय हुई लेकिन उनके प्रति पूर्वाग्रह से भरी सरकार ने जानबूझ कर उन्हें तैनाती नहीं दी. अमिताभ का कहना है कि उनकी बहाली के आदेश में यह स्पष्ट लिखा है कि उनकी तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे, फिर तैनाती का आदेश क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? अब राज्य सरकार से इस सवाल का जवाब पंचाट में पूछा जाएगा.

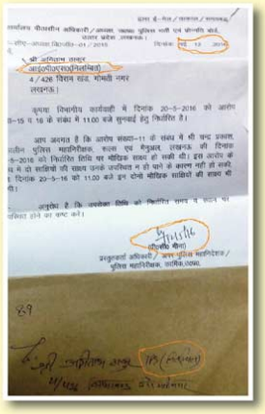

जिस लिफाफे में अमिताभ ठाकुर की बहाली का परिपत्र भेजा गया, उस पर ठाकुर को निलंबित आईपीएस अफसर ही लिखा गया. आईजी कार्मिक पीसी मीना की तरफ से ठाकुर को आदेश पत्र प्राप्त कराया गया, उसमें अमिताभ ठाकुर, आईपीएस (निलंबित) बताया गया. इस मंशागत भूल की तरफ ध्यान दिलाए जाने के बाद उसे दोबारा सुधार कर भेजा गया. अमिताभ ठाकुर को डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं दिया जा रहा. काम देने के लिए भी अमिताभ को कैट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है.

निलंबन पर अखिलेश का नहीं अनीता सिंह का हस्ताक्षर था

आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के निलंबन आदेश पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बजाय प्रमुख सचिव अनीता सिंह का हस्ताक्षर था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच को गृह विभाग द्वारा दिए गए दस्तावेजों से यह मामला उजागर हुआ. अभिलेख के अनुसार 13 जुलाई 2015 को तत्कालीन डीजीपी जगमोहन यादव ने बिना किसी तत्कालिक कारण का उल्लेख किए प्रमुख सचिव गृह को अमिताभ ठाकुर को निलंबित करने के लिए पत्र लिखा. उक्त पत्र मुख्य सचिव आलोक रंजन के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा और प्रमुख सचिव अनीता सिंह ने फौरन ही मुख्यमंत्री की तरफ से उसे अनुमोदित कर दिया. अमिताभ ठाकुर ने कैट में यह मामला भी उठाया था और अपने निलंबन को अवैध बताया था. दूसरी तरफ उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने फर्जी दस्तावेज रच कर उनके पति अमिताभ ठाकुर को प्रताड़ित किए जाने के मामले में मुख्य सचिव आलोक रंजन और गृह विभाग के प्रमुख सचिव देवाशीष पांडा के खिलाफ लोकायुक्त संजय मिश्रा की अदालत में मामला दायर कर रखा है. परिवाद में कहा गया है कि इन अफसरों ने उनके पति आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के सेवा सम्बन्धी मामलों में फर्जी अभिलेख बना कर उन्हें प्रताड़ित किया. अदालत को विस्तार से जानकारी दी गई है कि किस तरह उक्त अफसरों ने सिविल सर्विस बोर्ड की कोई वास्तविक मीटिंग किए बगैर फर्जी अभिलेख बना कर अमिताभ ठाकुर का निलंबन दो-दो बार बढ़ाया. फर्जी अभिलेख बनाने के तमाम सबूत देकर लोकायुक्त से गृह विभाग और डीजीपी कार्यालय की सम्बन्धित पत्रावली तलब करते हुए मामले की गहराई से जांच करने और आपराधिक कृत्य के दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश करने की अपील की गई है. ■

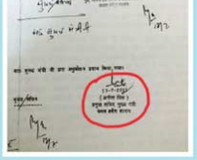

भ्रष्ट खनन मंत्री को बचाने में खोद डाली मुलायम ने अपनी छवि

उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के भीषण भ्रष्टाचार के खिलाफ आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी समाजसेवी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा अभियान चलाने से नाराज उत्तर प्रदेश सरकार ने ठाकुर परिवार को अपना सीधा निशाना बनाया. ठाकुर के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराने से लेकर तमाम षडयंत्र किए गए, लेकिन ठाकुर दम्पति ने धैर्य के साथ उसका मुकाबला किया. आखिरकार सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने फोन करके अमिताभ ठाकुर को धमकियां दीं, लेकिन ठाकुर ने मुलायम की धमकी वाले फोन की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली और उसे सार्वजनिक कर दिया. इस पर अखिलेश सरकार और बौखला गई. अमिताभ ने धमकी भरे फोन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी. आखिरकार अदालत के सीधे हस्तक्षेप पर एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जैसी उम्मीद थी, वैसा ही हुआ, पुलिस ने मामले की लीपापोती करने की कोशिश की और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया. सपाइयों ने धमकी वाले टेप को फर्जी साबित करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसमें नाकाम रहे थे. मुलायम की धमकी को एक अभिभावक की झिड़की बता कर मामले को हल्का करने की उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोशिश तो की थी, लेकिन सरकार की साजिश तुरंत ही उजागर हो गई जब अमिताभ ठाकुर पर बलात्कार का प्रतिशोधी मुकदमा दर्ज करा दिया गया. विडंबना यह है कि बलात्कार के इसी प्रकरण में हाईकोर्ट के आदेश पर लखनऊ के गोमतीनगर थाने में मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष जरीना उस्मानी समेत आठ लोगों पर षडयंत्र करने का मुकदमा दर्ज किया गया था. नूतन ठाकुर की तहरीर पर हाईकोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था. महिला आयोग की अध्यक्ष जरीना उस्मानी ने आइपीएस अमिताभ ठाकुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. इसमें उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के सहयोग करने का भी आरोप था. इसके जवाब में नूतन ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और जरीना उस्मानी समेत आठ लोगों पर फर्जी फंसाने का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी. बलात्कार के मुकदमे में अदालत को भी आखिरकार यह कहना पड़ा कि इस मामले में कोई कानूनी सूत्र नहीं है. मुलायम की धमकी को अभिभावक की डांट बताने वाले अखिलेश यादव उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए कि अमिताभ ठाकुर की वह गलती क्या थी, जिस पर नेता जी नाराज होकर उन्हें डांटने लगे? आरटीआई ऐक्टिविज्म वे पहले से कर रहे थे, जनहित याचिकाएं वे पहले से दाखिल कर रहे थे, धरना-प्रदर्शन में वे पहले से शामिल होते रहे और सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ वे अपना विरोध पहले से दर्ज कराते रहे, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल में उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने इस दरम्यान अमिताभ ठाकुर को क्यों नहीं डांटा? दरअसल, अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के प्रति समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम और मुख्यमंत्री अखिलेश की नाराजगी प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई गई मुहिम से गहराती गई. खनन मंत्री के भ्रष्टाचार की शिकायत सबसे पहले प्रतापगढ़ के ओमशंकर द्विवेदी और उनके वकील अजय प्रताप सिंह राठौर ने की थी. लोकायुक्त से की गई शिकायत में कहा गया था कि गायत्री प्रसाद प्रजापति ने जब विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल किया था तब उनकी सम्पत्ति 1.81 करोड़ रुपये थी और मंत्री बनने के बाद गायत्री ने 942.57 करोड़ रुपये की सम्पत्ति बना ली. लोकायुक्त के समक्ष 1725 पन्ने का साक्ष्य भी प्रस्तुत किया था. लोकायुक्त से की गई शिकायत में खनन मंत्री की 943 करोड़ की सम्पत्ति की बात कही गई, लेकिन बाद में कई और सम्पत्तियों का ब्यौरा मिला. अब तक गायत्री की 1350 करोड़ से अधिक की सम्पत्तियों की रजिस्ट्री मिल चुकी है. खनन मंत्री के भ्रष्टाचार मामले को नूतन ठाकुर ने मुहिम की शक्ल में बदल दिया और अखिलेश सरकार के भ्रष्ट मंत्री की करतूतें सार्वजनिक होने लगीं. जब हाईकोर्ट के निर्देश पर खनन मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, तभी सपा नेतृत्व पूरी तरह बौखला गया और अनापशनाप कदम उठाने लगा. ■

अमिताभ ने यह भी कहा कि बिना काम के वेतन दिया जाना गैरकानूनी है. ठाकुर ने डीजीपी एस जावीद अहमद को पत्र लिख कर बेमानी वेतन देने की प्रक्रिया को खत्म कर उन्हें और अन्य सम्बद्ध अफसरों को तत्काल तैनाती देने की मांग की. ठाकुर ने कहा कि उनसे बिना सरकारी काम लिए प्रतिदिन लगभग पांच हजार रुपये वेतन दिया जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित है. लिहाजा, या तो उन्हें स्वतंत्र तैनाती दी जाए या डीजीपी ऑफिस में ही कोई जिम्मेदारी दी जाए, ताकि उनके वेतन का औचित्य साबित हो सके. अमिताभ ठाकुर द्वारा यह मसला उठाए जाने के बाद उनकी समाजसेवी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर ने इसे लेकर कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है. उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर महीनों से डीजीपी कार्यालय से सम्बद्ध आईपीएस अफसरों को बिना काम लिए वेतन देने के मामले में त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि सम्बद्ध अफसरों को बैठा कर दिए गए वेतन की राशि की वसूली गृह विभाग के प्रमुख सचिव और डीजीपी के वेतन से की जाए.

नूतन ठाकुर ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि मौजूदा समय में भी आधा दर्जन आईपीएस अफसर डीजीपी कार्यालय से सम्बद्ध हैं, जिनमें आईपीएस अफसर सुनील सक्सेना 14 जनवरी से और लव कुमार 22 जनवरी 2016 से ही अटैच कर रखे गए हैं. इनके अलावा चार अन्य अफसर भी पिछले कई महीनों से बिना कोई सरकारी काम के निठल्ले बैठे हैं और इन पर सरकार द्वारा लाख-सवा लाख रुपये प्रति माह का वेतन दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि इन सभी अफसरों का वेतन जोड़ा जाए तो यह हर महीने लगभग 15 लाख रुपये आता है. नूतन ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ साल में ऐसे सारे सम्बद्ध अफसरों का हिसाब निकाल कर उन्हें दिए गए वेतन की राशि गृह विभाग के प्रमुख सचिव और डीजीपी से वसूली जाए. उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई अपेक्षित जवाब नहीं मिलने पर वे इस मामले में अदालत की चौखट पर जाएंगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

काशी हिंदू विश्वविद्यालय

घपलेबाजी का अड्डा

पूर्वांचल के एम्स के नाम से मशहूर सर सुंदर लाल चिकित्सालय के नवनियुक्त मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. उपाध्याय की नियुक्ति विवादों में घिर गई है. यह नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए एक काले धब्बे के रूप में उजागर हुई है.

डॉ. ओपी उपाध्याय

चौथी दुनिया ब्यूरो

एक दोहा है कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी. काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यही हो रहा है. कुलपति साहब के फैसले भी अजीबोगरीब हैं. जहां एक ओर कोर्ट से बरी व्यक्ति को पुन: विश्वविद्यालय में ज्वाइन होने नहीं दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट से सजायाफ्ता व्यक्ति की नियुक्ति करने में उन्हें थोड़ी भी झिझक नहीं हो रही है. ऐसा लगता है कि विश्वविख्यात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अब घपलेबाजी का अड्डा बन गया है. ऐसी कई खबरें विश्वविद्यालय से आ रही हैं जिससे यह लगता है कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन नियम कानून को ताक पर रखकर फैसले ले रहा है. बीएचयू में घपलेबाजी की खबरें तब आ रही हैं जब पूरा विश्वविद्यालय भारत रत्न मदन मोहन मालवीय की कर्मभूमि का शताब्दी वर्ष मना रहा है. इस अंक में हम दो ऐसी खबरें पेश कर रहे हैं, जिनसे यह साफ लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास पर कालिख पोतने में जुटा है. ये दोनों विषय विश्वविद्यालय प्रशासन के निकम्मेपन को उजागर करते हैं. पहला मामला मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. ओपी उपाध्याय की नियुक्ति का है और दूसरा मामला प्रोफेसर संदीप पांडेय की बर्खास्तगी का है.

पहले, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की नियुक्ति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन और मानव संसाधन मंत्रालय की नाकामी को समझते हैं. जिनकी नियुक्ति हुई उनका नाम डॉ. ओपी उपाध्याय है. पहले भी वह विवादों में रहे हैं, लेकिन जून 2011 को उन्हें फीजी नेशनल युनिवर्सिटी में तीन साल के कॉन्ट्रेक्ट पर कुलपति का सलाहकर बनने का ऑफर मिला था. मतलब यह कि जून 2014 तक उन्हें फीजी नेशनल युनिवर्सिटी में ही रहना था. बताया जाता है कि वह अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा किए बगैर भारत लौट आए और दोबारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नियुक्त हो गए. यहां सवाल यह है कि जब वह फीजी से वापस बीएचयू आए तब विश्वविद्यालय में उनकी पुनर्नियुक्ति के दौरान सारे नियम-कानून का पालन किया गया? क्या जरूरी कागजात और एनओसी यानि अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा कराया गया या फिर इन सबको नजरअंदाज करके उन्हें वापस रख लिया गया? 17 अप्रैल 2016 को डॉ. ओपी उपाध्याय को कुलपति ने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के रूप में नियुक्त कर दिया. समझने वाली बात यह है कि डॉ. ओपी उपाध्याय अगर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट नहीं बने होते, तो वह 30 जून 2016 को रिटायर हो गए होते. अब, जब वह मेडिकल सुपरिंटेंडेंट बना दिए गए हैं, तो उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है. डॉ. ओपी उपाध्याय की नियुक्ति विवादों में तकनीकि मामले को लेकर तो है ही, लेकिन फीजी में जो उन्होंने कारनामा किया उसे सुनते ही आप दंग रह जाएंगे.

काशी विश्वविद्यालय के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. ओपी उपाध्याय की दास्तान मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ फीजी के क्रिमिनल केस संख्या 1297/2012 से पता चलती है. यह केस यौन उत्पीड़न का है. इस केस में पीड़िता 21 साल की लड़की है जो उस वक्त बीएससी की स्टूडेंट थी. कोर्ट के आदेश के मुताबिक डॉ. ओपी उपाध्याय ने 21 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया. इस केस की सुनवाई 8 जनवरी 2013 को हुई थी. सुनवाई के दौरान डॉ. ओपी उपाध्याय ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अपनी तरफ से सारी दलीलें दीं, लेकिन कोर्ट ने उनकी बातों को मानने से इंकार कर दिया. फीजी की कोर्ट ने डॉ. उपाध्याय को 21 साल की लड़की का अपने घर पर यौन शोषण करने का दोषी पाया. कोर्ट ने उन्हें 18 महीने की जेल की सजा दी और तीन साल के लिए सस्पेंड कर दिया. इसके साथ पीड़िता को 500 डॉलर का हर्जाना देने को कहा गया और एक हजार का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया. इस फैसले के बाद डॉ. ओपी उपाध्याय ने फीजी हाईकोर्ट में अपील की. हाईकोर्ट ने भी डॉ. उपाध्याय की सजा को बरकरार रखा.

अब सवाल यह है कि डॉ. ओपी उपाध्याय को किस आधार पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नियुक्त किया गया? और नियुक्त करने के बाद उन्हें मेडिकल सुपरिंटेंडेंट क्यों बना दिया गया? क्योंकि एक बार जब फीजी हाईकोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी, तो ऐसे में दो ही परिस्थिति पैदा होती हैं. डॉ. ओपी उपाध्याय ने फीजी की जेल में सजा काटी या फिर वहां से भाग निकले. दोनों ही परिस्थितियों में डॉ. उपाध्याय एक गुनहगार हैं. सवाल यह है कि क्या डॉ उपाध्याय ने फीजी की अदालत के फैसले के बारे में कुलपति या मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सूचना दी या फिर उन्हें झांसा देकर वह विश्वविद्यालय में फिर से कार्यरत हुए हैं?

अफसोस की बात यह है कि फीजी में हुई इस घटना के बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन को पता है लेकिन इसके बावजूद डॉ. उपाध्याय के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र महासभा के पूर्व अध्यक्ष रामकरण यादव फीजी की घटना और डॉ. उपाध्याय की नियुक्ति को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिख चुके हैं. उन्होंने यह पत्र ऊपर भी भेजा है. उन्होंने काशी विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव काउंसिल के सारे सदस्यों को भी पत्र के माध्यम से इस मामले से अवगत कराया. फिर ऐसी क्या बात है कि सभी अधिकारी डॉ. ओपी उपाध्याय पर लगे आरोप के बारे में जांच करने से बच रहे हैं? क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की नियुक्ति में फीजी प्रकरण को जानबूझ कर नजरअंदाज किया गया है? इस बात की जांच होनी चाहिए कि इस पृष्ठभूमि का व्यक्ति कैसे विश्वविद्यालय को चकमा देने में कामयाब हुआ है और साथ ही इस चूक के लिए कुलपति को भी जिम्मेदार बनाना चाहिए.

पूर्वांचल के एम्स के नाम से मशहूर सर सुंदर लाल चिकित्सालय के नवनियुक्त मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. ओपी उपाध्याय की नियुक्ति विवादों में घिर गई है. यह नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए एक काले धब्बे के रूप में उजागर हुई है. सवाल यह उठने लगा है कि युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. गिरीश चंद्र त्रिपाठी को क्या यह पता है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की है जिन्हें एक लड़की के यौन शोषण का दोषी पाया गया. क्या उन्हें यह पता नहीं था कि डॉ. उपाध्याय पर पहले भी कई आरोप लगे हैं. नोट करने वाली बात यह है कि जब उन्हें डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के लिए तीन बार और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के लिए दो बार चयन समिति ने अयोग्य ठहरा चुकी है तो फिर ऐसी क्या बात है कि फीजी से लौटने के बाद वह अचानक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट पद के लिए सबसे योग्य हो गए? इस सवाल का जवाब कुलपति साहब को देना चाहिए, क्योंकि फीजी में प्रोफेशनल स्तर पर उन्होंने कोई कारनामा तो किया नहीं बल्कि एक गुनहगार के रूप में वह वहां से वापस लौट हैं. अब सवाल यह है कि क्या मानव संसाधन विकास मंत्री और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति अब भी खामोश रहेंगे या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? ओपी उपाध्याय न सिर्फ कानून की नज़र में गुनहगार हैं बल्कि ऐसे किसी व्यक्ति का शिक्षण संस्थान में कार्यरत होना भी सामाजिक दृष्टि से गलत है. ■

हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद जिद पर अड़ा बीएचयू प्रशासन

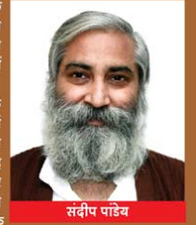

संदीप पांडेय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से विज़िटिंग प्रोफेसर संदीप पांडेय को बर्खास्त किए जाने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद उन्हें फिर से ज्वाइन नहीं करने दिया जा रहा. मैगसेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडेय ने कहा कि उनके पक्ष में अदालत का इतना मजबूत आदेश आने के बाद भी विश्वविद्यालय के कुलपति गिरीश चंद्र त्रिपाठी बीएचयू में उनकी वापसी नहीं होने दे रहे हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संदीप पांडेय के काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आईआईटी में विजिटिंग फैकल्टी के अनुबंध को खत्म करने का आदेश 23 अप्रैल को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि देशविरोधी गतिविधियों जैसे आरोप लगाकर एकतरफा कार्रवाई करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है. न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी की खंडपीठ ने पांडेय की तरफ से दायर याचिका को अनुमति दे दी जिन्होंने छह जनवरी 2016 के विश्वविद्यालय प्रबंधन के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनके अनुबंध को खत्म कर दिया गया था. उन्हें रसायन इंजीनियरिंग विभाग में विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल इस साल 30 जुलाई तक था. उक्त आदेश में गांधीवादी कार्यकर्ता पांडेय को यह भी कहा गया कि उनके अनुबंध को खत्म करने का फैसला आईआईटी (बीएचयू) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में किया गया जिसने उन्हें साइबर अपराध और देशहित के खिलाफ काम करने का दोषी पाया. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने बीएचयू में राजनीति विज्ञान के एक छात्र के पत्र का संज्ञान लिया जिन्होंने पांडेय पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने और नक्सलियों से सहानुभूति रखने का आरोप लगाया था. पांडेय के वकील राहुल मिश्रा ने तर्क दिया कि संबंधित अधिकारियों ने यह फैसला याचिकाकर्ता की आवाज को दबाने के लिए किया, क्योंकि वह अलग विचारधारा के व्यक्ति हैं. आदेश को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि यह मामला महज अनुबंध रद्द करने का नहीं है बल्कि छवि खराब करने वाला दंडात्मक आदेश है जिसमें साइबर अपराध करना और देशहित के खिलाफ काम करना जैसे भारी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. अदालत ने कहा कि यह सभी आरोप गंभीर हैं और याचिकाकर्ता के व्यवहार व चरित्र पर गंभीर आक्षेप लगाते हैं. अदालत ने कहा कि जिस तरीके से एकतरफा फैसला किया गया है, उसे हम मंजूरी नहीं दे सकते.

हाईकोर्ट का यह आदेश आने के बावजूद बीएचयू के कुलपति अपनी जिद पर अड़े हैं और संदीप पांडेय को अध्यापन का कार्य जारी करने का आदेश नहीं दे रहे. संदीप पांडेय इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं और कहते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईआईटी से मेरा निष्कासन रद्द करने का इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो फैसला आया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत ने मेरी विचारधारा और कार्यों की वैधता स्वीकार की है. फैसले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का बचाव किया गया है और कहा गया है कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वैध एवं संवैधानिक अधिकार है, लिहाजा अपने से अन्य विचारधारा का गला नहीं घोंटा जा सकता. न्यायाधीशों ने वाल्टेयर का वह प्रसिद्ध वक्तव्य भी उद्धृत किया कि, मैं आपसे असहमत हो सकता हूं लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लगा दूंगा. संदीप पांडेय ने कहा कि बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय भी कहते थे कि भारत तभी मजबूत रहेगा और प्रगति करेगा जब सारे समुदाय मिलजुल कर साम्प्रदायिक सद्भावना व सौहार्द के साथ रहेंगे. अदालत ने भी पंडित मदन मोहन मालवीय का उक्त कथन उद्धृत किया है. हाईकोर्ट ने बीएचयू के कुलपति और प्रशासनिक पदों पर बैठे अन्य अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रशासनिक पदों पर विद्यमान लोगों को अकादमिक व प्रशासनिक निर्णय लेते समय तटस्थ रहना चाहिए.

इस प्रकरण का विचित्र पहलू यह भी है कि संदीप पांडेय के दो अन्य रिश्तेदार भी बीएचयू से निकाले जा चुके हैं. बीएचयू में इंडोलॉजी विभाग के प्रोफेसर राजबली पांडेय और केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर गोपाल त्रिपाठी को भी 1960 में हजारी प्रसाद द्विवेदी समेत कुछ अन्य प्रोफेसरों के साथ निकाल दिया था. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के तीन वर्षों तक कुलपति रहे आचार्य नरेन्द्र देव को भी अप्रिय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा था. ■

feedback@chauthiduniya.com

मशहूर होने की ललक का दबाव

अनंत विजय

जब कोई लेखक अपने सर्वश्रेष्ठ दौर में होता है, उस वक्त लिखना छोड़ दे ऐसा सुनने में कम ही आता है, हिंदी में तो और भी कम. हिंदी के लेखक जब तक जीवित रहते हैं तब तक लिखते रहते हैं. ज्यादातर हिंदी के लेखकों को लगता है कि किताबों की संख्या से ही उनको अमरत्व प्राप्त होता है, उसकी गुणवत्ता से नहीं, लिहाजा वो रचनात्मक तौर पर चुक जाने के बाद भी कुछ न कुछ लिखते रहते हैं. नतीजा यह होता है कि पूर्व में जो प्रतिष्ठा उन्होंने अर्जित की होती है वो भी छीनने लगती है. इस रोग से हिंदी का शायद ही कोई लेखक अछूता रहा है. पहले उपन्यास लिखकर साहित्य जगत में अपना डंका बजाने वाले लेखक से जब उपन्यास छूटता है तो वो संस्मरण लिखने लगते हैं. यहां भी जब उनकी थाती खत्म हो जाती है तो वो आत्मकथा की ओर मुड़ते हैं. बीच-बीच में छिटपुट लेखों के संग्रह आदि छपवा लेते हैं. इसका फायदा यह होता है कि उनके किताबों की संख्या बढ़ती चली जाती है. प्रकाशक लेखक की प्रसिद्धि के दबाव में किताबें छाप भी देते हैं. उम्र के छिहत्तरवें पड़ाव पर आकर राजेन्द्र यादव ने किशोरावस्था में लिखा अपना उपन्यास *एक था शैलेन्द्र* छपवा लिया था, जो बेहद अनगढ़ और उनकी प्रतिष्ठा को कम करने वाला था. उसपर से तुर्रा ये कि इसको अविकल और असंपादित कहकर प्रचारित भी किया गया था. इस उपन्यास ने राजेन्द्र यादव के किताबों की संख्या में अवश्य इजाफा कर दिया था, लेकिन उनकी लेखकीय प्रतिष्ठा इससे धूमिल ही हुई थी. 2006 में उन्होंने यह किताब मुझे दी थी और समीक्षा लिखने का आदेश दिया था. किताब पढ़कर मैंने उन्हें फोन किया कि अगर मैं इसकी समीक्षा लिख दूंगा तो आप खफा हो जाएंगे. साथ ही मैंने विस्तार से अपनी आपत्तियों को उनको बताया था. खैर यादव जी इतने लोकतांत्रिक थे कि वो सामने वाले की न केवल बात सुनते थे बल्कि उसकी राय का सम्मान भी करते थे. अपने अंदाज में उन्होंने मुझे हड़काया भी था. लेकिन उसके बाद एक बार भी मुझे समीक्षा लिखने के लिए उन्होंने नहीं कहा था. इसके पहले राजेन्द्र जी ने हंस के अपने संपादकीय को भी संकलित कर प्रकाशित करवाया था. 2001 में उनका लगभग आत्मकथ्य *मुड़-मुड़ के देखता हूं...* प्रकाशित हुआ था. तब उस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी को कठघरे में खड़ा किया था और व्यक्तिगत अर्थहीनता का प्रश्न भी उछाला था. चेखव के नाटक तीन बहनों की एक पात्र, जो कि व्यर्थता बोध की मारी थी, का एक संवाद उद्धृत किया था काश! जो कुछ हमने जिया है, वह सिर्फ जिंदगी का रफ ड्राफ्ट होता और इसे फेयर करने का एक अवसर हमें और मिलता. दरअसल, यह लाइन हिंदी के उन

तमाम लेखकों की बाद की रचनाओं को देखते हुए बरबस याद आ जाती है कि काश उनको एक बार फिर से रचनात्मक जीवन मिलता और वो अपनी कमजोर रचनाओं का पुनर्लेखन कर पाते. यहां राजेन्द्र यादव का नाम सिर्फ इसलिए ले सका कि उनसे जुड़ा एक प्रसंग स्मरण में था. अन्यथा तो हिंदी के बहुतेरे लेखक यही कर रहे हैं. कई लेखक तो अपनी चंद कहानियों को बार-बार अलग-अलग नाम से प्रकाशित करवा कर किताबों की संख्या बढ़ाते रहते हैं. मेरी प्रिय कहानियां, मेरी चुनिंदा कहानियां, मेरी दस कहानियां, मेरी पच्चासी कहानियां, फलां और अन्य कहानियां आदि आदि.

दरअसल जब हम लेखन में आ रहे अवरोध की बात करते हैं तो यह बात साफ है कि लेखक भी एक तय सीमा तक ही लिख पाते हैं और उसके बाद वो खुद को या तो दोहराने लगते हैं या फिर अपने बनाए लेखकीय मानदंड को ही पार नहीं कर पाते हैं. हिंदी के कथाकार संजय की कहानी *कामरेड का कोट* इतना चर्चित हुआ कि उसकेबाद संजय की कोई रचना उनको वो प्रसिद्धि नहीं दिला पाई और फिर कालांतर में वो साहित्य की दुनिया से लगभग विस्मृत हो गए. इसी तरह से अगर हम देखें तो हिंदी के बड़े कवियों में से एक आलोक धन्वा का लेखन भी लगभग स्थगित है. आलोक धन्वा का अबतक एक ही कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है, हालांकि बाद में उन्होंने पत्र-पत्रिकाओं में छिट पुट कविताएं लिखी. एक आलोचक के मुताबिक आलोक धन्वा का लंबा मौन अपनी कविता को विकास के नए धरातल पर पहुंचाने की तैयारी थी. इसी तरह से अगर हम हिंदी की मशहूर उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा की कृतियों पर विचार करें, तो देखते हैं कि जो धार या जो पैनापन उनके लेखन में *इदन्नम* से लेकर *अल्मा कबूतरी* तक था या जिस तरह की रचनात्मक ऊंचाई उनकी आत्मकथा से *दो खंड- कस्तूरी कुंडल बसै और गुड़िया भीतर गुड़िया* में दिखाई दिए वह उसके बाद के लिखे उपन्यासों में नहीं मिलता है. मैत्रेयी पुष्पा के पहले लिखे गए उपन्यास उनके बाद के उपन्यासों के लिए अबतक चुनौती बनकर खड़े हैं. मेरा मानना है कि *अल्मा कबूतरी* उनकी अबतक प्रकाशित रचनाओं में सबसे श्रेष्ठ है. दरअसल, लेखकों की न लिख पाने की जो समस्या है वो विश्वव्यापी है. पश्चिम में इसे राइटर्स ब्लॉक कहते हैं. वहां यह माना जाता है कि किसी भी रचना पर सालों तक काम करते रहो, उसको लगातार संपादित करते रहो, उसमें जोड़ो घटाओ और जब संतुष्ट हो तो प्रकाशित करवाओ. यह सवाल भी पश्चिम में लगातार उठता रहा है कि कविता कहानी या उपन्यास लिखना शुरू करना आसान है, लेकिन लेखक को अपना लेखन कब रोक देना चाहिए यह बड़ा सवाल है. उस सवाल से अमेरिका के लेखक लगातार मुठभेड़ करते रहे हैं. अमेरिका के ही एक मशहूर लेखक थे राल्फ एलिसन जिनकी एक बेहतरीन कृति *द इनविजिबल मैन* 1952 में प्रकाशित होकर खूब चर्चित हुई थी. नस्लीय राष्ट्रवाद पर केंद्रित यह किताब जब प्रकाशित हुई थी तब अमेरिका के आलोचकों ने इसको मास्टरपीस करार दिया था. लेकिन इस उपन्यास के प्रकाशन के चालीस साल बाद तक राल्फ एलिसन अगली कृति को लिखने को लेकर संघर्ष करते रहे थे. इन चालीस वर्षों तक वो अपना एक उपन्यास *फनटीन्थ* लिखते रहे थे. उस दौरान अमेरिका में राल्फ एलिसन को लेकर मजाक भी होता था कि अनिश्चित काल तक यह उपन्यास लिखा जाएगा. अपनी मृत्यु तक राल्फ एलिसन ने अपने दूसरे उपन्यास को प्रकाशित नहीं करवाया क्योंकि वो इससे संतुष्ट नहीं थे. उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों ने उनके लिखे दो हजार पृष्ठ प्रकाशक को छापने के लिए दे दिए. प्रकाशक ने उसको संपादित करके पांच सौ पन्नों का उपन्यास बना दिया. राल्फ एलिसन का उपन्यास था, जिसके बारे में साहित्य जगत में यह चर्चा थी कि इसको चालीस साल से लिखा जा रहा है और उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी लिहाजा किताब को लेकर पाठकों और आलोचकों में उत्सुकता थी. किताब छपी, बिकी भी खूब लेकिन इसने पाठकों को भी निराश किया और आलोचकों ने तो विनम्रता के साथ इसको खारिज ही कर दिया. इसके बाद अमेरिका में इस बात को लेकर व्यापक चर्चा हुई थी कि आखिरकार राल्फ एलिसन इस किताब को क्यों नहीं छपवाना चाहते थे. राल्फ एलिसन के कुछ मित्रों ने उस वक्त यह बताया था कि वो इसके ड्राफ्ट से असंतुष्ट थे. यही हाल हिंदी में भी होता है. कई लेखक अपने जीवन काल में अपनी कुछ रचनाओं को नहीं छपवाते हैं लेकिन उनके मूर्ख वारिस चंद पैसों की लालच में उनकी कमजोर कृतियों को छपवाकर उनकी प्रतिष्ठा कम करते हैं. क्या ऐसी कुछ व्यवस्था बननी चाहिए कि जो लेखक अपनी किसी रचना को प्रकाशित नहीं करवाना चाहते हैं उसके बारे में वसीयत करके जाएं. इससे उनकी प्रतिष्ठा बची रह सकती है.

राइटर्स ब्लॉक का दूसरा उदाहरण है द न्यूयॉर्कर में काम करने वाले जोसेफ मिशेल का जो सालों तक दफ्तर जाते रहे, लेकिन कुछ लिख नहीं पाए. उनके बारे में कहा जाता है कि उनके दफ्तर से जाने के बाद उनके मित्र डस्टबिन खंगालते थे कि किस तरह का ड्राफ्ट फाड़ कर जोसेफ मिशेल ने फेंका है. दरअसल इस राइटर्स ब्लॉक से हर लेखक का सामना होता है जब उसके सामने रचनात्मकता का संकट उत्पन्न हो जाता है, लेकिन अपने को समीचीन बनाए रखने की ललक भी जोर मारती है. हिंदी के लेखक इस चुनौती को झेल नहीं पाते हैं और राइटर्स ब्लॉक पर खुद को रेलिवेंट बनाए रखने की ललक भारी पड़ जाती है और इसी ललक में कमजोर कृतियों का प्रकाशन कर अपनी प्रतिष्ठा को कम करते चले जाते हैं. रचनात्मकता के चुक जाने पर ई एम फोस्टर ने उचित ही कहा था कि वो सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं करते हैं और फिर शाम को बैठकर दिनभर के अपने कामों पर लिखना शुरू कर देते हैं. यह एक लेखक की पीड़ा है लेकिन राइटर्स ब्लॉक पर सटीक टिप्पणी भी है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

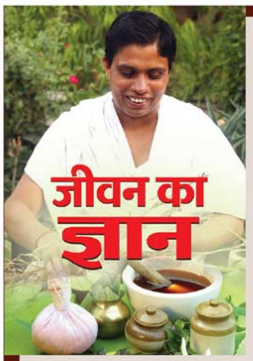

ईसबगोल

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

शिरो रोग :

❖ **शिर:शूल-** ईसबगोल को यूकेलिप्टस के पत्तों के साथ पीसकर मस्तक पर लेप करने से शिर:शूल का शमन होता है.

कर्ण रोग :

❖ **कर्णशूल-** ईसबगोल के 10 ग्राम लुआब में 10 मिली प्याज का रस मिलाकर गुनगुना करके 1-2 बूंद कान में डालने से कान की पीड़ा का शमन होता है.

मुख रोग :

❖ **मुखपाक-** ईसबगोल के लुआब से कुल्ला करने से मुखपाक में लाभ होता है.

❖ **दंतपीड़ा-** ईसबगोल को सिरके में भिगोकर, दांतों के नीचे दबाकर रखने से दंत पीड़ा का शमन होता है.

उदर रोग :

❖ **अतिसार-** 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी को दही के साथ दिन में 2-3 बार सेवन करने से जीर्ण आमातिसार तथा रक्तातिसार में लाभ होता है.

❖ ईसबगोल के बीजों को 1 लीटर पानी में उबालें, जब आधा पानी शेष रह जाए तो तीन खुराक बनाकर दिन में तीन बार देने से हर प्रकार की पेचिश, मरोड़, अतिसार इत्यादि में लाभ होता है.

❖ ईसबगोल के बीजों को पानी में डालकर जब उनका लुआब बन जाता है तब इस लुआब में शक्कर डालकर पीने से अमीबिक पेचिश, जीर्ण आमातिसार, अतिसार, पतले अतिसार, उदरशूल आदि में लाभ होता है. बालकों के चिरकालीन अतिसार में इसका प्रयोग बहुत लाभदायक है.

❖ ईसबगोल के साबुत बीजों को या 10 ग्राम ईसबगोल भूसी को ठंडे जल के साथ सेवन या उनको थोड़े जल में भिगोकर फूल जाने पर सेवन करने से आंत्रशूल तथा शोथ का शमन होता है.

❖ ईसबगोल के बीजों को भूनकर सेवन करने से भी अतिसार और आमातिसार का शमन होता है.

❖ 100 ग्राम ईसबगोल की भूसी में 50-50 ग्राम सौंफ और मिश्री मिलाकर 2-3 चम्मच की मात्रा में दिन में 2-3 बार सेवन करने से अमीबिक पेचिश में लाभ होता है.

वृक्कवस्ति रोग :

❖ **मूत्र-विकार-** चार चम्मच ईसबगोल भूसी को एक गिलास पानी में भिगो दें और थोड़ी देर बाद उसमें स्वादानुसार मिश्री डालकर पीने से मूत्रकृच्छ्र तथा मूत्रदाह का शमन होता है.

❖ एक ग्राम ईसबगोल की भूसी में 2 ग्राम शीतल मिर्च तथा 500 मिग्रा कलमी शोरा मिलाकर सेवन करने से शमन होता है.

कर्ण रोग :

❖ **कर्णशूल-** 1-2 बूंद जंगली ईसबगोल पत्र-स्वरस को कान में डालने से कर्णशूल का शमन होता है.

मुख रोग :

❖ **दन्तमूलशोथ-** जंगली ईसबगोल के पत्तों को पीसकर उसमें मक्खन मिलाकर दांतों पर मलने से दंतमूल शोथ का शमन होता है.

उदर रोग :

❖ **अतिसार-** 1-2 ग्राम जंगली अश्वगोल के बीज चूर्ण को सेवन करने से अतिसार तथा प्रवाहिका में लाभ होता है.

त्वचा रोग :

❖ **व्रण-** जंगली ईसबगोल के पत्रों को पीसकर व्रण पर लगाने से, व्रण से होने वाले रक्स्राव का स्तम्भन होता है तथा व्रण का शीघ्र रोपण होता है.

विष चिकित्सा :

❖ **कीटदंश-** अश्वगोल पत्र को पीसकर दंश स्थान पर लेप करने से कीटदंश-जन्य शोथ, दाह, वेदना आदि विषाक्त प्रभावों का शमन होता है.

विषाक्तता :

❖ जंगली ईसबगोल प्रत्यूर्जता, क्षोभक तथा त्वक् विकार उत्पन्न करता है. इसे अति-मात्रा में सेवन करने से अल्परक्तचाप तथा मृदु विरेचक प्रभाव उत्पन्न होते हैं. इसका प्रयोग गर्भावस्था तथा स्तन-पान कराने वाली स्त्रियों को नहीं करना चाहिए.

❖ ईसबगोल नाड़ी दौर्बल्यकारक एवं क्षुधानाशक है. यह औषधि प्रसूता के लिए हानिकारक है.

निवाण: *सिकंज बीज एवं शहद.*
प्रयोज्यांग : *बीज एवं फल की भूसी.*
मात्रा: *भूसी चूर्ण 5-10 ग्राम जल अथवा दुग्ध के साथ या चिकित्सक के परामर्शानुसार.* ■

❖ **कब्ज-** एक से दो चम्मच की मात्रा में ईसबगोल की भूसी को रात्रि में सोते समय गर्म दूध के साथ लेने से कब्ज दूर होती है.

❖ ईसबगोल की भूसी व त्रिफला चूर्ण को बराबर मात्रा में मिलाकर लगभग तीन से पांच ग्राम तक रात्रि में गुनगुने जल के साथ सेवन करने से सुबह मल साफ होता है. उदरशोथ व पित्त-कारकों में भी यह एक अनुभूत व निरापद प्रयोग है.

मूत्रकृच्छ्र में लाभ होता है.

अस्थिसंधि रोग :

❖ **गठिया-** जोड़ों के दर्द में ईसबगोल की पुस्टिस बांधने से लाभ होता है.

जंगली ईसबगोल

नेत्र रोग :

❖ **नेत्र-विकार-** जंगली ईसबगोल के पत्रों का क्वाथ बनाकर नेत्रों को धोने से दाह तथा कण्डु आदि नेत्र-विकारों का शमन होता है.

आचार्य बालकृष्ण

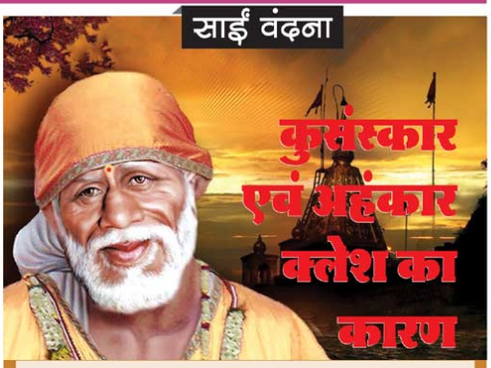

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

सद्गुरु की पूजा करके भी बहुत से लोगों के जीवन में क्लेश क्यों रहता है?

दरअसल उनके कुसंस्कारों, अपने अहंकार और प्रारब्ध का घोल इतना गाढ़ा होता है कि उनसे उनको मुक्त होने में कई जन्म लग सकते हैं. ऐसे में सद्गुरु के संकेतों को समझने की स्थिति ही कहां है? भीतर तो कुछ और घुला हुआ है. पहले अपने को इस लायक तो बनाएं कि गुरु-वचन को ठीक रूप से समझ पाएं. लोग उसको अपने अनुसार समझते हैं और अपनी चाहतों के अनुसार रंग देते हैं. अपने अच्छे आचरण से, अच्छे भावों से कुसंस्कारों की छाप को तो हल्का करें, धैर्य से अपने अहंकार को तो मिटाएं, सहकर प्रारब्ध के भोग को तो कम करें, तभी सद्गुरु के संकेत समझ आएंगे और उन संकेतों को समझ कर उन पर आचरण करने से जीवन में विसंगतियों से बचा जा सकेगा.

सुख-दु:ख के पीछे ईश्वरीय करुणा

सुख और दु:ख दोनों में हम गुरु की लीला को कैसे देखें?

मनुष्य असीम की करुणा-शक्ति को इतनी जल्दी नहीं समझ पाएगा. जैसे-जैसे वह सीमित अनुभवों से निकल कर असीम की ओर चलने लगेगा, उतना ही उसे उस असीम की करुणा-शक्ति के बारे में पता चलेगा. सर्वोच्च चेतना की समस्त लीला में, चाहे वह तात्कालिक रूप से सुख हो अथवा दु:ख हो- उन दोनों में वह उनके मंगलमय और करुणामय रूप को देखने लगेगा. जैसे कि श्रीरामकृष्ण परमहंस अपने जीवन की सबसे अधिक भयंकर और घोर कष्टप्रद स्थिति में भी श्री काली के रूप में करुणामयी माता का ही रूप सदा देखते रहे. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

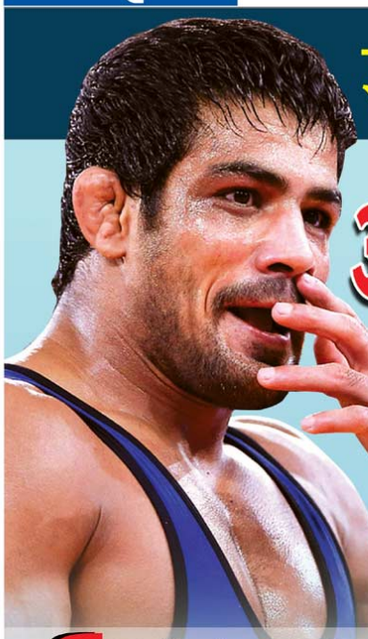

सुशील बनाम नरसिंह यादव

ओलंपिक से पहले दंगल

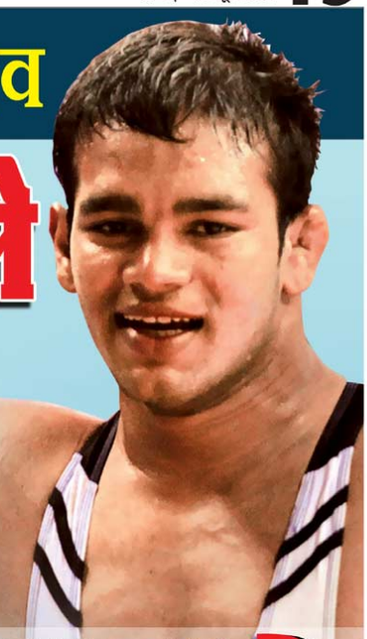

हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करे और देश के लिए पदक जीते. भारत में खेलों को लेकर लोगों की सोच में धीरे-धीरे बदलाव हो रहा है. इसलिए हर स्तर पर खिलाड़ी उभरकर सामने आ रहे हैं. भारत में खेलों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है. सुशील और नरसिंह के बीच का विवाद भी इसी प्रतिस्पर्धा का नतीजा है. विश्व चैंपियनशिप के पहले 74 किग्रा भार वर्ग के होने वाले ट्रायल मुकाबले पर हर किसी की नज़रें थीं. लेकिन चोट की वजह से सुशील ट्रायल्स में भाग नहीं ले सके और नरसिंह को लास वेगास जाने का मौका मिल गया. नरसिंह ने हाथ आए इस मौके को नहीं गंवाया और पहले ओलंपिक क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में ही ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया.

नवीन चौहान

ओलंपिक के आयोजन से पहले भारतीय खेल जगत में हलचल मचना एक तरह की रवायत हो गई है. लंदन ओलंपिक से पहले खिलाड़ियों के बीच के मतभेद देश हित पर भारी पड़े थे. विश्व स्तरीय टेनिस खिलाड़ियों की उपस्थिति के बावजूद लंदन में भारतीय दल टेनिस कोर्ट में अपनी छाप नहीं छोड़ सका था. लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना जैसे खिलाड़ियों के टीम में होते हुए भी भारतीय टेनिस दल लंदन से खाली हाथ लौटा था. इस बार कुछ ऐसी ही लड़ाई कुश्ती के अखाड़े में हो रही है. इस लड़ाई में एक तरफ दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार हैं तो दूसरी तरफ ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके नरसिंह पंचम यादव हैं.

सुशील लगातार तीसरी बार ओलंपिक पदक हासिल करने का सपना देख रहे हैं. लेकिन इस बार उन्होंने अपने भार वर्ग में बदलाव किया है. सुशील ने अबतक जितने भी अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं उन्होंने उनमें से अधिकांश 66 किग्रा भार वर्ग में जीते हैं. ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद सुशील दो साल तक मैदान से दूर रहे. इस दौरान उन्होंने अपने भार वर्ग में बदलाव के लिए तैयारी की. साल 2014 में इटली के सस्सारी में हुई प्रतियोगिता से उन्होंने वापसी की और 74 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया. इसके बाद साल 2014 में ग्लासगो में आयोजित 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में 74 किग्रा भार वर्ग में कुश्ती का स्वर्ण पदक हासिल किया. लंदन ओलंपिक के बाद उन्होंने केवल इन्हीं दो अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लिया और दोनों में ही पदक हासिल किया है, लेकिन बीजिंग और लंदन ओलंपिक के बीच उन्होंने 8 अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लिया था. कंधे की चोट की वजह से वह पिछले साल अमेरिका के लास वेगास में हुई विश्व चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सके थे, इसके पहले वह नए भार वर्ग के लिए तैयार होने और चोट से उबरने में व्यस्त थे. बीजिंग और लंदन ओलंपिक में क्रमशः कांस्य और रजत पदक जीतने के बाद विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर वह देश के सबसे सफल ओलंपिक एथलीट बनकर उभरे थे. उनकी खासियत यह है कि वह बड़ी स्पर्धाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं.

वहीं दूसरी तरफ 27 वर्षीय नरसिंह यादव ओलंपिक में पदक जीतने का सपना संजोए बैठे हैं. नरसिंह यादव 74 किग्रा वर्ग के एक्सपर्ट हैं वह लगातार 9 सालों से इस वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उन्होंने पिछले साल सितंबर में अमेरिका के लास वेगास शहर में हुई विश्व चैंपियन में 74 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया था. ओलंपिक को छोड़कर वह कुश्ती की अन्य सभी बड़ी प्रतियोगिताओं में पदक हासिल कर चुके हैं. फिलहाल वह अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ दौर से गुजर रहे हैं. पिछले दो सालों में उन्होंने विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में कांस्य पदक हासिल किया है. हालांकि लंदन ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया था लेकिन पदक नहीं जीत सके थे. लंदन ओलंपिक के बाद नरसिंह ने नौ अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया और इन सभी प्रतियोगिताओं में कम से कम सर्वोच्च पांच खिलाड़ियों में जगह बनाने में सफल रहे. वर्तमान में विश्व रैंकिंग में नरसिंह पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक मुकाबले में लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता क्यूबा के लोपेज एजक्वे को मात दी थी. हालांकि इससे पहले बड़ी प्रतियोगिताओं में वह दबाव में बिखरते रहे हैं. यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है, लेकिन पिछले दो सालों के अपने प्रदर्शन से उन्होंने इस कमी की भरपाई कर ली है. आम तौर पर नरसिंह चोटों से दूर रहे हैं. वह वर्तमान में देश के सबसे फिट पहलवानों में से एक हैं. साल 2007 से नरसिंह 74 किग्रा वर्ग में खेल रहे हैं उनके पास इस कैटेगरी में खेलने का ज्यादा अनुभव है.

फोटो-*सुनील मल्होत्रा*

हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करे और देश के लिए पदक जीते. भारत में खेलों को लेकर लोगों की सोच में धीरे-धीरे बदलाव हो रहा है. इसलिए हर स्तर पर खिलाड़ी उभरकर सामने आ रहे हैं. भारत में खेलों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है. सुशील और नरसिंह के बीच का विवाद भी इसी प्रतिस्पर्धा का नतीजा है. विश्व चैंपियनशिप के पहले 74 किग्रा भार वर्ग के होने वाले ट्रायल मुकाबले पर हर किसी की नज़रें थीं. लेकिन चोट की वजह से सुशील ट्रायल्स में भाग नहीं ले सके और नरसिंह को लास वेगास जाने का मौका मिल गया. नरसिंह ने हाथ आए इस मौके को नहीं गंवाया और पहले ओलंपिक क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में ही ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया.

32 वर्षीय सुशील अब फिट हैं और तीसरी बार ओलंपिक पदक जीतने के लिए आतुर हैं लेकिन वह जिस कैटेगरी में इस बार खेलना चाहते हैं उसके लिए नरसिंह क्वालीफाई कर चुके हैं. ओलंपिक में कुश्ती की 18 स्पर्धाओं में प्रत्येक देश से केवल एक-एक रेसलर भाग ले सकता है. सुशील और नरसिंह में से कौन भाग ले यह सवाल खड़ा हो गया. सुशील ने कहा कि कोटा देश के लिए होता है खिलाड़ी का नहीं. वह ओलंपिक के लिए ट्रायल करवाना चाहते थे. जब रेसलिंग फेडरेशन ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि जो खिलाड़ी कोटा लाया है वही ओलंपिक में भाग लेगा. रियो ओलंपिक में भाग लेने के अरमानों पर पानी फिरता देख सुशील ने खेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा. इस वजह से मामला और बड़ा हो गया. उन्होंने बार-बार यह बात कही कि वह सिर्फ ट्रायल चाहते हैं जो इसमें जीते वही ओलंपिक में जाए. वह चाहते हैं कि ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति करे. मामले को बढ़ता देख फेडरेशन ने खेल मंत्रालय के पाले में गेंद डाल दी, लेकिन तत्कालीन केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है. फेडरेशन स्वायत्त संस्था है और उसे चयन के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार है. हम राष्ट्रीय खेल संहिता का पालन करते हैं और सभी खेल संघों की स्वायत्ता का सम्मान करते हैं. सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी.

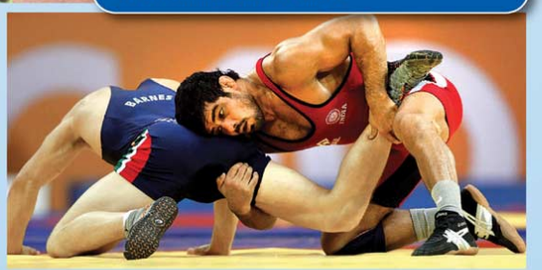

इसके बाद सुशील ने कोर्ट का रुख किया. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अंतिम निर्णय के लिए याचिका दायर की. याचिका दायर करने के मसले पर सुशील के कोच और ससुर सतपाल सिंह ने कहा कि उन्होंने इस विवाद के समाधान के लिए हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्हें मजबूरन कोर्ट जाना पड़ा. हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि ओलंपिक कोटा देश का होता है न कि खिलाड़ी का. ऐसे में ओलंपिक में भाग लेने के लिए ट्रायल होना ही चाहिए. याचिका में यह भी कहा गया है कि स्पोर्ट्स कोड के अनुसार प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा के लिए फेडरेशन को अलग-अलग ट्रायल आयोजित कराने चाहिए.

हालांकि रेसलिंग फेडरेशन का कहना है कि यदि आज सुशील और नरसिंह के बीच ट्रायल करवाया जाता है तो अन्य वर्गों के लिए भी ट्रायल करवाने की मांग उठेगी. फेडरेशन असमंजस की स्थिति में है. उसके लिए एक तरफ गड्ढा और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है. यदि सुशील ओलंपिक में नहीं जा पाते हैं तो देश के मेडल जीतने की आशाओं को बड़ा झटका लगेगा, वहीं दूसरी तरफ नरसिंह ओलंपिक में नहीं जाते हैं और सुशील पदक जीतने में असफल रहते हैं तो भी नुकसान देश का ही है. यदि अब तक 74 किग्रा वर्ग में नरसिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है तो उनसे अपेक्षा की जा सकती है कि वह बेहतर प्रदर्शन करेंगे और देश को मेडल जितवाएंगे. फेडरेशन के अध्यक्ष बृज भूषण शरन सिंह का कहना है कि 74 किग्रा वर्ग में सुशील कुमार की कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, इसलिए उन्हें ओलंपिक में भेजना घाटे का सौदा है. इसके अलावा सुशील चोट की वजह से काफी समय तक कुश्ती से दूर रहे हैं, इसलिए उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती.

इस तरह की स्थिति वर्ष 2004 में ग्रीस ओलंपिक के दौरान भी हुई थी. तब कृपा शंकर पटेल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे. जबकि योगेश्वर दत्त ने कोटा हासिल किया था. उस वक्त कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जिस खिलाड़ी ने कोटा हासिल किया है उसे ही ओलंपिक में जाना चाहिए यदि वह खिलाड़ी अनफिट है या फॉर्म में नहीं है उसी स्थिति में दूसरे खिलाड़ी को भेजा जाना चाहिए. यहां नरसिंह न ही अनफिट हैं और न ही आउट ऑफ फॉर्म हैं. विश्व के पूर्व नंबर एक ट्रैप शूटर रोंजन सोढ़ी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. 2008 में बीजिंग ओलंपिक के लिए टीम का चयन होना था. उस दौरान सोढ़ी विश्व रैंकिंग में दूसरे नंबर पर थे. उस दौरान उन्होंने 200 में 194 अंक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की थी. वहीं 2004 ओलंपिक के रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने साल 2006 में ही ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके थे, ओलंपिक से पहले उनके फॉर्म को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन शूटिंग फेडरेशन ने अंत में यह फैसला किया कि राठौर ने कोटा हासिल किया है इसलिए यही ओलंपिक में जाने के हक़दार हैं. लेकिन इसके बाद फेडरेशन ने अपनी सेलेक्शन की नीतियों में बदलाव किया. इसके बाद सेलेक्शन के लिए ट्रायल्स होने लगे.

सुशील की याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें फौरी राहत नहीं दी है. हालांकि कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करके उनका रुख पूछा है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि फेडरेशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुशील के कोच और अन्य अधिकारी साथ बैठकर कोर्ट को बताएं कि उनका पक्ष क्या है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेसलिंग फेडरेशन ने बताया कि नरसिंह यादव ने ओलंपिक के लिए सभी योग्यताएं हासिल कर ली हैं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि सुशील ने देश का गौरव बढ़ाया है लेकिन यदि फेडरेशन को तुरंत ट्रायल कराने को कहा जाएगा तो इससे गलत संदेश जाएगा और हर कोई अपना वजन बढ़ाएगा या घटाएगा. अदालत ने सुशील के वकील से पूछा है कि रेसलिंग फेडरेशन ने कौन से नियम तोड़े हैं और क्या गलत किया है. कोर्ट ने फेडरेशन को पांच दिन के अंदर सुशील को बुलाकर उनसे बात करने को कहा है. सुशील ने कोर्ट से कहा कि उन्होंने ओलंपिक के लिए काफी तैयारी की है. वह रियो ओलंपिक में जाने से पहले नरसिंह के साथ एक मुक़ाबला चाहते हैं. इसके जवाब में फेडरेशन ने कोर्ट से कहा कि सुशील कुमार ने दो से तीन बार नरसिंह यादव से किसी भी तरह के मुक़ाबले को टाला है. ओलंपिक के लिए नरसिंह 74 किग्रा भार वर्ग में सुशील से बेहतर रेसलर हैं. सुशील देश के लिए खेल चुके हैं नरसिंह को उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर चयनित किया गया है. फेडरेशन ने कोर्ट को यह भी बताया कि सुशील को सारी स्थिति और बातों की जानकारी है लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते. कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी.

कोर्ट के इस रुख से लगता है कि वह शायद ही रियो में भाग ले पाएं. सुशील ने भले ही ओलंपिक में दो बार पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है, लेकिन इस आधार पर वह किसी का हक़ नहीं मार सकते. हो सकता है कि वह नरसिंह रियो से स्वर्ण पदक जीतकर लौटें. क्योंकि उम्र के जिस दौर में आज सुशील हैं अगले ओलंपिक में नरसिंह भी उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे. जब सुशील ने रजत पदक जीता था तब वह 28 साल के थे आज नरसिंह 27 साल के हैं ऐसे में सुशील को सकारात्म रुख अपनाते हुए युवा खिलाड़ियों की मदद करनी चाहिए. हर कोई चाहता है कि खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए. सुशील देश के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलीट हैं और रहेंगे. उन्हें देश से बहुत प्यार और सम्मान मिला है, यदि वह इस विवाद को ज्यादा खींचेंगे तो लोग उन्हें स्वार्थी और अभिमानी कहेंगे. इसलिए नई पीढ़ी को मौका देकर उन्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, इसके अलावा देश के सभी खेल फेडरेशनों को इस मामले से सबक लेते हुए ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह का कोई विवाद पैदा न हो. जिससे खिलाड़ी अपना सारा ध्यान खेल में लगाएं न कि खेल से बाहर की गतिविधियों पर. इसी में खेलों, खिलाड़ियों और देश तीनों की भलाई है.■

navinonline2003@gmail.com

कोटा सिस्टम क्या है?

कोटा सिस्टम वह होता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी स्पर्धा में एक देश के कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं. इसका मतलब यह कि किसी भी खिलाड़ी की उस स्पर्धा में भाग लेना उसकी विश्व रैंकिंग पर निर्भर नहीं करता है बल्कि यह उसके देश की रैंकिंग पर निर्भर करता है. उदाहरण के लिए यदि किसी देश के तीन खिलाड़ी विश्व रैंकिंग में पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं और उसके पास केवल दो कोटा स्थान हैं तो देश के सभी खिलाड़ियों के बीच ट्रायल करवाकर दो ट्रायल के विजेता खिलाड़ियों को उस प्रतियोगिता में खेलने के लिए भेजा जाता है. ऐसे में दुनिया के अन्य खिलाड़ियों से बेहतर खिलाड़ी ओलंपिक जैसी प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित रह जाता है. ऐसे खिलाड़ी ओलंपिक में तभी भाग ले सकते हैं जब उन्हें उस खेल से संबंधित वैश्विक संस्था भाग लेने के लिए आमंत्रित करे या फिर किसी ओपन क्वालीफाईंग इवेंट को जरिए वे ओलंपिक या अन्य प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं.

सफल फिल्में देने के बावजूद सोनम कपूर के पास ज्यादा काम नहीं है

सोनम की राह कठिन

> नीरजा ने यह बात साबित की है कि सोनम बेहतरीन अभिनय करना जानती हैं. बहुत संघर्ष के बाद वह यहां तक पहुंची हैं, लिहाजा वे सोच-समझ कर फिल्में कर रही हैं.

इस वर्ष बहुत कम हिंदी फिल्मों को ही सफलता मिली. सफल फिल्मों में *नीरजा* का नाम भी है. नीरजा में बॉलीवुड का कोई बड़ा हीरो नहीं है. यह नायिका प्रधान फिल्म है जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भनोट का किरदार निभाया. सोनम ने बेहतरीन अभिनय कर फिल्म समीक्षकों की वाह-वाही लूटी. निःसंदेह कहा जा सकता है कि *नीरजा* साल की सुपरहिट फिल्म होने के साथ-साथ सोनम के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है. इससे पहले 2015 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म *प्रेम रतन धन पायो* में भी सोनम काम कर चुकी हैं. फिल्म सफल होने के बाद लगा था कि सोनम की डिमांड बढ़ जाएगी. उनके पास निर्माताओं की लाइन लग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. सफल फिल्में देने के बावजूद सोनम कपूर के पास ज्यादा काम नहीं है. उनकी बहन रिया ही सोनम को लेकर फिल्म प्लान कर रही हैं. यह सब देखकर तो ऐसा लग रहा कि सोनम कपूर की आगे की राह आसान नहीं है.

वैसे सोनम से जुड़े सूत्र इस बात से इंकार करते हैं. उनका कहना है कि सोनम को रोजाना फिल्मों के प्रस्ताव मिल रहे हैं, लेकिन वे ऐरी-गैरी फिल्म कर अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहतीं. *नीरजा* ने यह बात साबित की है कि सोनम बेहतरीन अभिनय करना जानती हैं. बहुत संघर्ष के बाद वह यहां तक पहुंची हैं, लिहाजा वे सोच-समझ कर फिल्में कर रही हैं. आने वाले दिनों में कुछ बेहतरीन फिल्मों में आप सोनम कपूर को देख सकते हैं.■

सैफ सीख रहे खाना बनाना

करीना कपूर हाल ही में अर्जुन कपूर के साथ फिल्म *की एंड का* में नज़र आईं. इस फिल्म में अर्जुन एक हाउस हस्बैंड के किरदार में थे, जो बहुत अच्छा खाना बनाता है. इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान अर्जुन ने करीना को ऑमलेट बना कर खिलाया था. तब करीना ने कहा था कि सैफ को तो कुछ भी बनाना नहीं आता. लेकिन शायद करीना को तब इस बात का पता नहीं था कि सैफ भी जल्द अपनी अगली फिल्म में शेफ बने नज़र आएंगे. सैफ अपनी अगली फिल्म *शेफ* में एक बावर्ची का किरदार निभाने जा रहे हैं. इसलिए आजकल उनका ज्यादातर समय किचन में ही बीत रहा है. फिल्म *शेफ* साल 2014 में आई अमेरिकन फिल्म *कॉमेडी ड्रामा* का रीमेक होगी. एयरलिफ्ट के निर्देशक राजा कृष्णा मेनन इस फिल्म के हिंदी वर्जन को निर्देशित करेंगे और सैफ अली खान इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे. राजा ने बताया कि इस फिल्म के लिए काफी तैयारी करने की जरूरत है. सैफ इसके लिए दो महीने की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं. दो जाने-माने शेफ उन्हें अपनी निगरानी में खाना बनाना सिखाएंगे. बताया जा रहा है कि अभी इस फिल्म के लिए किसी हीरोइन को साइन नहीं किया गया है. फिल्म की कहानी एक ऐसे शेफ की है जो लॉस एंजिलिस के मशहूर रेस्तरां में काम करता है. लेकिन अपने काम के साथ समझौता न करने के कारण वो नौकरी छोड़ देता है. इसके बाद वो अपने दोस्त और बेटे के साथ मिलकर एक फुड ट्रक की शूरुआत करता है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

क्यों उदास हुई दीपिका

दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी डेब्यू हॉलीवुड फिल्म *ट्रिपल एक्स: द रिटर्न ऑफ जैंडर कैज* की शूटिंग में व्यस्त हैं. इस दौरान दीपिका की अपने को-स्टार्स के साथ अच्छी दोस्ती हो गई. हाल ही में दीपिका की को-स्टार्स नीना डोब्रेव ने अपनी शूटिंग खत्म कीं. हॉलीवुड एक्ट्रेस नीना डोब्रेव ने अपनी *ट्रिपल एक्स: द रिटर्न ऑफ जेंडर केज* की को-एक्ट्रेस और बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण के साथ सेल्फी शेयर की, जिसमें दोनों काफी उदास नजर आ रही हैं. 27 साल की एक्ट्रेस नीना ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि वह फिल्म के सेट पर कई खूबसूरत लोगों से मिलकर काफी खुश हैं और आखिरी दिन इस उत्साहित सफर के साथ खत्म होने से दुखी हूं. इस सेल्फी के साथ नीना ने लिखा कि फिल्म के बेहतरीन और मेहनती लोगों के ग्रुप को मैं बहुत याद करूंगी. *ट्रिपल एक्स: द रिटर्न ऑफ जैंडर कैज* में नीना ने बेकी का किरदार निभाया है, जो बहुत पढ़ाकू लड़की है. वह तकनीक की मास्टर है. वहीं दीपिका फिल्म में सेरेना अंगर के किरदार में नज़र आएंगी. ट्रिपल एक्स सीरीज की यह तीसरी फिल्म है, जो 2017 में रिलीज़ होगी. फिल्म के हीरो विन डीजल हैं. दीपिका के फैन इस फिल्म की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.■

फ्लैशबैक

दिव्या भारती
अनसुलझी मौत की कहानी

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी, 1974 को मुंबई में हुआ था. लेकिन उनकी मौत एक हादसे में 5 अप्रैल, 1993 को महज 19 वर्ष की आयु में हो गई. उनकी मौत आज भी एक पहेली बनी हुई है. दिव्या भारती ने अपने समय में कई हिट फिल्में दी थीं. उन्होंने जितनी फिल्मों में भी काम किया, उनमें ज्यादातर फिल्में हिट रहीं.

मात्र सोलह साल की उम्र में दिव्या ने वेंकटेश के साथ सफल तेलुगु फिल्म *बोबिला राजा* की. दिव्या भारती ने तेलुगु फिल्मों से अपना करियर शुरू किया और 1992 में हिंदी फिल्मों में प्रवेश किया. *विश्वात्मा* उनकी पहली हिंदी फिल्म थी. दक्षिण की सफलताओं पर सवार दिव्या को मुंबई के फिल्म निर्माताओं ने घेर लिया.

अपने तीन साल के करियर के दौरान उन्होंने कई सफल फिल्में दीं. साल 1992 में तो दिव्या ने रिकॉर्ड 12 फिल्मों में काम किया. दिव्या के इस रिकॉर्ड को अभी तक किसी भी एक्ट्रेस नहीं तोड़ा है. दिव्या की इन 12 फिल्मों में 10 हिंदी और 2 तेलुगु फिल्में थीं. दिव्या की फिल्में *विश्वात्मा, शोला और शबनम, दिल आशना है और दीवाना* उनकी हिट फिल्मों में शामिल हैं.

5 अप्रैल 1993 को रात 11 बजे मुंबई में वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5 वें फ्लोर से गिरकर दिव्या भारती की मौत हो गई थी. दिव्या भारती ने खुदकुशी की थी या फिर उनका मर्डर हुआ. इस पर से मुंबई पुलिस अभी तक परदा नहीं उठा पाई है, क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं थे. माना जाता है कि दिव्या भारती बहुत खुशकिस्मत थी, वो जिस फिल्म को भी साइन करतीं, वो सुपर हिट हो जाती थी. कामयाबी की बुलंदी छूने के बाद दिव्या भारती ने अपने करियर के चरम पर ही साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली, लेकिन यह शादी उनके लिए बर्बादी साबित हुई. शादी के कुछ महीनों बाद उनकी रहस्यमयी मौत हो गई.

दिव्या भारती की कई निर्देशकों के साथ काम करने की ख्वाहिश थी लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी. उन्हीं में से एक थी निर्देशक राज कनवार की फिल्म लाडला जिसे बाद में श्रीदेवी के साथ बनाया गया. ■

बैंगनी लिपस्टिक में ऐश्वर्या ने
जलवा बिखेरा

ऐश्वर्या कान्स फिल्म समारोह में अपनी फिल्म सरबजीत की स्क्रीनिंग के मौके पर मौजूद थीं.

कान्स फिल्म समारोह में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी फिल्म सरबजीत की स्क्रीनिंग के मौके पर रेड कार्पेट पर होठों पर बैंगनी लिपस्टिक लगाए नज़र आईं. ऐश्वर्या डिजाइनर रामी कदी के हल्के गुलाबी रंग के डिजाइनर परिधान में बेहद आकर्षक नज़र आ रही थीं.

ऐश्वर्या समारोह में कॉस्मेटिक ब्रांड लॉरियल पेरिस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. ऐश्वर्या कान्स फिल्म समारोह में अपनी आगामी फिल्म सरबजीत की स्क्रीनिंग के मौके पर मौजूद थीं. उनके साथ फिल्म के निर्देशक उमंग कुमार, अभिनेत्री ऋचा चड्ढा और निर्माता जैकी भगनानी भी थे.■